SHRI NARESH AGRAWAL: For one minute or for two minutes!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Don't think like that.

SHRI NARESH AGRAWAL: I know, Sir. आपकी घंटी इतनी खतरनाक है कि आप एक और दो मिनट में मेंबर को बाध्य कर देते हैं ।

**श्री उपसभापति** : मैं खतरनाक हूं या घंटी खतरनाक है?

**एक सम्मानित सदस्य** : आप नहीं, घंटी है । ...(**व्यवधान**)...

**श्री भूपिंदर सिंह** : आप बहुत अच्छे हैं । ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. We will take more time. Okay. Mr. Minister, instead of two-and-a-half hours, let us take three or four hours! What is the problem?

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : सर, हम मूल रूप से सहमत हैं । ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think you have no objection. So, instead of two-and-a-half hours, the discussion is for four hours. The time will be allotted accordingly. The House is supreme; the House has decided. Fine. ...(*Interruptions*)... the House is supreme; the Chair goes by the House.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, you seem to have had a good lunch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why the change of mood.

SHRI SITARAM YECHURY: Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Anand Sharma.

---

## SHORT DURATION DISCUSSION

### Prevailing agrarian crisis in the country

**श्री आनन्द शर्मा** (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन के माध्यम से सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान एक ऐसी ज्वलंत समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिस पर अभी तक सरकार की कोई निगाह नहीं पड़ी । भारत एक कृषि प्रधान देश है । जैसा अभी कहा गया, देश के 65 प्रतिशत नागरिक आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं । जहां तक जमीन का सवाल है, किसानों के परिवारों के पास जो जमीन है, लैंड होल्डिंग्स हैं, समय के साथ-साथ वह कम होती जा रही हैं । जो उपजाऊ जमीनें थीं, उनमें से काफी उपजाऊ जमीनें हमारे विकास के लिए, सड़कें बनाने के लिए, दूसरी संस्थानों को बनाने के लिए भारी मात्रा में डायवर्ट हुई हैं । जिन जमीनों का उपयोग

कृषि के लिए था, उससे हटकर दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में उसका उपयोग हुआ। पूरे देश के अंदर हमारे किसानों की जमीनें विकास के लिए गई हैं। यह सही बात है कि जहां विकास होता है, वहां जमीनों की जरूरत पड़ती है। उसके साथ-साथ एक नीति बननी चाहिए और वह नीति ऐसी बने, जिससे किसान भी सुरक्षित रहे और देश में खाद्यान्न की उपलब्धि की कभी समस्या न हो। इसके लिए किसानों के हित की रक्षा करना, किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलना और कभी भी उन पर कोई संकट आए, कोई आपदा आए, उनकी फसल खराब हो या कीमत टूटे, तो उसके लिए तुरन्त शासन को, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।

उपसभापति जी, खाद्यान्न के उत्पादन में भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है। भारत में पिछले साल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 25 करोड़ टन, यानी 250 मिलियन टन हुआ। इसमें गेहूं का, चावल का, मक्के का, दाल का उत्पादन हुआ और अगर इसमें कपास को बाहर रखते हुए खाने के तेल को जोड़ लें, तो हमारे भारत का उत्पादन कुल मिलाकर 341-342 मिलियन टन हुआ है। इसमें चावल का उत्पादन 110 मिलियन टन के आसपास है, गेहूं का 93 मिलियन टन के आसपास है और उसी तरह मक्के का है, और चीजों का है। कुछ दालों की कमी है, कुछ दालें भारत के अंदर पर्यात मात्रा में हैं, जिनका निर्यात होता है, बाकी कई दालें ऐसी हैं, जिनका हमें आयात करना पड़ता है। इसी तरह खाने के तेल की कमी होने के कारण उसका आयात करना पड़ता है, कम से कम 8 से 9 मिलियन टन खाने के तेल का इम्पोर्ट भारत करता है, आयात करता है। देश में किसान को प्रोत्साहित करने के लिए कि किसान अपनी उपज बढ़ाए, खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाए, उसके लिए और दूसरे उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर एमएसपी देती है। सरकार उस पर हर वर्ष पुनर्विचार करती है, उसका रिव्यू करती है, उसको बढ़ाती है। पिछले दस सालों में किसानों की समस्याओं को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए निरंतर उत्पादन बढ़ा है। साथ ही साथ एमएसपी भी बढ़ा है। आज चिंता है गिरती हुई कीमतों की। वे कीमतें ऐसी नहीं गिरीं जिससे उपभोक्ता को कोई फायदा हो, कोई लाभ हो। इन कीमतों के गिरने का सीधा असर किसान पर पड़ता है, किसान के परिवार पर पड़ता है। देश के बाज़ार के अंदर कपास की कीमत टूट गई है। जो कपास दो साल पहले 5800 रुपए और 6200 रुपए में मिलता था, जो छोटे स्टेपल का कपास होता है या लांग स्टेपल का कपास होता है, आज कई राज्यों के अंदर उसका दाम गिरकर 3700 रुपए तक चला गया है। भारत के अंदर जो कपास का उत्पादन है, यह पिछले साल 330 लाख बेल्स था। इस साल कपास का उत्पादन जो संभावित है, वह 400 लाख बेल्स है। पिछले साल जब संकट आया था किसानों पर, तब एक बेल का एमएसपी पिछली सरकार ने 3400 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए किया था, 300 रुपए बढ़ाया था और बड़े पैमाने पर कॉटन कारपोरेशन के द्वारा एमएसपी के ऑपरेशन्स जारी किए गए, ताकि किसान को नुकसान न हो। खास तौर पर जिन राज्यों के अंदर नुकसान हुआ था, जैसे उस समय आंध्र प्रदेश में नुकसान हुआ था, वहां कॉटन कारपोरेशन ने एमएसपी ऑपरेशन्स शुरू किए, प्रोक्योरमेंट शुरू किया। आज कीमत टूटी है। मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि जब पहले कपास की कीमत टूटी थी, तो उस समय एक आंदोलन हुआ था। दो साल पहले गुजरात राज्य के अंदर, उस आंदोलन का नेतृत्व करने सड़कों पर गुजरात के उस समय के मुख्य मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी स्वयं निकले थे। मैं उस समय भारत सरकार का कपड़ा मंत्री भी था और वाणिज्य मंत्री भी था। हमने उस समय सोच-समझकर एक निर्णय किया कि किसान से सीधा खरीदा जाए और एक्सपोर्ट का रास्ता भी खोला जाए, ताकि किसान को अगर देश के बाज़ार में उसकी कीमत नहीं मिलती, तो बाहर के बाज़ार में वह सही

[श्री आनन्द शर्मा]

कीमत पा सके। उससे उसको राहत मिली। आज क्या हालत है? आज बाहर के बाज़ार में भी मांग टूट गई है। चीन ने अपनी नीति बदल ली है। माननीय उपसभापति महोदय, पिछले साल 117 लाख बेल्स भारत से एक्सपोर्ट हुई थीं, कीमत अच्छी थी। इस बार उत्पादन बढ़ा है, फसल बढ़ी है, पर क्योंकि चीन के पास कपास के पर्याप्त भंडार थे, तो चीन ने इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, आयात करना बंद कर दिया और चीन ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया के बाज़ार में कॉटन की कीमत टूट गई, तो आज हमारा किसान बाहर भेजना भी चाहे, चाहे कोई पाबंदी नहीं है एक्सपोर्ट पर, पर उसकी मांग कहां है? उसकी कीमत कहां मिलेगी? देश के बाज़ार में कोशिश हो रही थी कि कपड़ा मिलों में मांग बढ़े। टेक्सटाइल सेक्टर जो कृषि के बाद दूसरा नंबर रखता है, जिसमें लोगों को रोज़गार मिलता है, तो भारी संकट उस पर भी आया था। वह संकट कीमतों के कारण, फसल खराब होने के कारण, दुनिया के बाज़ार में मांग कम होने के कारण हुआ। तब 25 हजार करोड़ की textile sector की restructuring की गयी। हमारे देश के आज के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी उस समय वित्त मंत्री थे। सरकार ने यह सोचकर निर्णय लिया कि इस पूरे सेक्टर को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए यह आवश्यक है और रिज़र्व बैंक से बात करके, एक समिति बनाकर यह फैसला लिया गया। मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं। इतना बड़ा संकट है, सैकड़ों किसान पिछले तीन सप्ताह के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। ये आत्महत्याएं महाराष्ट्र में की गयीं, आंध्र प्रदेश में की गयीं, तेलंगाना में की गयीं और ये आत्महत्याएं प्रधान मंत्री के अपने राज्य गुजरात में भी की गयीं। इतना बड़ा संकट आने के बाद, जब फसल बढ़ गयी, कीमत टूट गयी, आधी पर आ गयी, इस सरकार ने, पिछले साल जो 300 रुपए एमएसपी बढ़ा था, इस साल क्या फैसला किया - पचास रुपए बढ़ाया। सिर्फ पचास रुपए ! 3700 से बढ़ाकर उसे 3750 रुपए किया गया। कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी तक जो खरीद की है, वह पिछले साल की तुलना में नगण्य है। यह सही बात है कि कपास की फसल अक्तूबर महीने से आती है।

**श्री भूपिंदर सिंह** (ओडिशा) : 4050 है।

**श्री आनन्द शर्मा** : 4050 लांग स्टेपल का है। 4000 पिछली बार था, जो लांग स्टेपल कपास का था और 3700 रुपए एमएसपी शॉर्ट स्टेपल कपास का था। दोनों में पचास-पचास रुपए बढ़े हैं और 3750 तथा 4050 रुपए कर दिए गए हैं। यह एक वास्तविकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर के रिवाइवल के बाद, उसको पुनर्जीवित करने के बाद हमारे देश में कपड़ा मिलों के अंदर मांग बढ़ी है और खपत बढ़ेगी, लगभग 311 लाख बेल्स की देश में खपत हो जाएगी, लेकिन जो प्रोजेक्शन है, जो संभावना दिखाई जाती है - एक्सपोट्र्स की, निर्यात की - कि 90 लाख बेल्स का निर्यात होगा, वह संभव नहीं है। इसका जिक्र मैंने किया, मैंने कारण भी बताए। मेरा इस सरकार से सीधा प्रश्न है कि क्या आपके अंदर किसान के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है? आज प्रतिपक्ष को मजबूर होकर, सरकार को जगाने के लिए हम यह चर्चा का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप, जो देश की जनता से, किसान से, गरीब से बड़े वायदे करके, बड़े आश्वासन देकर आए थे, आज किसान को, उसके कष्ट को देखते हुए आपने क्या कदम उठाए हैं, यह हम जानना चाहते हैं? आपको ज्यादा चिंता रहती है, बड़े कारबारियों के, बड़े बिज़नेस के फायदे की, कि जल्दी कानून बने और जो बने हुए हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्हें हटाया जाए। जो देश के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वे अभी एनपीएज़ से दबे हुए हैं। जो कर्ज़ वापस नहीं आ रहे और जो कारोबार कमज़ोर हो गए हैं,

उन्हीं बैंकों को मज़बूर करके, बड़े कारोबार, बड़े बिज़नेस को और कर्ज़ा देने की बात की जाती है और किसान के कर्ज़े के लिए आपने क्या फैसला किया? 7 प्रतिशत ब्याज पर किसान को कर्ज़ा मिलेगा, यह आपका फैसला है, शायद कल या परसों का है । आप उसको सुधारें, ब्याज को कम करें और किसान को राहत दें । यूपीए की सरकार ने उनका 72,000 करोड़ का कर्ज़ा माफ किया था । मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि हमने किस तरह से वह काम किया - चाहे उसमें और भी जरूरत हो, लेकिन मैं यह चीज़ जरूर कहूंगा कि उससे किसान को राहत मिली । जहां तक गेहूं की बात, चावल की बात है, भाई दिग्विजय सिंह जी इस पर बोलेंगे और हमारे अन्य साथी भी बोलेंगे, मैं हर विषय पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर आप देखें तो 2006-07 में चावल का एमएसपी 570 रुपए था, जो 2013 में बढ़ाकर 1310 रुपए कर दिया गया था । आपने उसमें पचास रुपए बढ़ाए । आपने उसमें 50 रुपया बढ़ाया है । जो ग्रेड "ए" के चावल का एमएसपी 600 रुपये था, उसको बढ़ाकर कर्मवार 1345 रुपये किया गया, आज उसे आपने 1400 रुपये किया है । अगर आप गेहूं को देखें, तो 700 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये हुआ, यूपीए सरकार के शासन काल में दुगना हुआ । जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और उसके लिए भी कहीं न कहीं आपको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए कि अर्थ-व्यवस्था का संचालन अच्छा था और अच्छे हालात में economy आपकी सरकार को मिली । देश के अच्छे दिन अभी इंतजार में हैं । किसान के अच्छे दिन नहीं आए, उसके बुरे दिन आ गए । प्रधान मंत्री जी की सरकार के सितारे अच्छे हैं, ये आपकी वजह से नहीं हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत टूट गई, उसका श्रेय भी आप स्वयं ले लें, तो यह हास्यप्रद बात है । ऑयल की 44-45 डालर कीमत टूटी है । ...**(व्यवधान)**... आप बीच में टीका-टिप्पणी न करें, कुछ अध्ययन कर लें । शायद आपको नहीं मालूम कि 2008-09 के बाद पेट्रोल की, डीजल की कीमत दुनिया के बाजार में नहीं टूटी थी, जब यूपीए सरकार ने कार्यभार सम्भाला था, जब एनडीए सरकार सत्ता में थी, ये अंतर्राष्ट्रीय दाम हैं, ये न आपके हाथ में हैं, न मेरे हाथ में हैं । जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब 27 डालर, 28 डालर प्रति बैरल था इंडियन बास्केट, का brent crude था, वह बढ़कर 128 डालर तक गई, मई महीने में 112 डालर थी और आज 62-63 डालर पर तेल आ गया है । आपके पास पैसा है, कम से कम 28 बिलियन डालर की बचत होगी, फिर भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? आप किसान को पैसा नहीं दे रहे हैं, एमएसपी बढ़ा नहीं रहे हैं । किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

उपसभापति महोदय, भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, अगर हमारा किसान पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन न करे, तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, जो इतना खाद्यान्न पैदा कर सके और हिन्दुस्तान को खिला सके । यह हमको खुद करना है । हम आयात पर निर्भर नहीं रह सकते । आज कीमत बढ़ी है, इनपुट कास्ट बढ़ी है, खाद की कीमतें बढ़ी हैं । सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता चिंताजनक है । ग्राउंड वाटर रिजर्व बहुत कम हो गए हैं । बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं । बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है । आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल्स की कीमतें टूटने के बाद राहत देने के बजाय एक महीने में दो बार आपने सेस लगा दिया, एक्साइज़ ड्यूटी डीजल पर बढ़ा दी है । इसका सीधा असर किसान पर होता है, इन्फ्लेशन पर होता है, महंगाई पर होता है, आम आदमी पर होता है । इसी से जुड़ी हुई बात प्रोक्योरमेंट की है । फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया चावल खरीदता है, दाल खरीदता है, गेहूं खरीदता है । चावल, गेहूं, मक्का और खाने का तेल मुख्य है । अब आप चावल की बात देखें, भारत में चावल का पर्याप्त उत्पादन है, पर्याप्त भंडार

[श्री आनन्द शर्मा]

है । हमारी सरकार ने चावल को एक्सपोर्ट किया और 10 मिलियन टन से ज्यादा चावल एक्सपोर्ट हुआ । वह भारत से बाहर गया, किसान को फायदा हुआ, उसे अच्छी कीमत मिली । दुनिया के बाजार में चावल की कीमत भी टूट गई है । इस बार पिछले साल की तुलना में एक-तिहाई चावल का एक्सपोर्ट होगा । गेहूं का निर्यात हो रहा था, इस साल गेहूं का निर्यात नहीं हो पाएगा, यह एक वास्तविकता है । यह कड़वा सच है । इस सब घटनाक्रम का सीधा प्रभाव भारत के किसान पर पड़ रहा है । आपको इस पर सोचना चाहिए । यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है । आप उनको राहत दें, आप उनका MSP बढ़ाएं, आप कॉटन कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन को हिदायत दें, लेकिन आपने वह नहीं किया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है । माननीय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं । आप एक ऐसे राज्य से आते हैं, जिसका कृषि में एक विशेष योगदान रहता है । यह सोचना चाहिए, यह राजनीति का विषय नहीं है । आपकी प्रतिपक्ष में रहते हुए सोच अलग थी । आज हालात अच्छे होते हुए, आर्थिक हालत अच्छी होते हुए, आपके पास पर्याप्त साधन हैं, आप साधन सम्पन्न हैं, अगर वे साधन देश के किसान के पास नहीं जाएंगे, देश के गरीब के पास नहीं जाएंगे, तो फिर किसके लिए हैं ?

महोदय, अपनी बात को विराम देने से पहले, मुझे एक बात और कहनी है । आपने प्रोक्योरमेंट क्यों कम की? हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए सब्सिडाइज करके गरीब लोगों के लिए जो खाद्यान्न देते हैं, खाने का तेल देते हैं, इस देश में बड़ी संख्या में लोग हैं, जिनको आज भी सब्सिडी देते हैं, जो कम कीमत पर खाद्यान्न हैं, वह देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को उपलब्ध कराने हैं । आपने उसमें क्या किया? जब मैंने मालूमात की तो पता चला कि इस साल प्रोक्योरमेंट 30 प्रतिशत घटा दिया गया है । आज किसान की यह हालत है कि आपने प्रोक्योरमेंट घटा दिया और एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, कीमत टूट गई, आत्महत्याएं हो रही हैं । यहां पर खेल-तमाशा हो रहा है । आपकी सोच क्या है? इस बारे में यह सदन ही नहीं, बल्कि देश भी जानना चाहता है । आज क्या आवश्यकता पड़ी कि हम आग्रह करें, हम इस बात को उठाएं, क्या आपका कोई फर्ज नहीं था कि इतना बड़ा संकट आ गया है, त्राहि-त्राहि मची है । मैंने एक बयान नहीं सुना, एक टिप्पणी नहीं सुनी । आपको बधाई हो कि आप महाराष्ट्र भी जीतकर आए हैं, सैकड़ों आत्महत्याएं हुई हैं । आप मालूमात करें और सदन को जानकारी दें । ...(**व्यवधान**)...

**श्री नंद कुमार साय** (छत्तीसगढ़): दोषी तो आप भी हैं ।

**श्री आनन्द शर्मा** : आप चुप रहिए और टीका-टिप्पणी मत करिए । आपकी पार्टी समय देगी, आप उठकर बोल लीजिए । मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं । ...(**व्यवधान**)... हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप लोग सदन की मर्यादा को देखें और टीका-टिप्पणी न करें ।

**श्री मनसुख एल. मांडविया** (गुजरात): हम आपकी भी और सदन की भी मर्यादा रखेंगे ।

**श्री आनन्द शर्मा** : उपसभापति महोदय, कई सदस्य नए आए हैं और कुछ इनको सत्ता का नशा है । इनको सदन की मर्यादा को समझने में अभी समय लगेगा । सत्ताधारी दल की क्या जिम्मेदारी है, वह भी समझना जरूरी है । मैं बुनियादी बात कर रहा हूं । यह अच्छे दिन का वायदा न मैंने किया था और न ही मेरे दल ने किया था, तो जिन्होंने किया है, उन्हीं की जवाबदेही बनती है । हिन्दुस्तान के लोग जवाब आप से मांगेंगे । आज देश में क्या हो रहा है, जवाबदेही आपकी है, जवाबदेही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की है, जवाबदेही विपक्ष की नहीं बनती है । हमारे के.सी. त्यागी

भाई बता रहे थे, आपने कह दिया कि बोनस मत दो और खुद प्रोक्योरमेंट खत्म कर दो, 30 परसेंट कम कर दो, FCI को निर्देश दे दो और राज्यों से कहो कि आप बोनस भी मत दो । आपने यह अच्छी किसान प्रेमी नीति बनाई है ।

उपसभापति महोदय, अंत में मेरा यही कहना है । वैसे कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह इसमें विशेष रुचि रखते हैं, जब वे हमारे दल की तरफ से बोलेंगे तो इस पर विस्तार से बोलेंगे । यह सरकार जागे और जहां पूरे सदन की एक जिम्मेदारी बनती है, कर्त्तव्य बनता है, देश के किसान के प्रति, देश के गरीब लोगों के प्रति कि किसान जो उत्पादन करता है और वह गरीब, जिसको पब्लिक ड्रिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से, PDS से खाना पहुंचाया जाता है, उन दोनों के हित सुरक्षित होंगे । इसके लिए सरकार MSP बढ़ाए, सरकार कर्जे का सूद माफ करे । हमने तो कर्जा माफ किया है, आप ब्याज तो माफ कर दीजिए । इस भारत के किसान का चाहे वह कपास उगाता है, चाहे वह चावल उगाता है, मूंगफली का तेल उगाता है, खाने के तेल पैदा करता है, गन्ना उगाता है, आप उसका इस साल का सारा ब्याज माफ करिए । गन्ने की समस्या अलग है । इस पर हमारे यूपी के भाई बोलेंगे । मैं आपको खाद्यान्न के तेल के बारे में और कहना चाहूंगा ।

हमको आठ, नौ मिलियन टन मंगाना पड़ता है, जिसके लिए हम अपने किसान को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके कहते हैं कि आप पैदा कीजिए । आज इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको खत्म कर दिया है, जिससे पाम ऑयल की कीमतें 35 प्रतिशत टूट गई हैं । आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि उससे देश में खाने के तेल की जो कीमतें हैं, वे टूटी हैं । लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें, तो इन सब चीज़ों का, कीमतें टूटने का लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंच रहा है । इससे न किसान को राहत मिलती है, न उपभोक्ता को, इसलिए यह एक चिंता का विषय है और हम यह उम्मीद करते हैं कि जब कृषि मंत्री जी अपना जवाब देंगे तो देश को आश्वस्त करेंगे । लेकिन आश्वस्त शब्दों में नहीं करें, क्योंकि शब्द तो हम रोज सुनते हैं । हमने इतनी बड़ी बातें सुनी हैं, हम रोज सुबह उठकर सोचते हैं कि शायद भारत का कायाकल्प हो गया है, टेलीविजन खोलते हैं, तब भी वही दिखता है, लेकिन यह ध्येय शब्दों से पूरा नहीं होगा, यह तो काम करने से होगा, धन्यवाद ।

**श्री राम नारायण डूडी** (राजस्थान) : उपसभापति जी, आज सदन के अंदर किसान और किसान की समस्या को लेकर बहस हो रही है । इस देश के अंदर किसान के हालात कैसे सुधरेंगे, इस बाबत जो विचार आएंगे, मैं अपने विचार उनसे सम्मिलित करता हूं । महोदय, मैं एक बहुत ही साधारण और ऐसे किसान परिवार से आता हूं, जिसका एक संयुक्त परिवार के रूप में धंधा केवल मात्र खेती पर निर्भर है । हम यह चीज़ देखते हैं कि देश की आबादी का 75 परसेंट हिस्सा किसान वर्ग का है और 25 परसेंट हिस्सा अन्य काम करने वाले लोगों का है । जब हम इन बातों की ओर ध्यान देते हैं कि 6 लाख गांव कृषि प्रधान हैं, तब ऐसे हालात में हमारे सामने किसान, किसान की समस्या, किसान की आमदनी, किसान का रहवास, किसान के बच्चे की पढ़ाई की बातें आती हैं ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर)** *पीठासीन हुए*]

अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि देश के अंदर आत्महत्याएं हो रही हैं । यदि इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाए, तो आज़ादी के 67 साल के बाद भी यही सच है । जब देश आज़ाद हुआ, तो इस आज़ादी की लड़ाई में, देश को आज़ाद करने में सबसे अहम भूमिका इस देश

[श्री राम नारायण डूडी]

के किसान की भी रही । वह किसान उस गुलामी के वक्त में बेगार, याचना, साहूकारों के चंगुल से मुक्ति पाने के संदर्भ में सोचता था कि जब देश आजाद होगा, तो मैं एक स्वावलंबी किसान बनूंगा । जिस प्रकार से एक उद्योगपति, एक सेठ-साहूकार और जो अन्य काम करने वाले लोग अपना जीवन यापन करते हैं, मैं भी उसी प्रकार का जीवन-यापन करूंगा । मगर दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी के 67 साल के बाद भी किसानों की स्थिति आज ठीक नहीं है । इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे कर्णधार थे, उन्होंने इनका ध्यान नहीं रखा । यदि वे किसानों के मामले में नीतिगत निर्णय लेते, यदि उनकी दशा को देखते हुए वे उनका ध्यान रखते, तो मैं समझता हूँ कि आज जो देखने में आ रहा है, वह नहीं आता । आजादी के बाद आज अगर हम केवल विगत 17 साल के आँकड़ों को देखें, तो इस देश के अन्दर 3 लाख लोगों ने आत्महत्या की है । पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे प्रदेशों के अन्दर लोगों ने आत्महत्या की है । यदि हम इसका कारण ढूँढ़ना चाहें, तो मैं एक ही बात समझता हूँ कि 60 साल राज करने वाली पार्टी ने किसानों की ओर कम ध्यान दिया । हो सकता है कि उन्होंने बेसिक तौर पर कार्य किए हो, मगर आम किसान, जिनमें छोटे-छोटे भूमिहीन, छोटे-छोटे काश्तकार, सीमांत काश्तकार शामिल हैं, वे ज्यादा कर्ज के अन्दर डूबते गए और कर्ज में डूबने के कारण उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा ।

अभी एक बात कही जा रही थी कि आपकी गवर्नमेंट ने यह किया, वह किया, यह नहीं किया, वह नहीं किया, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मोदी जी की सरकार को 6 महीने ही हुए हैं, मगर आप जरा 60 सालों की तरफ देखिए और उनकी तरफ ध्यान दीजिए । क्या आपने इस देश के अन्दर उनके लिए खेती के पर्याप्त साधन जुटाए, पर्याप्त खाद और बीज जुटाए, पर्याप्त ऋण दिया? आज केवल कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में काश्तकार हैं । यदि आप लोग उस परसेंटेज के अन्दर इस देश के अन्दर वित्त का या बजट का प्रावधान रखते, तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर यह नौबत नहीं आती । आपने कई आयोग बनाए । उन सभी आयोगों ने जो रिपोर्ट्स पेश कीं, यदि हम उन रिपोर्ट्स की ओर देखें, तो उन रिपोर्ट्स में स्पष्ट लिखा हुआ था कि यदि आप ये-ये उपाय करेंगे, तो इन काश्तकारों की माली हालत ठीक हो सकती है । आपने उन आयोगों की रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी के अन्दर डाल दिया, क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी कि आप काश्तकारों के उत्थान की बात करते । उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब हम उन रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो उनके अन्दर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स है । 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ और उन्होंने अक्टूबर 2006 में अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी । ...(**समय की घंटी**)... उन्होंने यह स्पष्ट लिखा कि काश्तकारों को जितनी उत्पादन लागत आती है, यदि उस लागत का 50 प्रतिशत उन्हें बोनस के रूप में दिया जाता है, तो उनको लाभकारी मूल्य मिल सकता है । मगर आपने उसे लागू नहीं किया । यदि उस समय आप इसे लागू कर देते, तो आज काश्तकारों की यह हालत नहीं होती, लेकिन आपने इसमें हिचकिचाहट दिखाई । आपकी सरकार यह नहीं चाहती थी कि हम इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करें ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले काश्तकारों के यहां संयुक्त परिवार होता था । संयुक्त परिवार के अन्दर एक व्यक्ति खेती करता था, दूसरा व्यक्ति पशु-पालन करता था, तीसरा व्यक्ति कोई और धंधा करता था, इस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हुए बहुत सीमित धन में वे अपना खर्च

चलाते थे । मगर जिस प्रकार से आज आधुनिकता की होड़ लगी हुई है ...(**समय की घंटी**)... मैं थोड़ा समय और लूंगा ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : आपके चार स्पीकर्स और हैं ।

**श्री राम नारायण डूडी** : सर, इस प्रकार से उनका खर्चा चलता था, मगर आज आधुनिकता की होड़ लगी हुई है । आज किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहता है, लेकिन उसका खर्च उसकी आय की सीमा में पूरा नहीं बैठता है । इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं । मोदी जी ने जिस प्रकार का विज़न रखा है, उसके अन्दर किसान के बच्चे को बेहतरीन पढ़ाई मिल सकेगी, किसान की आय बढ़ सकेगी । पूरे हिन्दुस्तान के स्तर पर जो काम हाथ में लिया गया है, उस काम का रिजल्ट केवल छः महीनों में ही दिखाई नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि हमारी नीतियों से आने वाले समय में इस देश के किसानों की अवश्य भलाई होगी, किसान सम्पन्न होंगे और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से उसे अपनी फसल का मूल्य मिल सकेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**प्रो. राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, आज सदन के अन्दर Agrarian Crisis के ऊपर चर्चा हो रही है । हमारे माननीय मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह जी और बालियान साहब, दोनों ही किसान परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं । मैं मानता हूं कि किसानों की समस्याओं के बारे में जितना मैं जानता हूं, उससे भी ज्यादा वे इससे परिचित हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसानों के सामने आज बहुत गम्भीर दिक्कतें हैं । मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूंगा, क्योंकि हमारे दूसरे मैम्बर को भी बोलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं ।

किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उपेक्षा आज एग्रीकल्चर सेक्टर की हो रही है । किसान को उसकी फसल की जो कीमत मिलनी चाहिए, वह मिल नहीं पाती है । कई बार तो जितनी उसकी लागत होती है, उस लागत मूल्य के बराबर भी उसे फसल की कीमत नहीं मिल पाती है ।

जब मैं उस सदन में था, तब मैं Agriculture Committee का चेयरमैन भी था । एक बार हम लोगों ने उस कमिशन के लोगों को बुलाया, जो एमएसपी तय करते हैं । हमने उन लोगों से पूछा, यह बताइए कि किस तरह से आप यह मूल्य तय करते हैं और कितनी लागत आती है । उनके हिसाब से, उस वक्त प्रति क्विंटल गेहूं और धान की जो लागत आई, उसके अनुसार Cost of Production, एमएसपी से ज्यादा था । जब लागत मूल्य एमएसपी से ज्यादा होगा, तो किसान आत्महत्या तो करेगा ही, वह घाटे में तो जाएगा ही । आज वही स्थिति है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एफसीआई ने भी चावल लेना बन्द कर दिया है, लेवी 67% से घटाकर 25% कर दी गई है, जो rice mill owners हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में धान खरीदना बन्द कर दिया है । नतीजा यह है कि आपने जो धान का एमएसपी साढ़े 1300 या 1360 रुपये रखा है, उसे व्यापारी लोग 900-950 रुपये में मंडियों से खरीद रहे हैं । इससे किसानों को लगातार 400-500 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है । केवल धान ही नहीं, चाहे वे कपास पैदा करने वाले किसान हैं या जूट पैदा करने वाले किसान हों, सबके सामने यह समस्या है । एक और बहुत बड़ी समस्या यह है, जो कीमतों का फ्लक्चुएशन होता है । कई बार ऐसा होता है कि लहसुन इस साल 4500-4700

[प्रो. राम गोपाल यादव]

प्रति क्विंटल बिक रहा है और अगले ही साल वह 400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा होता है। यह फ्लक्चुएशन रुक नहीं पा रहा है। उसकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि कई बार कोल्ड स्टोरेजेज़ में रखे हुए आलू को निकालने के लिए, उसका किराया देने के लिए भी वह पैसे नहीं दे पाता है। उससे कोल्ड स्टोरेजेज़ भरे रहते हैं, लेकिन कोई उसे लेने नहीं जाता है, उठाने नहीं जाता है। वहीं, कई बार वह इतना महँगा हो जाता है, जैसे इस साल हो गया है, कि जो पैसे वाले उसमें रख लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना ही पड़ेगा कि जब किसान के घर में उपज आए, तो उसको जो मूल्य मिलता है और जब उसके यहां से यह चला जाता है, तब उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है, यह फर्क नहीं होना चाहिए, जिससे किसान को लाभ हो सके। किसान को अभी लगातार नुकसान होता है। किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल यही नहीं, सारा पशुधन जो है, वह किसानी से ही जुड़ा हुआ है। पशुओं को चारा उससे मिलता है। पशुधन से बहुत कुछ हो सकता है। इससे किसान का लाभ हो सकता है। एनिमल हस्बैंड्री और फिशरीज़ भी एग्रीकल्चर के अन्तर्गत ही आती हैं। खेती में तो एक सीमा होती है कि इससे ज्यादा आप पैदा नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल हस्बैंड्री में कोई सीमा नहीं है। आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दूध तथा अन्य चीज़ों की पैदावार ज्यादा हो सकती है। हमारे स्वयं के आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दूध से जो कैपिटल मिलता है, वह गन्ना और धान से मिलने वाले कुल कैपिटल से ज्यादा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो सब्जियां हैं, फल हैं या जो perishable vegetables and fruits हैं, उनके बारे में स्वयं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के और अन्य सोर्सेज़ के आंकड़े हैं कि देश में हर साल लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के फल, सब्जी और मांस सड़ जाते हैं। इतने ज्यादा सामान सड़ जाते हैं कि अगर फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था सही हो जाए, तो किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। कभी-कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। बालियान साहब इसे जानते हैं। जब मैं सम्भल से लोक सभा में था, तो उस इलाके में टमाटर इतने ज्यादा होते थे कि कई बार तो वे ट्रकों और सड़क के किनारे पड़े रहते थे, लेकिन उनको कोई खरीदने वाला नहीं होता था और वे बरबाद हो जाते थे। तो फूड प्रोसेसिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा, किसानों पर कर्ज हो जाता है। आपने बड़े-बड़े लोगों पर - वित्त मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं -- बड़े-बड़े लोगों के ऊपर जो कर्ज है, उसमें लाखों करोड़ रुपये राइट ऑफ कर दिये गये। हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपये राइट ऑफ कर दिये गये और 100 रुपये के लिए किसान जेल चला जाता है। जिन लोगों पर बहुत बड़ा कर्ज है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कॉरपोरेट घराने के लोगों पर, उनको और कर्ज दे देते हैं, ताकि वे कमा सकें और रिपे कर सकें, लेकिन किसान के प्रति ऐसा नहीं है। जितना आपने राइट ऑफ कर दिया, उतना अगर किसानों को दे दें, तो सारे किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। अभी आनन्द शर्मा जी बता रहे थे कि इन्होंने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था, तो आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। आप उन बड़े लोगों से वसूल लीजिए और किसानों का राइट ऑफ कर दीजिए। इससे किसानों का कल्याण हो सकता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किया था कि 4 परसेंट इंटरेस्ट पर किसानों को कर्ज देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में मार्जिनल फार्मर्स से कोऑपरेटिव सोसायटीज़ 4 परसेंट और कहीं-कहीं केवल 2 परसेंट तक ही इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन उस पर भी कांग्रेस की सरकार ने कोई अमल नहीं किया। स्वामीनाथन जी एक बड़े एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे। वे हमारी कमेटी के मेम्बर भी थे।

**3.00 P.M.**

...(**समय की घंटी**)... बस, मैं खत्म कर रहा हूँ । उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, उसके हिसाब से अगर किसान को चार परसेंट की दर से ब्याज लगे, तो वह दे सकता है, क्योंकि किसान के लिए सब कुछ घाटे का सौदा है ।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि किसानों के लिए कर्ज की ब्याज दर चार फीसदी की जाए और बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान ऋणग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए बीमे की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनको लाभ मिल सके । कभी सूखे के कारण उनकी फसल बरबाद हो जाती है, कभी बाढ़ के कारण उनकी फसल बरबाद हो जाती है, कभी ओला पड़ने से बरबाद हो जाती है, तो कभी कोहरे के कारण सारी फसलों में झुलसा रोग लग जाता है। अभी वह मौसम आने वाला है। जैसे ही कोहरा शुरू होगा, यह दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुछ न कुछ उसको कम्पंसेट करने के लिए प्रोवीजन होने चाहिए । इसलिए, हर किसान को एक यूनिट मान कर बीमा योजना लागू करनी चाहिए । अभी आपने एक गांव को भी यूनिट नहीं माना है । इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे उम्मीद है कि किसान के परिवार से आने वाले कृषि मंत्री जी किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, we are discussing a very serious issue. Although it was discussed on several occasions in the past and successive Governments, from time to time, took some measures to address the crisis, we are still confronted with the crisis in such a manner that some more efforts are required from the Government to address the problem.

Sir, I will not take much of your time. There is a widespread perception that unbearable burden of debt and increased competition from imports are symptomatic of a crisis in Indian agriculture. Both these phenomena are real. Inability to bear debt has led to farmers' suicides on an unprecedented scale. I will refer to the suicide figures later. Import liberalization has had a strong dampening effect on the prices of several crops, especially plantation crops. This has caused considerable distress in regions where there is a prominence of farm economy.

Sir, there are two reasons for us to be concerned that Indian agriculture may, indeed, be facing a wider and deeper crisis. First, the long-term growth trend in production and productivity of agriculture considerably less than required to sustain the projected high overall growth rates in the coming decade may actually be slowing down. And, secondly, the growing economical and social disparities between agriculture and the rest of the economy and between rural and urban sectors. We have forgotten that about 70 per cent of our population lives in the rural areas. Many years ago Gandhiji said that India lives in the villages. It is still the reality today that about 833 million people, that is, 70 per cent of the total population, live in villages.

Sir, I would like to quote some important reports here. According to a *Lancet*

[Shri Sukhendu Sekhar Roy]

study made by researchers from London School of Hygiene and Tropical Medicine and other studies made by Cambridge University's Department of Sociology and University College, London, Department of Political Science, the huge variation in suicide rates between Indian States can largely be accounted for by suicides among farmers and agricultural labourers. This is the report of the studies made by different universities across the world. Sir, these studies also say, and I would quote one line, "Farmers at highest risk have three characteristics; one, those that grow cash crops such as cotton, coffee and jute; two, those with marginal farms of less than one hectare of land; and three, those with debts of more than ₹ 500. These are the three areas that they have identified, which are the cause of rampant suicides by farmers. Sir, the study also says that a large proportion of these rural inhabitants have not benefited from the economic growth of the past 20 years. We keep beating drums of economic growth, but no benefit from the so-called economic growth has gone to the kitty of farmers or the rural people of India, and this is a hard reality. Sir, in fact liberalization has brought about a crisis in the agricultural sector; that has pushed many small-scale cash crop farmers into debt and in some cases to suicides. We are aware of the notorious Monsanto company; which has created havoc in the Vidarbha region of Maharashtra, whether it is the BT Cotton or the GM crops or the pesticides. There is a documentary film, not a feature film, directed by world famous documentary film director Mr. Micha X. Peled, an American Director and this film has got more than hundred international awards in different film festivals. I can arrange a special show for the hon. Members of this august House. The day I saw it, I could not withstand the shock and trauma which have been inflicted upon the cotton farmers of Maharashtra. This is not only shocking but inhuman also. According to the New York University School of Law report and I quote its banner headline only which implies everything to make everybody understand what is Monsanto. They say and I quote "Either mankind will stop Monsanto or Monsanto will stop mankind". This is the situation. This is a horrible situation. I am indebted to the brothers and sisters of the Swadeshi Jagaran Manch. They have raised a protest and the Government has reportedly deviated from introducing this GM test trial so far as my knowledge goes. If the Government still sticks to that decision, then this should be opposed tooth and nail by all the patriots and all nationalists.

Now, my next point is if you look at the suicides by farmers due to agrarian distress in 2014, the State of Maharashtra is heading the list. I am having a list with me. There are 204 cases of farmers' suicides in Maharashtra alone from January to April 2014. No figure has been released by the Government regarding farmers' suicides from May to October for reasons better known to the Government. During the 12 months of

last year, 407 farmers committed suicides as compared to 204 in four months of this year. In Telangana up to October, 2014, 69 farmers committed suicides, in Karnataka up to mid-Nov, 2014, 19 farmers committed suicides, in Gujarat from up to October, 2014, 3 farmers committed suicides, in Kerala from up to October, 2014, 3 farmers committed suicides and in Andhra Pradesh up to June, only 3 farmers' committed suicides. So, these are the comparative figures. I am not going to mention the figures of farmers' suicides of 2011 and 2012. But, this is an alarming situation and the Government must address this problem in a befitting manner. I am also coming from an agricultural producing State, that is, West Bengal. What is the situation in West Bengal? We are trying to help the farmers in a manner so that they can earn their livelihood; at least they can maintain their 'animal existence'. The bare 'animal existence' is very important. We are trying our level best to provide some inputs. The cumulative figure for farmers' household income in my State has been increased by 39.64 per cent in the year 2011 to 2013. In the year 2011, my Government came to power led by Ms. Mamata Banerjee. Within two years, there is an increase of 39.64 per cent in income so far as the cumulative figures for farmers' household are concerned. So far as the cumulative figures of quantity of foodgrain produce are concerned, now there has been an increase of 8.54 per cent. As regards, the cumulative figure of State expenditure out of State Budget, there has been an increase of 59.52 per cent in the Budget for agriculture. Production of cereals has increased from 148 lakh tonnes in 2010-11 to 173 lakh tonnes in 2013-14. This way we are doing it. The other areas where we are helping the farmers are: distribution of farm equipment, storage facilities, agro education, seed banks, State seed laboratories and crop insurance. Sir, 15 horticultural crops have also been brought under the purview of crop insurance. Under support to marginal farmers, nearly 50,000 marginal farmers have been given ₹ 5,000 each for purchasing implements as per their choice. We have also introduced pension for farmers. Sir, 66,700 farmers have been brought under Farmers' Old Age Pension Network. We have also set up Brihat Krishak Bazar in different parts of the State. In this way, we are trying to help the farming community of our State. I would personally appeal to the hon. Minister of Agriculture and the Government of India to make serious efforts so that farmers' suicide can be combated without any further loss of time. Sir, there is a need for evolving certain comprehensive measures by the Government of India so that we need not discuss this agrarian crisis time and again. Thank you.

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। सर, बचपन में घाघ कवि की कविताएं पढ़ते हुए हमने कभी पढ़ा "उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान"। कृषि जो है, यह सबसे उत्तम प्रोफेशन में थी और अब यह भीख मांगने जैसी इस देश के अंदर हो गयी, पिछले 60-65 सालों की निरन्तर सरकारों की उपेक्षा की वजह से। माननीय मंत्री जी, जहां से आते हैं वह देश के किसान आंदोलन का और आजादी की लड़ाई के आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा

[श्री के.सी. त्यागी]

है-चम्पारण। अपने वक्तव्य के दौरान मैं उम्मीद रखूंगा कि गांधी जी का संकल्प और किसानों की करुणा का उनके मन में कुछ ध्यान होगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 9 जुलाई को आपके स्थान पर डिप्टी चेयरमैन थे, मैं यहां था और माननीय मंत्री जी यहां थे, उनका मैं 9 जुलाई का एक वक्तव्य सुनाता हूं । जो गन्ना किसानों के बकाया के बारे में मैंने उठाया था । I am quoting Shri Radha Mohanji. "सरकार ने पैसा नहीं दिया है, सरकार ने बैंकों से कहा है कि आप इन्हें ऋण दीजिए, इंटरेस्ट हम देंगे लेकिन इंटरेस्ट हम तब देंगे जब पैसा किसानों के खाते में जाएगा ।" यह पूरा असत्य है । उसके बाद इन्होंने भी और जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अच्छा होता वे भी यहां होते, जस की तस स्थिति है । सरकारों की अदला-बदली से हमारी किस्मत बदलती है, हम नहीं मानते । जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि भाग्य और भाव, यह भगवान लिखता है कि भाग्य में क्या लिखा है और किसान का भाव क्या होगा । तो सरकारों की अदला-बदली से कुछ फर्क पड़ता है, हम ऐसा नहीं मानते और जो आपकी जगह उपसभापति महोदय थे, I am quoting his statement, "That it is taken note of and you can look into it and reply to him." He directed the Minister of Agriculture and Consumer Affairs. सर, 1950-51 में जो सकल घरेलू उत्पादन था कृषि और उसके सहायक उद्योग का, वह 51 परसेंट था । सर, आज वह घट करके 1912-13 में 13.7 परसेंट रह गया । सर, मुझे कष्ट यह है और एलीगेशन के तौर पर नहीं, पीड़ा के तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के काबिल अध्यक्ष थे श्री राजनाथ सिंह, जो किसानों के हमदर्द थे और हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी थे, उन दोनों ने समूचे देश से कहा था, मैं बी.जे.पी. का घोषणा पत्र अगर मेरे मित्र कहेंगे तो वह पढ़कर सुना सकता हूं, और उनके डेढ़ दर्जन वक्तव्य हैं कि अगर हम सरकार में आए, अगर हमारी सरकार बनी तो जो लागत मूल्य that is the cost of production उसमें 50 परसेंट प्लस करके हम किसानों को देंगे । सर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलें की समिति है, उसने बिना किसी तब्दीली के आयोग की सिफारिश से रबी की फसल में 50/- रुपए की मामूली वृद्धि की है । अगर मैं सारी फसलों को गिनवाऊं, तो पिछले साल के मुकाबले दामों में टोटल 3 परसेंट की वृद्धि हुई है । जिनको सत्ता से बाहर किया कि ये किसानों के हमदर्द नहीं हैं, उनके स्थान पर जो सरकार आई, उसने 50 परसेंट का वादा किया, लेकिन किसानों की फसलों के दामों में सिर्फ तीन परसेंट की वृद्धि हुई है । मैं आपको भी, वित्त मंत्री महोदय को भी, आप बीजेपी के हैं और मैं जनता दल (यू) का हूँ इस नाते से नहीं, किसान पुत्र होने के नाते से इस सदन में चुनौती देना चाहता हूँ कि आप किसी भी लागत मूल्य का मूल्यांकन करा लीजिए, मैं आज के बाद वक्तव्य नहीं दूंगा, गन्ने का भाव 300/-रुपए प्रति क्विंटल बैठता है और जो आपने एफआरपी तय की है वह कितनी की है? यह आज की बात नहीं है, वे भी कोई कम गुनाहगार नहीं हैं । हमारे साथी, जो अकाली दल वाले बैठे हैं, सब जानते हैं, मैंने बहुत कम उम्र में चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में, उस समय बोट क्लब पर एलाउड था, धरने पर बैठते थे । हम यह मानते थे कि उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी वह एंटी-किसान सरकार थी । उस समय चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता थे । सरकारों की अदला-बदली से किसान के भाग्य में और उसके भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, जस का तस है ।

सर, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, जिनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ । अभी प्रधान मंत्री जी महाराष्ट्र गए थे और जब उन्होंने इनकी सरकार को चेलेन्ज करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में 3500 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे देश के प्रधान मंत्री से उम्मीद बंधी थी, मगर सरकार

बने छह महीने हो गए। तीन दिन से नागपुर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गन्ना और कपास के किसान धरने पर बैठे हैं। वह वही जगह है, वही असेम्बली है, मुख्यमंत्री की अदला-बदली हुई है, लेकिन भाग्य और भाव में कोई अदला-बदली नहीं हुई। तीन मिनट में इंडियन फार्मर सुसाइड कर रहा है, यह रेट है। एक बार में टीवी डिस्कशन में था, चीनी मिल मालिकों का एक अधिकारी मेरे सामने बैठा था। पहले वह कन्ज्युमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में अधिकारी था, मैंने वहां किसानों की आत्महत्या का जिक्र किया और मैंने बहुत विनम्रता से पूछा, मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, कि क्या किसी चीनी मिल-मालिक ने भी आत्महत्या की है? उसकी कहानी अगर सुनाऊंगा, तो और छोटे पड़ जाएंगे। पिछले एक साल में इस सदन में मैंने क्या-क्या देखा है? आपने 12 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया है, इन्होंने भी दिया है, ये कोई पीछे नहीं रहे, किस काम के लिए? To bail out the Sugar Mills Association. सर, तीन स्टेक-होल्डर्स हैं-चीनी मिल-मालिक हैं, हम किसान हैं और कन्ज्युमर्स हैं। न कन्ज्युमर्स का भला होता है, न हमारा भला होता है, सिर्फ और सिर्फ चीनी मिल-मालिकों का भला होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, the moment I am talking to you, 3300 करोड़ रुपये किसानों पर आज भी बकाया है। आपने गलतबयानी की, आपने कहा कि उनके खातों में जाएगा। उन्होंने लंबी-लंबी कारें खरीदीं, यह मेरी जानकारी में आया है। उनके अधिकारियों ने मुझे बताया कि जो पैसा आपके यहां से गया है, उससे ऐय्याशियां हो रही हैं, दूसरे पेशों में लगा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यह हमारी पीड़ा वित्त मंत्री जी के पास जाए। अब वित्त मंत्री जी से भी जुड़ा हुआ मामला है। बजट आ रहा है। फिक्की के, सीआईआई के, एसोचैम के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। गलती से एक बार किसानों के प्रतिनिधियों को बुला लीजिए, आप चाहें तो भारतीय किसान संघ को बुला लीजिए। जयपुर में अभी स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम हुआ। जब जॉर्ज साहब हम लोगों के नेता थे, उनके साथ हमें उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आपके किसानों के सवाल पर, आपके मजदूरों के सवाल पर उनकी आपसे असहमति है, विचार आपका भी यही है और विचार उनका भी यही है, वे सत्ता में नहीं हैं और आप सत्ता में हैं, फर्क इतना है।

महोदय, मैंने कल डब्लूटीओ का जिक्र किया था, लेकिन उसका पासिंग रेफरेन्स जरूर दूंगा। हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय की जो आर्थिक नीतियां थीं, आप उनको भी छोड़ दें,... डीनेशनलाइजेशन हो रहा है उन सारी चीज़ों का, जिनके लिए आपकी नेता जानी जाती थीं, जिनकी वजह से उन्होंने ढाई सौ की कांग्रेस को चार सौ तक पहुंचाया था। अब वह रिपोर्ट भी आने वाली है। रिपोर्ट्स सारी आपके टाइम की हैं। आपने बनाई थीं रिपोर्ट्स और ये रखेंगे। जितनी भी कमेटियों की मीटिंग्ज़ में मैं जाता हूं, कांग्रेस पार्टी के टाइम की रिपोर्टें, they have implemented. तो इनको भी कैसे गाली दें ? आप कुछ इश्यूज़ पर इश्यू बनाइए। ये जो नीतियां हैं, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, हम और हमारे नेता उसे नहीं मानते। लोहिया-जयप्रकाश जी की असहमति थी, लेकिन जवाहरलाल ठीक थे। विदेश नीति में ठीक थे, नेशनलाइजेशन में इंदिरा गांधी जी ठीक थीं। उन्होंने 800 चीजों पर प्रतिबंध लगाया था कि ये चीज़ें बाहर से नहीं आएंगी और बड़े सेक्टर में नहीं बनेंगी। आप भी उस दुनिया में चले गए और उस दुनिया में ये आपसे आगे हैं। आर्थिक नीतियों पर अगर पल-पल इनका विरोध नहीं करोगे, तो माफ करना, आप दूसरी पार्टी के लोग हो, इनसे एक-एक चीज़ में अलग नहीं दिखोगे, तो वहां नहीं पहुंचोगे, जहां पहुंचना चाहते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सवालों पर मुस्तैदी से ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला बोल रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : इसीलिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, मैं अपनी पार्टी से अकेला बोल रहा हूं ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : आपके दस मिनट हैं । ...**(व्यवधान)**...

**श्री के.सी. त्यागी** : सर, आपकी कृपा मुझ पर कम रहती है । ...**(व्यवधान)**... रूडी साहब बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था । यह पार्टियों का मामला नहीं है । यह गांव के लोगों की agony है । आपातकाल में मैं जेल में था । सुबह के टाइम चार किसान मुझे रोते हुए मिले । मैंने पूछा तो पता चला कि कर्ज़ वसूली में आए हैं । कितना है? उस ज़माने में, 1975 में, पांच सौ रुपए बहुत हुआ करते थे । इसी सदन में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं । उनकी सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण माफ किए हैं । इनकी सरकार दस लाख करोड़ रुपए के कर सकती है कि "तू डाल-डाल, मैं पात-पात"। चूंकि जो प्राइयॉरिटीज़ हैं, जब देश के प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दे दिया, बुरा मत मानिएगा कि मेरी नस-नस में व्यापार है, तो मैं चाहता हूं कि वे कहते कि मेरी एक नस में व्यापार है, दूसरे में खेती है, तो हमारे जैसे लोगों का मन प्रसन्न हो जाता । ...**(समय की घंटी)**... लेकिन उन्होंने वह नहीं कहा ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : आप अच्छे किसान हैं, इसलिए एक मिनट और ले लीजिए, वैसे आपका टाइम समाप्त हो गया है ।

**श्री के.सी. त्यागी** : बड़ी कृपा है आपकी ।

सर, मैं प्राथमिकताओं के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं और राधा मोहन जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं । इतने सज्जन हैं कि इनको पूरा भी नहीं कर सकते हैं । एक तो इरिगेशन का मामला है । इस देश की लगभग 60 परसेंट ज़मीन नॉन इरिगेटेड है । भगवान तय करेगा कि वहां पर फसल ठीक होगी या नहीं? 70,000 करोड़ रुपए में बुलेट ट्रेन चलेगी और उसी बजट में इरिगेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न होगा, तो कोई भला नहीं हो सकता । आप बढ़ाइए । इस वजह से भी बढ़ाइए और सारा विपक्ष आपके साथ रहेगा ।

सर, गन्ने के भुगतान के बारे में मैंने आपको बताया । अब एमएसपी में तीन परसेंट की वृद्धि हुई है । बालियान जी आप वहीं से आते हैं, जहां चौधरी चरण सिंह जी का कार्य क्षेत्र है । कैसे आप वहां के किसानों को शक्ल दिखा सकते हो और इतना भी कीजिए कि जो गन्ना, चना, चावल, गेहूं ज्यादा पैदा करे, तो सरदार पटेल और चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसी पुरस्कार की घोषणा कर दीजिए कि इस देश में जो सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करेगा, उसको सरदार पटेल पुरस्कार मिलेगा । हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है । चौधरी चरण सिंह के नाम पर कर दीजिए । ...**(समय की घंटी)**... हमारे मित्र यहां बैठे हैं, इनका नालन्दा जिला है, हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं पैदा करने वाले किसान इनके यहां के हैं । सरकार ने कभी प्रोत्साहित नहीं किया । ...**(समय की घंटी)**... मैं कन्क्लूड ही कर देता हूं, फिर पढ़ देता हूं । आपकी भी इच्छा नहीं है ।

हमारे लिए भूमि अधिग्रहण कानून बना था । हमारे मित्र रमेश जी बैठे हैं । मेराथन एफर्ट्स किए थे, लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, हमारी बहन सुषमा जी ने, उन्होंने कहा - This is my

programme. This is my Adhigrahan. उसमें भी बड़े पूंजीपतियों के दबाव में आकर हमारा गला काटने का प्रयास हो रहा है ।

सर, 165 ज़िलों में नक्सलवादी थे । जिस दिन से मनरेगा लागू हुआ, 85 जिलों में नक्सलवादी रह गए । आप सीना तानकर क्यों नहीं कहते कि हमारी इन योजनाओं से गरीबी घटी है? अगर ये कम करना चाहते हैं, तो यहां काम मत होने दीजिए और सड़क गरमाइए, जैसे 22 तारीख को मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम वादा निभाओ के रूप में आ रहे हैं । एक-एक चीज़ पर लड़िए । BT cotton का भी अभी ज़िक्र किया गया ।

सर, एक साजिश और है, मल्टीनेशनल्स की तरफ से, अमेरिका की तरफ से । ...**(समय की घंटी)**... यहां पर बीजों की ऐसी भरमार की जा रही है, जो अमेरिका के हों । पहले तो बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों ने मना किया था, अब पता नहीं किस दबाव में वे कह रहे हैं कि हम अपने यहां एप्रिसिएशन कराएंगे । सर, जब भुखमरी से या कर्ज की वजह से कोई किसान आत्महत्या करता है या बकाए की वजह से आत्महत्या करता है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तय कीजिए और एक-आध को सस्पेंड कीजिए कि कैसे किसान ने आपके यहां आत्महत्या की । सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मेरा जो सबसे प्रिय विषय है, मैं उस पर आना चाहता हूं कि आपका दाम तय करने का मेकेनिज्म क्या है । जो कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष इन्होंने तय किया था, who is not a farmer, वह इनका अध्यक्ष है । जो पिछली सरकार ने किया, जस का तस है, न उसमें कोई एग्रीकल्चरिस्ट था, न कोई किसान वैज्ञानिक था, जस के तस बैठे हुए हैं । आप उसे डिज़ॉल्व करो । आपने अन्य कई संस्थाएं डिज़ॉल्व कर दी हैं । आप ऐसा कृषि मूल्य आयोग बनाओ, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों और कृषि वैज्ञानिक हों ।

सर, अंतिम बात मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप किसी संस्था को ले लीजिए, आप बिठा लीजिए, इनका एक आदमी ले लीजिए, हमारा ले लीजिए, अपने बिठा लीजिए और भारतीय किसान संघ पर छोड़ दीजिए । अगर इन सारी चीज़ों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने तय किए हैं, वे निकल जाएं तो इन सवालों पर मैं संसद में कभी बहस नहीं करूंगा, लेकिन जो वादा किया है, निभाना पड़ेगा । आप ही ने कहा था । उम्मीदें आप ही ने जगायी थीं, इन्होंने भी उम्मीदें जगायी थीं । जो हश्र इनकी उम्मीदों का हुआ, अगर आप वादा नहीं निभाओगे तो वही हश्र आपकी उम्मीदों का भी होगा । इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि जो किसान का खाली पेट है, वह बद्दुआओं से ही इतना काम कर देगा कि वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह** (बिहार)ः महोदय, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं । अभी के.सी. त्यागी जी ने कहा....

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : जब आपका नम्बर आएगा, तब आप अपनी बात कहिएगा ।

**श्री बशिष्ठ नारायण सिंह** : मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं । के.सी. त्यागी जी ने अभी प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य पर और व्यापार के संबंध में उनकी जो राय थी, उस पर कहा है । चाणक्य ने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा, प्रजा को भिखारी होने से कोई रोक नहीं सकता ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : वे तो चाय वाले थे, आप भूल गए हैं ।

SHRI T. RATHINAVEL (Tamil Nadu): I thank the Chair for giving me an opportunity to take part in the discussion on agrarian crisis that has been devastating the economic infrastructure and the life and livelihood of our people, especially in the rural areas of our sub-continent. On behalf of our AIADMK Party led by our compassionate and visionary leader, Makkal Muthalvar, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, I would like to make certain observations from our experience of handling the great disasters like Tsunami, Thane Cyclone and inundating floods due to heavy rains in many parts of Tamil Nadu. All these disasters were met with prompt relief and rescue operations by our decisive leader with great concern for the poorer and affected sections of our society. That is why our leader remains in the hearts of our people as People's Chief Minister. We are discussing, almost in every session, the difficulties faced by the agriculture sector in this august House. Now, when the service sector is emerging to be the engine of our economy, we cannot ignore agriculture sector. At this point of time, I would like to bring to the notice of the Government the very alive issues taken up by our beloved leader, Dr. Amma, with the hon. Prime Minister himself. The lasting and permanent solution for river water sharing pertaining to River Cauvery needs no mention. As one hailing from the sands of golden River Cauvery, I would like to reiterate the demand made by our leader.

Agrarian crisis arise due to various factors like nature's fury and the human indifference. If the Central Government is indifferent to the request of the State Government with regard to funding for schemes and assistance meant for agricultural sector, it may also lead to agrarian crisis. Our People's Chief Minister, Dr. Amma, had taken up with the Centre and directly with the hon. Prime Minister to the need to follow a uniform pattern of 50 per cent subsidy to small and marginal farmers and 35 per cent to other farmers in all blocks. This is necessary because the National Mission for Sustainable Agriculture taken up by the Centre extends a differential and reduced subsidy regime for micro irrigation schemes. As 305 out of 385 blocks are treated as non-drought-prone areas, the subsidy for the farmers has been reduced affecting agriculture in a big way.

Urea manufacturers in Tamil Nadu may be allowed to continue with urea production with Naphtha as feedstock. This is necessary till a permanent solution for the supply of gas is evolved. This will also help our farmers in Tamil Nadu because they are facing an acute fertilizer shortage. Our State perspective and implementation plan is a part of the Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission. The project cost was estimated at ₹3,296.97 crores for the seven years from 2012 to 2020. We have got only ₹135 crores and ₹84 crores for the first two financial years from the Centre. But,

the Centre's share is ₹2,472 crores for implementing this Mission. With the failure of the Centre to release the full share of funds, it is only the farmers who face financial crunch leading to crisis.

In Tamil Nadu, we have taken up many comprehensive measures to improve the lot of the rural people especially the agriculturists and agricultural workers. But, still, the farm sector has to face challenges in the form of not getting water for irrigation or not getting the subsidized fertilizers in time. Our Government of Tamil Nadu, guided by our Dr. Amma, has taken up with the Centre to amicably solve the river water sharing crisis and release of fertilizer quota along with positive interventions favouring agricultural sector in the form of credit facilities and fixing up minimum support price for the agricultural produce.

In 1950-51, the net cultivated area in the country was 119 million hectares. In 2010-11, even after a gap of 60 years, the cultivable areas have increased only up to 140 million hectares. At a time when scientific and technical advancements are available, the rise in cultivable areas must have increased further. The average growth rate of agricultural sector in 12th Plan period and the previous Plan period remains the same.

At this juncture, I would like to bring to the notice of the Union Government that the Grants-in-Aid for Accelerated Irrigation Benefit Programme is released fully. Most importantly, the Agriculture Insurance mechanism must be strengthened. I also urge upon the Centre to take up vigorously the National Mission for Sustainable Agriculture. It will provide opportunities for the State Governments to serve the people better. Tamil Nadu, as guided by our Makkal Muthalvar Dr. Amma, is taking up several measures to ensure that the shades of an agrarian crisis do not darken the bright Tamil Nadu. But, still, we need the Centre to be liberal with funds to Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to evolve a long-term plan to overcome the agrarian crisis once and for all.

I would like to conclude by saying that let us not throw blame on mother nature every time.

**श्री राजपाल सिंह सैनी** (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । साथ ही मैं अपनी नेता बहन सुश्री मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज सदन में बोल रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में व्याप्त कृषि संकट पर आज चर्चा हो रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । हमारे दोनों मंत्री किसान परिवार से हैं । भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह सच भी है, लेकिन एक दूसरी भावना भी है, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं । हम

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

केवल उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन उत्पादन करने वाले के बारे में हम नहीं सोचते हैं, उसके सम्मान के बारे में नहीं सोचते हैं । महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो किसान गर्व से कहता था कि मैं किसान हूं । उसका पेशा सम्मान का था और किसान अपने बेटे को पढ़ाकर, अपने साथ खेती में ही लगाता था । यह लम्बा समय नहीं है, यह कोई लम्बी बात नहीं है, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है । किसान अपने बेटे को पढ़ाकर खेती में लगाना पसंद नहीं करता है । वह उसको नौकरी करवाना पसंद करता है, चाहे वह नौकरी कैसे भी मिले और किसी भी प्रकार की हो । किसान को और उसके बेटे को पता है कि अब कृषि फायदे का कार्य नहीं है, इसलिए कृषि से उसका मोहभंग हो रहा है ।

महोदय, सन् 1951 में भारत में 71 प्रतिशत किसान थे , लेकिन सन् 2011 में कृषि जनगणना के अनुसार किसानों की संख्या घटकर केवल 45.01 परसेंट बची है । हमारे किसान 26.09 परसेंट गायब हो चुके हैं । यह इस बात का प्रमाण कि किसान का मोहभंग खेती की तरफ से हो रहा है । यह क्यों हो रहा है, अभी मुझ से पहले बोलने वाले भाई श्री के.सी. त्यागी जी बता चुके हैं । महोदय, कभी जिसका दादा सौ एकड़ जमीन जोतता था, पचास एकड़ जमीन जोतता था, उसका पोता आज एक सीमांत किसान है और आज वह मजदूरी करने के लिए मजबूर है । उस वक्त जिसके पास एक छोटा उद्योग था, आज वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन चुका है । यदि उसको अरबपति, खरबपति भी कह दें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । दोनों का मिलान कहां होगा? व्यापार घोड़े की चाल चल रहा है और खेती कछुवा चाल चल रही है ।

महोदय, पहले गांव में 82.0 प्रतिशत लोग बसते थे । यह सन् 1951 की बात है और अब 2011 में 60.08 प्रतिशत लोग गांव में रह गए हैं । वे मजबूर हैं और खेती में कोई इन्टरेस्ट नहीं है । आज जमीन घट रही है, इसलिए वे गांव को छोड़-छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं । कोई बेचारा रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है । उनके पास घर नहीं हैं और वे पेड़ के नीचे रहते हैं तथा वहीं अपनी शादी कर लेते हैं । वे वहीं पर हनीमून मनाते हैं और वहीं बच्चा पैदा करते हैं । उनके घर पेड़ के नीचे हैं । उनके शहर में आने का यह दुष्परिणाम है ।

महोदय, आज किसान दयनीय स्थिति में है और उसकी स्थिति को वे लोग नहीं जानते, जो उसके द्वारा तैयार की गई उपज का मूल्य लगाते हैं । अभी त्यागी जी बता रहे थे कि जो मूल्य आयोग का अध्यक्ष है, उसे पता ही नहीं है किसान क्या होता है? अध्यक्ष को क्या पता खेती क्या होती है और गन्ना कैसे पैदा होता है? उसको क्या पता कि गन्ना पैदा करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है । इसलिए जब तक यह अध्यक्ष किसान की फसल का मूल्य तय करेंगे, तक तक किसान का भला नहीं हो सकता । जब तक मूल्य तय होते समय धोती वाला नहीं बैठेगा, तब तक किसान को उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता और उसकी स्थिति दयनीय बनी रहेगी । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, दोनों ही मंत्री किसान हैं । डा. संजीव कुमार बालियान जी, यहां बैठे हुए हैं । जब डा. संजीव कुमार बालियान जी को मंत्री बनाया गया, तो हमें उम्मीद जगी थी कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का भला होगा । उन्होंने प्रयास भी किया है और मैंने उन्हें गन्ने के भुगतान के लिए भागते हुए देखा भी है, वे नौजवान हैं । लेकिन कुछ नहीं हुआ और वही जस की तस स्थिति है और किसान को गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ है । अभी त्यागी जी बता रहे थे कि 66,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज के ऋण दे दिया और इस शर्त पर दिया कि तुम्हें

किसान को पेमेंट करनी है, लेकिन किसान की पेमेंट का एक पैसा नहीं दिया और दूसरे धंधे में लगा दिया । सरकार क्यों नहीं पूछती? वह तो सरकार के अधीन है और दुनिया भर की छूट दे दी गई । जो उन्होंने छूट मांगी, वह छूट दे दी गई । उसके बाद भी किसान को गन्ने का रेट नहीं मिल रहा है । आज भी किसान परेशान है । मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है और गन्ने के किसान हैं । हम कितनी मेहनत करके गन्ना पैदा करते हैं, इसमें हमारा पूरा परिवार लगा रहता है । उसके बाद ही गन्ने की फसल पैदा होने में सफलता मिलती है। जब उसको रेट मिलता है, तो भुगतान होता नहीं है । अगर गरीब को शादी करनी होती है तो वह शादी नहीं कर पाता है । महोदय, मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं । मेरे गांव के एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी । वह पचास हजार रुपए लेकर घर गया । घर वालों ने पूछा कि ये पचास हजार रुपए कहां से लेकर आए हो, तो उसने कहा कि मैं कर्ज लेकर आया हूं और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी । वह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया । जब बीमार पड़ गया, तो इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो पता लगा कि बेटी की शादी के लिए जो पचास हजार रुपए लेकर आया था, वह अपनी किडनी बेचकर लाया था । कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का अन्नदाता, जिसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, उसकी यह दुर्दशा हो गई है कि किडनी बेचकर अपनी बेटी की शादी करनी पड़ रही है । माननीय मंत्री जी, इस पर सोचना होगा, आपको किसान के हित के लिए कुछ न कुछ करना होगा । आप यह अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा । ...(**व्यवधान**)... क्या कह रहे हैं?

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर)** : आप इधर एड्रेस कीजिए ।

**श्री राजपाल सिंह सैनी** : अभी मेरे साथी चर्चा कर रहे थे कि उद्योगपति के पास चाहे जितना कर्ज़ हो, माननीय राम गोपाल यादव जी ने भी कहा कि अगर उद्योगपति के पास कर्ज़ा है, तो भी फिर से कर्ज़ा दिया जाता है, उसकी वसूली से कोई मतलब नहीं है । उसके पास सरकार जाती ही नहीं है, उसके पास तहसीलदार, एसडीएम जाता ही नहीं है, क्योंकि वह बड़ा उद्योगपति है, सरमायेदार है, कॉरपोरेटर है, लेकिन यदि किसान के पास किसी का दस हजार रुपये का कर्ज़ है, तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है । वह किसान, जो इतना अनाज पैदा करता है और पूरे हिन्दुस्तान को पालने का काम करता है, उसके साथ यह बर्ताव किया जाता है । जब तक हिन्दुस्तान में यह दोहरी नीति रहेगी, तब तक किसी का भला, किसान का भला हो नहीं सकता है ।

किसान के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएं आती हैं । बेचारा किसान परेशान है । मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि वहां रात में दो बजे बिजली आती है । अगर कड़ाके की सर्दी है, रात है, परंतु यदि रात में दो बजे बिजली आती है तो वह अपने परिवार के सदस्यों को खेत पर लेकर जाता है, अपना ट्यूबवेल चलाता है और सिंचाई करता है । उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? इसको कितने लोग जानते हैं? क्या मूल्य आयोग के अध्यक्ष जानते हैं कि किसान रात में दो बजे जाकर ट्यूबवेल चलाता है? रात को दो बजे ट्यूबवेल चलाने का मतलब कड़ाके की ठंड में जाना है । क्या कोई जा सकता है? अगर हम एक गाड़ी वाले को दिन में आगरा लेकर जाएं, तो वह 2000 रुपये में जा सकता है, लेकिन अगर उसको रात में लेकर जाएंगे, तो वह 5000 रुपये मांगेगा । आप सोच सकते हैं कि इस तरह से किसान अपनी खेती करने के लिए कितना मजबूर है, इसलिए किसान के बारे में सोचना पड़ेगा । उसके सामने और भी परेशानियां आती हैं । जैसे दैविक आपदा है, जब उसकी फसल

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

तैयार होती है, तो कभी ओला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसकी फसल की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य तय है । मैंने देखा है सरकार पच्चीस रुपये का चैक दे देती है, पंद्रह रुपये का, तेरह रुपये का चैक दे देती है । किसान इसको लेकर कहां जाए? यह मज़ाक नहीं तो और क्या है? बैंक वह जा नहीं सकता, उसके साथ मज़ाक किया जाता है ।

और भी अन्य कई समस्याएं हैं । यहां जो मेरे साथी किसान हैं, वे तो समस्याएं जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं हैं, उन बेचारों को क्या पता कि हिन्दुस्तान में नीलगाय भी है, जंगली सूअर भी है और ये किसान के दुश्मन हैं । ये किसान की खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं । उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है । इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए । ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन व्यावहारिक बातें हैं । ये व्यावहारिक बातें हैं, ये आंकड़े नहीं हैं, इसलिए किसान को सभी सुविधाएं देनी पड़ेंगी । ...(**समय की घंटी**)... उपसभाध्यक्ष जी, मैं अभी बोलंगूा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा । आप इन बैकबेंचर्स को देखकर घंटी बजाते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उनके लिए पूरा टाइम है । आनन्द शर्मा जी यहां नहीं हैं, सीतारमण जी भी नहीं हैं, कल डब्ल्यूटीओ पर बात हो रही थी ...(**व्यवधान**)... त्यागी जी, मैं बोलंगूा कि कल डब्ल्यूटीओ पर बात हो रही थी । चूंकि आनन्द शर्मा जी, क्योंकि पहले वाणिज्य मंत्री हैं, सीतारमण जी अब हैं - मैं तो जब किसान का नाम आता था, फॉर्मर का नाम आता था, तो ईयरफोन कान पर लगा लेता था, उनको सुनता था, और हमें कुछ पता नहीं है । त्यागी जी किसान के लिए बहस कर रहे थे और जब वे फॉर्म बोलती थीं, तो मैं तुरंत कान पर लगा लेता था कि किसान संबंधित कोई बात है, इसलिए अंग्रेजी बोलने वालों को पूरा टाइम देते हैं और हम बेचारे हिन्दी बोलने वाले पिछड़ रहे हैं । हिन्दुस्तान तो हिन्दी वालों का देश है ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी.सिंह बदनौर)** : हिन्दी का महत्व हर वक्त रहेगा । आप फिक्र मत कीजिए, बोलिए ।

**श्री राजपाल सिंह सैनी** : मान्यवर, सुनिए । दिग्विजय साहब, मैं आप लोगों से कहता हूं, कि अगर आज हिन्दुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो हिन्दी बोलकर बनी है । वे कहीं भी जाते हैं, हिन्दी बोलते हैं । उन्होंने लोगों के दिल जीतने का काम किया या बेवकूफ बनाने का काम किया जो अपनी सरकार बनाकर ले गए । ...(**व्यवधान**)... हटाएंगे हिन्दी वाले । आप सही कह रहे हैं यदि मोदी हट सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी हिन्दी से हट सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलना छोड़ो, हिन्दी बोलो । हिन्दी बोलोगे तो हटा सकते हैं, वरना हट नहीं सकते हैं । उद्योग लगाने के लिए ...(**समय की घंटी**)... मैं जरूर बोलूंगा, आप घंटी बजाते रहोगे, मैं फिर भी बोलूंगा, उद्योग लगाने के लिए ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : ये लोग आपका टाइम ले रहे हैं । आपको पता ही नहीं है कि ये लोग आपका टाइम ले रहे हैं ।

**श्री राजपाल सिंह सैनी** : मैं पढ़ देता हूं । मैं बस एक मिनट में अपनी बात कह देता हूँ । किसान की उपजाऊ जमीन को उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए सस्ते दाम पर अपने नाम करा लेते हैं, लेकिन वे उस पर उद्योग नहीं लगाते और जमीन वर्षों तक खाली पड़ी रहती है, फिर उसकी नोइयत चेंज करा कर, उसकी श्रेणी चेंज करा कर ऊँचे दाम पर बाजार में बेच देते हैं,

जिसका पूरा लाभ उद्योगपति उठाते हैं । मेरा सुझाव है कि उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बंजर या पथरीली जमीन देनी चाहिए, जिससे वहां का विकास भी होगा और किसान की उपजाऊ जमीन बचेगी । ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, देश में 751 कृषि विकास केंद्र हैं, जो किसानों को समय-समय पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की ट्रेंनिग देने का काम करते हैं, लेकिन न तो उनके पास जमीन है, न साधन हैं, न उपकरण हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है । उन्हें पूरी तरह मजबूत करना पड़ेगा, तब किसानों का भला होगा । ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर)** : थैंक्यू । श्री के.एन. बालगोपाल ।

**श्री राजपाल सिंह सैनी** : सर, मैं बस एक मिनट मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ।

महोदय, अगर खेती को बचाना है, तो खेती के प्रति किसान का लगाव बढ़ाना होगा और हमें नई-नई तकनीक पर कृषि को लाना होगा । त्यागी जी, इजराइल की तर्ज पर खेती करनी होगी, ड्रिप इरिगेशन लानी होगी और किसान को पूर्णतः अनुदान देकर नई तकनीक का उपयोग करते हुए किसान का लगाव कृषि की ओर बढ़ाना होगा और किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य समय पर देना होगा ।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सरकार से अनुरोध करूँगा कि आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, माननीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी, भाई संजीव कुमार बालियान जी, आपने और आपके नेता ने जो भरी सभाओं में हमारे यहां भी गए थे और कहा था कि किसानों, मेरी पूरी सरकार बनवाओ ।

**श्री उपसभापति** : आप समाप्त कीजिए ।

**श्री राजपाल सिंह सैनी** : उपसभापति जी, आप आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा । मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ । हमारे सम्मानित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहां भी गए थे और उन्होंने भरी सभा में कहा था कि किसानों, मेरी बहुमत की सरकार बनवा दो, मैं 100 दिन में तुम्हारी जेबें भर दूँगा, तुम्हारी पेमेंट करा दूँगा । मान्यवर, 200 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी किसान की जेब में एक रुपया नहीं गया है, उनकी जेबें खाली हैं, वे रो रहे हैं । माननीय राधा मोहन सिंह जी, भाई संजीव कुमार बालियान जी, जो वादे आपने किए थे, आप उनको पूरा कर दीजिए और किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए चुनाव में किए हुए सभी वादों को पूरा करके किसानों के साथ इंसाफ करिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री भूपिंदर सिंह** : डिप्टी चेयरमैन सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह सुन-सुन कर कान पक गए हैं, थक गए हैं । जब हम बाहर जाते हैं, तो किसान सवाल पूछता है कि जब आप लोग वोट लेने के लिए आते हैं, तब तो बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं, हम आपकी सरकार भी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी के ऊपर आपकी लाठी चलती है, तो वह केवल किसान के ऊपर चलती है । यह कृषि प्रधान देश, डिप्टी चेयरमैन सर, it has become a slogan, there is no

[श्री भूपिंदर सिंह]

conviction. Let us accept this reality. अपनी छाती पर हाथ रख कर हम सब यहां एक बार सोचें कि आज अगर 80 प्रतिशत किसान सिक हैं, बीमार हैं, तो यह देश कैसे स्वास्थ्यवान हो सकता है, हिन्दुस्तान कैसे विश्व में बड़ा हो सकता है और स्वास्थ्यवान देश हो सकता है? आप यह फार्मूला मुझे बताइए । कौन बताएगा कि जिस देश का किसान, जिस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या सिक हो, बीमार हो, जो रात को सो नहीं पाता है, सुबह क्या करूँगा, सोच नहीं पाता है, तो वह देश कैसे खुशहाल और हरियाला हो सकता है? मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि आज उन्हें यहां आकर एक शब्द बोलना चाहिए कि आपने जो वादा किया कि किसान जितना खर्च करता है, आप उसका कास्ट प्लस 50 प्रतिशत भाग देंगे, यह आप कह रहे हैं । जैसा त्यागी जी ने भी बताया, हम सब पिछले दिनों से बताते आ रहे हैं, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते समय किसान को क्यों नहीं बुलाते कि वह कितना खर्च करता है? कहा गया है कि आज हमारे जो कृषि मंत्री हैं, वे भी एक किसान परिवार से हैं । हम सब, जो यहां आए हैं, उनमें से कोई यह कह नहीं सकता कि मेरे बाप-दादा किसान नहीं थे, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मेरे फादर किसान नहीं थे, तो मेरे ग्रैंडफादर जरूर किसान थे, अगर वे भी नहीं तो, उनके पिता जी जरूर किसान थे । इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हम लोग, चाहे राज्य सभा में हो, लोक सभा में हो या राज्यों की विधान सभाओं में हो, उसी के पैसे से आज यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है, हम सिर्फ उनकी बात करके और चिल्ला करके चले जाते हैं ।

यहां पर राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि at the end of the day, सरकार कुछ तो स्वीकार करे । मैं जानता हूं, बाहर लॉबी में सरकार सब कुछ स्वीकार करती है, लेकिन यहां पर बोलने में उसे तकलीफ होती है । आप इस सिस्टम को परिवर्तित कीजिए । सरकार या मंत्रीगण, जो लोग भी आज पब्लिक लाइफ में हैं, आप विश्वास कीजिए कि अगर हम सच्चाई कहते हैं तो लोग उसकी सराहना करते हैं । किसान आपकी फोटो लगाकर उसकी पूजा करेगा ।

मुझे दुःख से कहना पड़ेगा, मंत्री महोदय, अगर आज आपका जवाब मज़बूत न रहा, तो कल सुबह जब न्यूज़ आएगी कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, तब उसकी जवाबदेही आपकी होगी । हमारा संविधान कहता है, 'Every individual is the property of the State.' संविधान में हमने यह कसम खाई है कि एक आदमी को भी हम मरने नहीं देंगे। अगर एक भी आदमी की जान जाती है, तो वह संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होता है । इस पर आपको विचार करना चाहिए ।

सर, मैं कुछ प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा । पहली बात मैं इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहता हूं । अगर कहीं पर हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं पर लग जाते हैं, तो साथ के साथ इंश्योरेंस का चेक हमें मिल जाता है । लेकिन किसान तीन-तीन साल, चार-चार साल तक National Insurance Scheme में पैसा जमा करवाता है, उसको क्या मिलता है? मंत्री महोदय, आप ज़रा Life Insurance के Premier Institution से कह कर किसानों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को भी liberalize करवाइए। हम सोच रहे हैं कि इसके लिए हम बाहर से और कंपनीज़ लाकर लगाएंगे । आप Insurance policy के ऊपर पुनर्विचार कीजिए । किसान रोता रह जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है । बैंकों में वह इंस्टॉलमेंट का पैसा भरता रह जाता है, लेकिन उसके

बदले में उसे क्या मिलता है? पिछली बार भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जिन राज्यों में राज्य सरकारें किसान को Energy Sector में सब्सिडी दे रही हैं, उन राज्यों को केंद्र सरकार सपोर्ट करे। जो राज्य उनको सब्सिडी देते हैं, केंद्र सरकार उन राज्यों को 50% सपोर्ट अपनी तरफ से करे। किसानों के लिए एनर्जी फ्री की जाए।

आज मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा। यहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी भी बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। यूपीए की सरकार ने क्या किया, यह बात उन्होंने बताई। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are left with only one more minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, today, it has been allotted four hours. So, please allow me for ten minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. That is why you have been allotted only six minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: No, Sir. At least give me eight minutes. Please allow me, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only six minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Please do not say no. ...(*Interruptions*)... Everybody has spoken for a longer time. So, please allow me too. ...(*Interruptions*)...

**श्री भूपिंदर सिंह :** सर, यूपीए की सरकार ने बताया कि हमने ये ये काम किए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 60 साल में इस देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं। हम इस बात को स्वीकार करें कि देश में जब भी, जो भी सत्ता में आया है, उसने कुछ न कुछ किया ही है। लेकिन आज आपको जो मैंडेट मिला है, उसके लिए आपने कहा है कि हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे और इतने अच्छे दिन आएंगे, जितने आज तक कभी नहीं आए थे। वे अच्छे दिन क्या हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसान के लिए अच्छे दिन नहीं आए, तो देश के लिए अच्छे दिन आ ही नहीं सकते, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं।

सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा ऐक्ट लाएंगे कि अगर कोई Minimum Support Price से कम में distress sale करता हो, तो उसको जेल के अन्दर भेजा जाए और उसकी बेल भी न हो। आप ऐसा ऐक्ट क्यों नहीं ला रहे हैं ? तो मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हालांकि आज वे यहां पर नहीं हैं, अगर आप अच्छे दिन लाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के किसानों के चैम्पियन बनना चाहते हैं, उनकी रखवाली करना चाहते हैं तो bring a Bill. हर रोज़ आप कोई न कोई बिल ला रहे हैं, किसानों के लिए भी एक ऐसा ही बिल लाया जाए।

सर, मुझे कोई समझाए कि Minimum Support Price का क्या मतलब होता है? किसान को अगर Minimum Support Price से एक पैसा भी कम दिया गया, तो उसके लिए जेल होनी चाहिए और उसकी कोई बेल भी नहीं होनी चाहिए। आज ऐसी ही किसी व्यवस्था की जरूरत है।

[श्री भूपिंदर सिंह]

आज ओडिशा में किसान कॉटन के लिए परेशान हैं । आप जानते हैं कि ओडिशा में हुदहुद आया जिससे वहां के डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी, बालानगीर इत्यादि में खेती का बहुत नुकसान हुआ । वहां पर कॉटन पैदा करने वाले किसान परेशान हैं । आप चीन गए, प्रधान मंत्री ने चीन से क्या बात की, हमें नहीं मालूम, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि चीन ने हमारा कॉटन लेने से मना कर दिया? यहां पर long staples की जो कॉटन है, उसकी बात की जाती है । The best cotton growers are there in my district, that is, Kalahandi, which is a drought-prone area. Because of black soil,

ओडिशा में सबसे अच्छा कॉटन लॉग स्टेपल कॉटन होता है । एक किसान वहां जितना खर्चा करता है, उतना भी उसको नहीं मिलता है । मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर से कह रहा था कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पूरा कॉटन मेरे राज्य से खरीदे, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,050 है, उतने में कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी कपास खरीदने के लिए राजी नहीं है । वे किसान दिल्ली तक नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने हमें अपनी आवाज़ यहां आपके सामने रखने के लिए भेजा है । तो मंत्री महोदय, आप उनके लिए कम से कम कुछ तो दर्द दिखाइए ।

सर, इसके साथ ही, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज चाइना से जो इसे बंद कर दिया है, तो चीन के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट था? उसके अलावा वहां हुदहुद से नुकसान हुआ । ...(**समय की घंटी**)... यहां शरद पवार जी नहीं है । वे अभी हॉस्पिटल में हैं । I wish him कि वे जल्दी ठीक हों ।

**श्री उपसभापति** : Okay. Now, please conclude.

**श्री भूपिंदर सिंह** : सर, मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । सर, यूपीए सरकार में, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा ऐसे प्रांत हैं, जहां हम धान की उपज सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा चावल देते हैं । सर, हुदहुद के कारण आज धान का जो कलर चेंज हुआ ...(**समय की घंटी**)... उस कलर चेंज वाले धान को एफसीआई खरीदे । आप उसके लिए व्यवस्था कीजिए ।

**श्री उपसभापति** : हो गया ।

**श्री भूपिंदर सिंह** : सर, आज जो 300 रुपये की बात कही गई है, उनको बोनस देने की बात, वह बोनस आप उस सरकार को नहीं देना चाहते । लेकिन, कम से कम इनपुट सब्सिडी कॉटन ग्रोअर्स के लिए, मेज़ के लिए और जो किसान आज पीछे हो गया है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, you are also a farmer. You are having rubber plantations. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, we are proud of rubber cultivation in Kerala.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): How many acres of land do you have, Sir?

**4.00 P.M.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am having only one acre of rubber plantation.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, how many rubber trees do you have? ..(*Interruptions*)..

SHRI P. RAJEEVE: That is sufficient for your livelihood, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ..(*Interruptions*)... With whatever is available, I live happily. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, you are a marginal farmer. ..(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Correct. I am a marginal farmer.

**श्री भूपिंदर सिंह :** तो मार्जिनल फामर के लिए यह सरकार कुछ सोचे। ...(**समय की घंटी**)... मार्जिनल फार्मर को भी बचाने की कोशिश की जाए। उसके लिए जो उपाय है, इसको कैसे किया जाए? Sir, sense of the House will be with me. I appeal, let the Government come forward, rising above politics, above rajniti, एक मानवीय नीति, एक कृषि नीति। ...(**समय की घंटी**)... किसानों के लिए एक बिल लाइए ...(**व्यवधान**)... और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में खरीद करते हैं, ...(**व्यवधान**)... उनको जेल भेजने की व्यवस्था कीजिए। थैंक यू।

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Sir, I wish to place before you some of our serious concerns regarding the acute agrarian crisis and conditions of peasantry in the country and seek immediate steps for overcoming the bleak scenario. Sir, the decision to take this subject for discussion itself shows the seriousness of the issue. The unprecedented crisis has put farmers in acute distress and it is manifested in unfortunate escalation of farmer suicides. Sir, according to independent estimates, in Telangana alone, during the six months period preceding 26th November, over 430 farmers committed suicide. Vidarbha and Marathwada in Maharashtra have also reported an increase in farmer suicides, with over 120 farmers committing suicides in November alone. In West Bengal, there are reports of even paddy farmers committing suicide, which is unprecedented. Sir, the agrarian crisis has not spared any State. Even a State like Punjab has seen an increase in suicides due to indebtedness. The crash in prices of many major crops and absence of any price stabilisation effort or support mechanism is only likely to further worsen the situation. Now, this has extended to plantation sector in a serious way. We had a discussion about rubber yesterday.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair*]

Again, there is a notice for Short Duration Discussion on agrarian crisis. Sir, I know that plantation crops do not come under the Ministry of Agriculture. But, plantations like rubber, jute, tea, coffee, etc. should come under the Ministry of

[Shri K.N. Balagopal]

Agriculture. Mr. Minister, I am saying that plantation crops should also come under the Ministry of Agriculture. Presently, plantation crops are not under the Ministry of Agriculture. There is a serious crisis in rubber plantations. Same is the case with jute. We discussed about this in the last week. It is a very serious situation, Sir. The rubber farmers are losing about ₹13,000 crores per year. It is because we are producing 9 lakh tonnes of rubber every year. There is an average price fall of ₹150 per kilo. Just now our hon. Deputy Chairman was saying that 'I am a farmer of only 1 acre of rubber estate.' As per the estimate of Rubber Board, one acre rubber plantation will produce 700 kilo rubber annually. Based on the previous price, which means 700x240, its value was around ₹2 lakhs. But now the rubber price per kilo has been reduced by ₹150, which means a farmer with one acre of land is losing 1 lakh rupees every year. That means he cannot survive with the rubber farming. So, there is a serious situation about rubber, a serious situation about tea, about jute and also about all other plantation crops. That is why I am requesting the hon. Minister and the Government to also take the plantation sector under the Agriculture Ministry and give subsidies. Now many of the subsidies are not available for the plantation sector. That is why I am adding this point here.

Sir, the stated objective of the Government's price policy for agricultural produce is to ensure remunerative prices to the farmers for their produce and thereby to encourage higher investment and production. Here also, in reality, leave alone getting remunerative prices, the farmers are not even able to realize the cost of cultivation rendering agriculture unviable. Actually, no remunerative price is there.

Sir, we have the recommendations of the Swaminathan Commission. Prof. Swaminathan was a Member of this House. We know that he is an expert on agriculture sector. A Commission was appointed under his chairmanship. His recommendation was that 50 per cent over and above the cost of production should be given to the farmers as the base price. But, unfortunately, we are not giving it. Earlier, the UPA Government had come out with some formula of fixing the MSP. They used to increase the MSP by ₹50 per quintal annually for wheat and paddy. Now the NDA Government is also practising the same thing. They are also increasing MSP by ₹50 per quintal for wheat and paddy. So, both the UPA Government and the NDA Government are not supporting the interest of the farmers. This is the situation in the country. So, we have to change that habit.

Sir, now I come to another area, *i.e.*, the Ministry of Consumer Affairs. A new phenomenon has emerged after the Bali discussion and the discussion on the Trade Facilitation Agreement. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

has issued a letter to States – to all the States which are procuring the wheat, rice and other things – regarding change in policy of procurement for the Central pool. This direction will dismantle even the present weak public procurement as well as the price support system for Indian farmers. The letter clearly takes a position against States giving bonus over and above the Minimum Support Price. At present, the States like Kerala, Tamil Nadu, Andhra, even Bengal, and some other States like Punjab are giving some bonus to the farmers over and above the MSP. But as per the Central Government's direction, the Consumer Affairs Ministry is directing the State Governments not to give the extra bonus price to the farmers. This will affect the market and farmers in a serious way.

Sir, neo-liberal policies are the backbone of all these kind of policies. So, not only the agriculture in a particular area, but all areas are also affected because of these policies. Sir, take the case of sugarcane farmers. In majority of North India, sugarcane farmers are there. Sugarcane farmers in India are facing acute distress and thousands of crores of arrears are due from sugar mills to the poor famers. The U.P. farmers had a very big agitation recently. More than ₹4000 crores is the amount of arrears due to the farmers. This is as per the statistics published in a newspaper. The Government has doled out further benefits to the sugar lobby without any concrete action by them to clear the arrears. One statement says that it is 110 billion rupees. This is an astonishing figure. This is the amount which the Government has to give to the farmers Here also, the issue is related with providing Minimum Support Price to the sugarcane farmers.

Sir, jute farmers in India are also in dire straits as the Government policy of allowing plastic bags has sharply curtailed the demand for jute bags, and also the MSP is very low. There was a big agitation in the Session itself on this issue. That is why we witnessed a big agitation from MPs regarding the MSP given to jute farmers. Sir, another area that I wish to talk about is our cattle. This too comes under the Ministry. Thousands of cattle died in the States of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Maharashtra due to a suspected outbreak of the dreaded Foot-and-Mouth disease. Thousands of cattle in Tamil Nadu died due to the Foot-and-Mouth disease. It happened in Kerala and Karnataka too. A cow costs anywhere between ₹50,000 to ₹60,000 and in some cases, even one lakh rupees. Many of them are dying. There is no proper insurance policy in place. There is no policy to give monetary support or insurance to the farmers. This is an area that needs attention. Recently, we had the bird flu or the avian flu. It happened in Kerala. Earlier, when I spoke about Namakkal, our Tamil Nadu friends raised their voices saying that it was not Namakkal. But now it has been found that Namakkal is also affected. I am for protecting the interest of the farmers. Now, the avian flu is affecting the birds, but there is no insurance mechanism

[Shri K.N. Balagopal]

and no mechanism with the Agriculture Ministry to protect them. This aspect also needs to be considered.

Sir, I would make just one or two points more. Giving the MSP, avoiding the middlemen and constructing more godowns, especially refrigerated godowns, are very important for protecting the farmers' interest. Sir, an alteration in the situation of persistent agrarian crisis is possible only if the farmers are assured of truly fair and remunerative prices. Immediate steps to reign in cost of output and provide them at subsidized rates are also necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Balagopal.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, I would speak just two-three lines more.

Sir, input prices must be regulated and fertilizer prices must be frozen at pre-nutrient-based subsidy. Increase in fertilizers prices is a very serious issue. There, we need to give some subsidy.

Sir, a comprehensive social security scheme for agricultural workers and strengthening of the MNREGA is also required. Free Trade Agreements and trade liberalization measures must not be implemented. Dumping of cheap agricultural produce from other countries must be disallowed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Balagopal.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, this is an important point. I would be stopping with this sentence.

All trade negotiations must be transparent and the Parliament as well the States must be taken into confidence. Even yesterday we had put a question to the hon. Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, about the latest trade agreements. We are in the dark about the trade agreements. So, there were trade agreements about import policies and now, a Free Trade Agreement with the European Union is coming.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Just make the point.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, all this must be informed and discussed in the Parliament.

I have put forth my points. I thank you for giving me one minute additional time. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Balagopal. Now, Shrimati Gundu Sudharani.

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI (Telangana): Sir, we are an agrarian country and more than 60 per cent of our people depend on agriculture and its allied activities. This is not for the first time that we are discussing about the issue relating to farmers. We have been, almost in every Session of the House, discussing agriculture in one form or the other. This shows the significance and importance that we attach to our farming and farmers to address their problems.

Since I have limited time, let me concentrate my observations to the State of Telangana. We are a new born baby of Mother India and we are one of the unfortunate States where in spite of having the Jeeva Nadulu of Krishna and Godavari, the State is facing agrarian crisis year-after-year, resulting in suicides by farmers in large numbers. The reasons for agrarian crisis are many, but the main reasons are low rainfall, poorly irrigated regions, consistent failure of the Government to supply power to farmers for at least seven hours a day, non-availability of seeds and fertilizers in time and increase of debt burden on farmers.

Sir, I would cite one or two examples which would make it clear where we stand. If you look at the gross irrigated area, it stood at 32 lakh hectares in 2013-14 and the net irrigated area was 22 lakh hectares during the same period. So, there is a gap of 10 lakh hectares. As farmers of Telangana are dependent on rainfall for irrigation, and with this year's not so encouraging rainfall, as usual, farmers depended on borewells for water. That too failed due to failure of the Telangana State Government to supply power. This results in nearly 600 suicides by farmers in the State. In Telangana, in the Chief Minister's constituency, there were 98 suicides. The Government of India, to address this kind of problems in States like Telangana, Rajasthan, Maharashtra, etc., constituted a Task Force under the Chairmanship of Shri Nara Chandrababu Naidu on Micro Irrigation which submitted its Report in 2004 after a thorough and detailed study of Israel and other models for optimum utilisation of water through micro irrigation. The Task Force identified 70 million hectares of potential area to bring under micro irrigation. But, so far, we have not achieved even 5 million hectares of potential area even after 10 years of implementation of the Report. So, I request the hon. Minister to implement this report in all districts of Telangana and in other States.

The second part of agrarian crisis is due to non-availability of remunerative prices. Farmer, after passing through the above phases, produces something, be it paddy or cotton or maize or anything. When he brings his produce to market, he is not getting the MSP. For example, cotton is extensively produced in Warangal, Nalgonda, Karimnagar, Khammam and Adilabad districts. This year there is a good crop. But the Government is not giving farmers remunerative price. The Government has fixed

[Shrimati Gundu Sudharani]

₹4,050 as MSP for Grade-1 cotton, but I can say with full sense of responsibility that no farmer in my State has got more than ₹3,700. Secondly, the CCI has been requested to open up more and more centres, but not enough centres have been opened. Coupled with this, the decision of Chinese Government to substantially reduce cotton imports from India has fallen on farmers like a bolt from the blue. So, all that I want is that the Government should implement the recommendations made by Swaminathan Commission that MSP should be fixed at the cost price plus 50 per cent.

Sir, agricultural credit is one more reason behind the agrarian crisis in Telangana. There is no doubt that agricultural credit in Telangana has gone up to ₹39,619 crores in 2013-14. But the situation on the ground is different. The present Government has promised in its manifesto that it will waive off all the loans taken by farmers up to ₹1 lakh. With this, only ₹11,200 crores agricultural credit is going to be waived. The State Government has dragged implementation of its promise, which has resulted in banks refusing to give fresh loans for new crops. This has really cornered the farmers and they have left with no other option but to go to moneylenders to take loan at exorbitant rate. When they failed to repay loan and when pressure mounted from moneylenders, many farmers committed suicide. They are having small holdings of 2 or 3 acres and there are also leaseholders who have committed suicide.

Sir, one thing I want to say. भारत देश में किसान को अन्नदाता मानते हैं। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि तेलंगाना में अन्नदाता को ही खाने के लिए अन्न की कमी है।

So, I urge the hon. Minister to kindly pay more attention to Telangana which is really in need of your financial and other help to save it from the current agrarian crisis. Thank you.

**डा. अशोक एस. गांगुली** (नाम-निर्देशित) : सर, हिन्दी भाषी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि बंगाल का होने के नाते मैं हिन्दी में बोलूं तो दो-चार प्वाइंट मिस हो जाएंगे। उसके लिए आप माफ कीजिएगा। मैं अंग्रेजी में जरा दो-चार बातें करना चाहता हूं।

Hon. Vice-Chairman, Sir, and hon. Minister, agriculture is the biggest Indian story, but it faces some natural and technological crisis. And I want to spend two or three minutes in enumerating some of the issues. The farmers of India are the invisible defenders of this nation. We never look at them as the defenders of this nation. We must look after their interests because that is the way we can look after our own interests. The farmers include not only the land owners; farmers are also the farm labourers, whose numbers are far more large. I belong to Maharashtra and it is a very sad case that out of the 301 farmers, who have committed suicide this year, the

highest number is from Maharashtra, that is, 204. Sir, 124 farmers have committed suicide in Marathwada and Vidharbha in November alone. The Chief Minister, Mr. Fadnavis, has notified a drought-like condition in 19,000 villages in Maharashtra out of the total 39,000 villages.

Now, the points I want to make are very simple. First of all, I don't think that Minimum Support Price is a favour to the farmers. It is their legitimate due, and we must never treat it as a favour being done to the farmers by increasing and showing them that we are doing some favour to them.

The second thing, that I wish to point out, is that the Agriculture Produce Marketing Corporations are possibly one of the biggest stumbling blocks for the producers of fruit and vegetables. India is the second largest producer of fruit and vegetables in the world. Yet, because of the absence of cold-storage and cold-chain, 40 million tonnes of fruit and vegetables are wasted every year through spoilage. And, there is a great political debate whether we should allow Foreign Direct Investment or not. I am neither for nor against Foreign Direct Investment. I request the hon. Minister of Agriculture, through you, Sir, to please go and look at the data of FDI on the ground in three countries. Look at the data of FDI on the ground in China, Indonesia and Malaysia, where none of the small traders have been affected due to FDI. As a matter of fact, business has gone up as a result of organised trade, whether domestic or foreign, making investment in collection, distribution and storage.

Sir, the biggest challenge that we are facing today is the uncertainty of climate change and global warming. Therefore, one of the major issues that all our farmer friends must know is that ISRO weather satellites are providing micro-area short-term forecast to the farmers in order to overcome the uncertainties of the weather. Sir, through you, I request the Agriculture Minister to kindly encourage and invest more in short-term weather forecasting, which is going to be far more important to the farmers than even some of the chemicals or fertilizers and hybrid seeds in some cases because if you cannot sow on time and if you cannot reap in time, everything else falls by the wayside.

Finally, I wish to say that one of the biggest dangers facing India is the rapidly-depleting ground water table and the poisoning of the ground water. Technology for rejuvenation of ground water, whether in Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka or in Tamil Nadu, requires major investment. I request the hon. Minister of Agriculture to kindly look at this very serious issue. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Dr. K.P. Ramalingam to speak in Tamil.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, at present, there is a deep agrarian crisis in our country. We discuss this issue every year in this august House, but we have not yet devised a definite plan for its solution. This is a very deep crisis. To earn money, there are thousands and thousands of industries in our nation, but to earn food, the only way is agriculture. But, now, the agriculture is in deep crisis.

Sir, I would like to speak from my heart. So, I would like to speak in my mother-tongue – Tamil.

*Hon'ble Vice Chairman Sir,

"What is the resource that is lacking in this country,
Why should we solicit abroad,"

This axiom suits more to the agricultural sector than to any other sector in our country. What are the necessities for agriculture? Land, water, fertilizer, and proper procurement price for the harvest produced are the need of the time. In our country, cultivable land is present in abundance. There is no shortage of agricultural land. Some agricultural land is being used to build concrete buildings and industries. This is one side of the scenario. For fertile agricultural land, organic manure is sufficient. If we pay proper attention to animal husbandry, we can get sufficient manure. We should establish a new institution to be known as—Indian Council of Veterinary Research' (ICVR) in the lines of Indian council of Agricultural Research (ICAR). Through this ICVR, we should enhance the development of animal husbandry. The department of animal husbandry has to be modernized. The country is facing severe crisis with respect to fertilizers. The issues with regard to shortage of fertilizers and urea have been discussed in this House.

Now the country is going towards micro irrigation, which needs liquid fertilizers. We have to import liquid fertilizers from abroad. But subsidy is not given to imported liquid fertilizers. More facilities and subsidies have to be given for the production of liquid fertilizers in India. Efforts have to be made to produce liquid fertilizers indigenously.

The greatest factor which causes agrarian crisis in our country is water shortage. How should we find solution to this crisis? There are hundreds of rivers in India. That is why I said that no resource is lacking in our country. We have many rivers such as Indus, Ganga, Brahmaputra, Narmada, Mahanadhi, Krishna, Cauvery, Godavari, Penaar, Vaigai, Tamiraparani, Neyaaru etc. We consider rivers as our mothers India has

* English translation of the original speech made in Tamil.

two and a half lakh square kilometer of cultivable land. But only 20% of this land is utilized now. That is, we are utilizing only 360.94 lakhs hectares of irrigated land.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

DR. K.P. RAMALINGAM: Sir, I need five minutes more. Our AIADMK friend has given four minutes. Mr. Ganguly has given four minutes. Those eight minutes I am going to take.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please take one minute more.

DR. K.P. RAMALINGAM: No, no, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): He completed before time. ...(*Interruptions*)...

DR. K.P. RAMALINGAM : Yes, yes. That is what I said. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN: Please do not waste your time.

DR. K.P. RAMALINGAM: *The northern and eastern parts of our country are affected by flood regularly. The southern and western parts of our country are affected by drought regularly. It has become a routine for us to watch this situation. We are giving relief to drought affected areas. We are giving relief to flood affected areas. My Hon'ble colleagues discussed about the issues with regard to Andhra Pradesh and Odisha. They have asked for more allocation. When we consider all these issues, we should think about interlinking of rivers.

80% of water in our rivers is wasted. The only solution to this problem is interlinking of rivers. “Impossible is the word only to be found in the dictionary of fools.” Possibility is the sanctity of human kind. I would like to reiterate that impossibility is the argument of fools and that possibility is the sanctity of human kind.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) : Is it a poetry festival?

DR. K.P. RAMALINGAM:* We should not forget the fact that China got promissory notes from the people to build Grand Canal. Rivers were interlinked in the United States of America between the states of California and Texas. The gigantic Canals of Volga and Kubr were interlinked in Russia. King Frederick I of Germany interlinked three rivers - Elbe, Oder and Weser by canal, in the eighteenth century itself. Earlier interlinking of these rivers was considered impossible. Therefore, in our country also, if there is a will there will be a way. Mere impersonation is not enough. During the time of general elections, many people impersonate as farmers. Impersonating as a farmer is not enough. One has to live as a farmer.

---

* English translation of the original speech made in Tamil.

[Dr. K.P. Ramalingam]

We have sought the help of foreigners for commercial benefits like running of bullet trains. It is said that our country get loans to the extent of one lakh crore or two lakh crore for implementing the projects of bullet rains. Instead, we can seek their assistance for interlinking of rivers. We can get loans to the extent of many lakhs of crores from foreign countries to interlink rivers. It will enhance the development of the country, by achieving self-sufficiency in food. During the last General Elections to Lok Sabha, the crown of Prime Ministership of India was vacant. The incumbent Prime Minister has achieved that crown due to his rhetoric and many grandiloquent electoral promises. The electoral promises should not be mere promises. They have to be implemented. With these words, I conclude my speech. Thank you.

**श्री दिग्विजय सिंह** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने, आज इस देश में किसानों के जो हालात हैं, उन हालातों के बारे में चर्चा करने के लिए समय प्रदान किया । मैं सदन के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं । किसी सरकार की कार्यप्रणाली उसकी नीति, नियम और कानून तथा व्यवहार की वजह से जानी जाती है । 60 के दशक के पहले सारे अंतराष्ट्रीय क्षेत्र के लोग यह कहते थे कि जिस तेजी से भारत की आबादी बढ़ रही है, उसमें भारत के लोग भूखों मरेंगे, यहां अकाल आएगा, लेकिन 60 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी के समय में हरित क्रांति लायी गयी, उसकी वजह से आज हम उस हालात में हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, self sufficient हैं । सर, 2004 से लेकर 2014 के बीच में अगर यूपीए सरकार के दस साल का मूल्यांकन किया जाए तो पहली बार देश में शहरी क्षेत्र के बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति बढ़ी है । साथ ही अगर आप न्यूनतम मूल्य लें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें तो केवल गेहूं पर 55 प्रतिशत बढ़ी, मोटे अनाज पर 81 प्रतिशत बढ़ी, धान पर 75 प्रतिशत बढ़ी । अगर आप बैंक क्रेडिट को लें तो बैंक क्रेडिट में किसानों के लिए 700 प्रतिशत इजाफा हुआ । 72000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप पता लगाएं तो उस क्षेत्र में लगभग 18 प्रतिशत से ज्यादा खरीद मोटरसाइकिल की हुई और 22 प्रतिशत बढ़ोतरी ट्रैक्टर्स की हुई । आप देखेंगे कि एग्रीकल्वर जीडीपी ग्रोथ एनडीए के मुकाबले यूपीए सरकार में कहीं ज्यादा रही है । इसी के साथ-साथ पोस्ट हारवेस्ट जो क्रॉप आती रही, उसकी वेयरहाउसिंग की व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई ताकि उस रिसीट के आधार पर किसानों को कर्जा मिल सके । उससे किसानों को बेहतर खरीद करने का अवसर मिला और distress sale से हम लोग उन्हें मुक्ति दिला पाए ।

मैं आज एनडीए सरकार की हालत की तुलना करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी, जो आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तुलना की है, उससे कहीं कम कीमत में किसानों को आज बेचना पड़ रहा है, distress sale हो रही है । मक्का की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1,310 रुपये क्विंटल है, लेकिन मक्का 1,000, 1,100, 1,200 रुपये क्विंटल में बिक रही है । चने का 3,100 रुपये क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और बाजार में 2,500 से 2,800 रुपये क्विंटल का भाव है । उड़द का 4,300 रुपये क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और मार्केट में 3,800 से 4,000 रुपये क्विंटल में उड़द की दाल बिक रही है । सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बोई जाती है, एनडीए की सरकार आने से पहले सोयाबीन की कीमत 3,500 से 3,800 रुपये क्विंटल थी, आज वह घटकर 2,200 से

2,400 रुपये क्विंटल हो गई है । कपास की कीमत जहां 4,000 रुपये क्विंटल हुआ करती थी, आज 2,500 से 2,600 रुपये क्विंटल पर आ गई है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, किसान के सामान के भाव बाजार में कम हो गए लेकिन उपभोक्ता के भाव कम नहीं हुए । कपास सस्ता हो गया, कपड़ा सस्ता नहीं हुआ । धान सस्ता हो गया, चावल सस्ता नहीं हुआ । तिलहन सस्ता हो गया, तेल सस्ता नहीं हुआ । आखिर किसको लाभ हुआ ? लाभ हुआ प्रोसेसर को, व्यवसायी को । माननीय मंत्री जी, आप स्वयं किसान हैं । आप बिहार के बारे में पता लगा लीजिए किस रेट में आज किसानों को मजबूरी में धान बेचना पड़ रहा है । आज 900 से 1000 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है । पहले राइस मिल्स को 65 प्रतिशत लेवी देनी पड़ती थी, मेरे पास जो आदेश है, उसमें तो 65 प्रतिशत ही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब प्रो. राम गोपाल यादव जी ने बताया कि अब इसके आदेश केवल 25 प्रतिशत खरीद के हो गए हैं । स्वाभाविक है कि जब लेवी का प्रतिशत घटेगा, तो धान के भाव भी कम होंगे । आप किसी भी राज्य में पता लगा लीजिए धान के भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं नीचे हैं । इसमें किसकी जबावदारी है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने, मेरे समय से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा हमने बोनस देने का फैसला किया था । केंद्र सरकार ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो एग्रिकल्चरल प्राइस कमीशन ने रिपोर्ट दी, उससे आगे बढ़कर कीमत दी, लेकिन हमें यह जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जो राज्य बोनस देगा, वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपरेशन नहीं होगा, मार्केट परचेज नहीं होगा । यह अपने आप में जो हमारे देश का एक संघीय ढांचा है, उसके साथ कुठाराघात है । अगर राज्य सरकार अपने बजट से किसी को बोनस देना चाहती है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं उस व्यवस्था को नकारने वाले? माननीय मंत्री जी, मैं इस बारे में आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो राज्य आज अपने बजट से धान पर बोनस देना चाहता है, तो आप किस कानून के अंतर्गत उनको रोक रहे हैं? किस कानून के अंतर्गत आपने मार्केटिंग आपरेशन्स नहीं करने की धौंस-धपट दी है? माननीय मंत्री महोदय, इस धौंस-धपट से सरकार नहीं चल सकती है । महोदय, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने इस बार जैसा कि त्यागी जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो घोषणा की है, गेहूं के आपने 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए है । आपने केवल तीन प्रतिशत बढ़ाया है जबकि फर्टिलाइजर के भाव यथावत हैं और यही नहीं किसानों को खाद खरीदने में भयंकर दिक्कत आ रही है । आप किसी भी राज्य में पता लगा लीजिए, खाद की जितनी आवश्यकता किसानों को है, किसानों को मजबूरी में, कालाबाजारी में खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है । आप चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए । क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आप कैमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करके, समय पर खाद उपलब्ध करवाएं? उपसभाध्यक्ष जी, आप समझते हैं कि खेती की अगर समय पर बुवाई नहीं होगी, सही समय पर खाद नहीं मिलेगा, सही समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो फसल कैसे पैदा होगी? मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है और विशेष तौर पर आपको कैमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और एडवांस स्टॉकिंग होनी चाहिए । जब मैं मुख्यमंत्री था, तब हम एडवांस स्टॉकिंग करते थे । एडवांस स्टॉकिंग करने के लिए जो इंटरेस्ट बीयर करना पड़ता था, तो राज्य सरकार अपने बजट से करती थी । मेरे दस साल के कार्यकाल में एक बार भी कालाबाजारी की शिकायत नहीं आई, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आई, उन्होंने उसको खुला कर दिया और आज खुलेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है । मैं समझता हूं कि अनेक प्रांतों में कालाबाजारी की शिकायत है ।

[श्री दिग्विजय सिंह]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी के साथ-साथ किसानों के हित में हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी लाए । जैसा कि त्यागी जी बता रहे थे कि सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि हमारा एजेंडा लागू कर दिया । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन करने का आपने जो वायदा कॉरपोरेट सेक्टर को चुनाव के समय किया हुआ है, क्या आप उसे निभाएंगे, या किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उसका विरोध करेंगे ? माननीय मंत्री जी, आपको अपने जवाब में इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ।

मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस बारे में विचार करें कि आखिर किसानों के हित में आप क्या करना चाहते हैं? किसानों के हालात को प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस योजना बनाई, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस का जो इम्पलिमेंटेशन है, जो उसका क्रियान्यवन है, उसमें काफी दिक्कत है । उदाहरण के लिए पिछले साल मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल खराब हुई थी, तो क्रॉप इंश्योरेंस बुवाई से पहले मिल जाना चाहिए था । यानी कि अक्टूबर 2013 में जो फसल खराब हुई, उसका रिकार्ड इंश्योरेंस कम्पनी के पास आ गया, तो उसके क्रेडिट का लाभ अगर 2014 की बुवाई से पहले किसानों को नहीं मिलेगा, तो वह खाद और बीज कहां से लेगा? इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस के क्रियान्वयन के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको अगले साल की बुवाई से पहले ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Your party has got three more speakers. How much more time will you take?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, if you don't want, I can sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): You please speak. Just tell me how much more time do you want?

**श्री दिग्विजय सिंह** : Sir, give me, at least, ten minutes more. मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस के मसले पर माननीय कृषि मंत्री जी, आप मुझ से सहमत होंगे कि इसके क्रियान्वयन के ऊपर आपको विचार करना चाहिए, ताकि फसल खराब होने के बाद अगर अगली फसल की बुवाई से पहले उसको क्रेडिट का लाभ मिल जाना चाहिए, ताकि उसको खाद और बीज खरीदने में आसानी हो जाए । मैं हमेशा आर्गेनिक फार्मिंग का पक्षधर रहा हूं । मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को तरज़ीह दी थी । फर्टिलाइजर की जो बढ़ती कीमतें हैं, बीज और पेस्टिसाइड्स की जो बढ़ती कीमतें हैं, उस परिप्रेक्ष्य में यदि आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान नहीं दिया तो किसानों के हालात सुधर नहीं सकते हैं । आज किन कारणों से सुसाइड्स हो रहे हैं? इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है । हम उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, हालांकि अकेले मध्य प्रदेश में पिछले दस सालों में सत्रह हजार से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन उनके कारण क्या हैं? माननीय उपसभाध्यक्ष जी, उसका मूल कारण नंबर एक, गिरता हुआ जल स्तर, depleting ground water है । उन्होंने ट्यूबवेल में इन्वेस्टमेंट किया, सूख गया, दूसरा कारण क्रेडिट की कमी है । क्रेडिट की कमी की वजह से उसको बाजार से दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत पर कर्जा लेना पड़ता है, जो कि 24, 36 प्रतिशत तक हो जाता है, क्योंकि किसानों की bank credit choke हो चुकी है । इसका तीसरा

कारण poor crop selection है । चौथा कारण, जिस तरह से लोगों को genetically-modified seed दी जाती है, उनसे आकर्षक वादे करके, उसके अंदर गलत तरीके का बीज प्रॉड्यूस किया जाता है, उसकी वजह से भी आत्महत्याएं हुई हैं । इसके साथ-साथ ही आपको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, एग्रीकलचर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है । मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं । मध्य प्रदेश में यह एक आश्चर्य की बात है कि जहां देश की जीडीपी ग्रोथ 3 परसेंट है, वहीं मध्य प्रदेश में 2011-12 में 24.9 per cent growth in agricultural sector. Is it possible? असंभव! उसी के साथ-साथ 2012-13 में 20 परसेंट, 2013-14 में 19.8 परसेंट है । एक तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ 20 परसेंट अब है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार केंद्र सरकार से ओला पीड़ितों के लिए, सूखे के लिए पैसे मांग रही है । उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के * का काम करने की उस्तादी किसी के पास है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच है । माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज आवश्यकता इस बात की है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वालिटी सीड्स और seedlings (नर्सरी) में बराबर रेग्युलेशन होना चाहिए । सीड्स सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ पर पूरा ध्यान देना चाहिए । क्वालिटी सीड्स के लिए कहूं तो अगर होर्टिकल्चर के लिए क्वालिटी सीडलिंग्स नहीं मिलेंगी, तो आगे मदद नहीं हो पाएगी । मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं ।

इसके साथ ही agricultural extension बहुत जरूरी है । टेक्नोलॉजी के माध्यम से agricultural extension हो रहा है, लेकिन साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि फार्मर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और सक्रय रूप से और बढ़ाने की जरूरत है । भारतीय जनता पार्टी से हमारे मंत्री जी मौजूद हैं । उन्होंने अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में कहा था कि हम इसको उद्योग का दर्जा देंगे और जितनी भी लागत है, हम उसका पचास प्रतिशत प्रॉफिट देंगे । माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इन्होंने सात महीने में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिससे यह महसूस हो सके कि आपने ऐसा किसी भी तरह का कोई निर्णय ले लिया है, जिससे यह लगे कि आप लोग लागत का पचास प्रतिशत व्यवस्थित करेंगे । अगर आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन में ही उसी के माध्यम से भाव तय करते तो इसमें मदद मिल सकती थी ।

इसी तरह से जेनेटिकली मोडिफाइड सीड के बारे में है । स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ उसका विरोध करता रहा है । आप लोगों ने इस बारे में जो कमेटी बनाई, उसको फील्ड ट्रायल्स के लिए एप्रूवल दिया गया है । भारतीय किसान संघ ने आपका विरोध किया है और कहा है कि इस सरकार ने हमारे साथ * किया है । अगर आप ही का संगठन, आरएसएस का संगठन, भारतीय किसान संघ आज आपसे यह कह रहा है कि आपने उनकी भावनाओं के साथ * किया है, तो आप समझ सकते हैं आज भारत के किसान आपके बारे में क्या सोचते हैं? मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... मेघराज जी, आप बैठ जाएं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज पूरे देश में मोदी जी की पहचान किसके साथ है? व्यापारी के साथ, व्यवसायी के साथ, कारपोरेट के साथ । अगर 7 महीने में किसी को लाभ पहुँचा है, तो किसानों का तो नुकसान हुआ है, लेकिन व्यवसायी और व्यापारी को लाभ हुआ है । मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी कथनी और करनी में अन्तर रहा है, जनता इस बात को देख रही है और मेरे भाई ने अभी जो कहा था कि राजा व्यापारी, तो जनता भिखारी । धन्यवाद ।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

**डा. सत्यनारायण जटिया** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हम किसान की तकलीफों के बारे में चर्चा कर रहे हैं । कुदरत ने उसको जिंदा रहने का जो मौका दिया है, उसमें वह मरना क्यों चाहता है? इसलिए बाकी बातों पर ध्यान न देते हुए यदि हमने उसकी बेहतरी पर ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से उसके प्रति न्याय होगा । किसानों का दर्द ऐसा है कि

"जब आवाज दे रहा हो दर-दर,
हम यहां पर राजनीति करते रहे,
तो जमाना क्या कहेगा?
इसलिए इधर-उधर की बात मत कर,
बता कि कारवां क्यों लुटा?
हमें रहजनों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है ।
क्या कमाल है?"

सबने अच्छा काम किया, फिर आदमी क्यों मर रहा है? इंसान की जिंदगी से बढ़ कर कोई नियामत नहीं हो सकती । वह जिंदा रहना चाहता है । खेती-किसानी पर हमारे देश का प्रमुख आधार है । एक समय था, जब कहा करते थे कि

"उत्तम खेती, मध्यम बान,
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ।"

एक जमाना था, क्योंकि साफ-सुथरा काम था । जितनी मेहनत, उतना परिणाम । इसमें इधर-उधर का कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं । साफ काम होता था, परंतु समय के साथ-साथ हमने कहा कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये किसान क्यों मर रहे हैं? इसलिए इन सारी बातों पर जाया जाए, तो मेरे पास जो आँकड़े उपलब्ध हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आदमी का मरना जारी है और उसके कारण हमारी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। किसान का मरना कोई साधारण बात नहीं है । जितनी सुसाइड हो रही है, आत्महत्याएँ हो रही हैं, 2002-03 से मुझे उसके आँकड़े मिले हैं । 2002-03 में 17,971, 2003-04 में 17,164, 2004-05 में 18,241, 2005-06 में 17,131, 2006-07 में 17,060, फिर 2007-08 में 16,632, 2008-09 में 16,196, 2009-10 में 17,368, 2010-11 में 15,964, 2011-12 में 14,027 और 2012-13 में 13,754. ये आंकड़े लगातार हजारों में रहे हैं । इसका मुख्य कारण जो बताया जाता है, हि यह है कि किसान इस उम्मीद में कर्जा ले लेता है कि अच्छी फसल आएगी और वह उस कर्जे को चुका देगा । 'खाद, बीज, बिजली और पानी - इनकी हो रही परेशानी' । किसानों के लिए कुछ पंचवर्षीय योजनाओं तक तो हमने सिंचाई पर ध्यान दिया और बाद में हमको उसके परिणाम भी मिले । किसान कर्ज लेकर चुका नहीं पाता था और नहीं चुका पाने की वजह से उसके साथ, उसके परिवार के साथ तरह-तरह तकाज़े होते थे, जिसके कारण उसको मृत्यु का आह्वान करना पड़ता था और वह मर जाता था । यह ठीक नहीं है । भगवान ने इन्सान को इसलिए पैदा नहीं किया है कि वह मेहनत करे, परिश्रम करे और मर जाए । God didn't create man to be miserable, hungry and die in the midst of plenty, which is the result of his own labour. मेहनत का परिणाम मौत नहीं होना

चाहिए । मेहनत का परिणाम यदि मौत है, तो फिर हम कहां रह रहे हैं? हम जिस आज़ादी की बात करते थे, उस आज़ादी को कामयाब करने के लिए, सार्थक करने के लिए हम कौन से प्रयास करने वाले हैं? मैने अभी आपको किसानों की मौत के हर वर्ष के आंकड़े बताए, उसमें पिछले कुछ सालों कोई बहुत ज्यादा कमी या बढ़ोतरी नहीं आई है । अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आपकी सारी योजनाएं क्या कर रही हैं? आपकी सारी सुविधाएं क्या कर रही है?

अभी हमारे पूर्ववक्ता अपनी बात को कह कर यहां से चले गए, उनको पूरी बात सुननी चाहिए थी । उन्होंने बताया कि हमने यह किया, वह किया । हम कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है, किन्तु दूसरे लोग भी तो कुछ कर रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने का काम यदि किसी ने किया है, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने किया है । किसानों को बिजली का साल में एकबारगी भुगतान करने की जगह दोबारगी, दो हिस्सों में करने की सुविधा दी गई । 1200 रुपये प्रति हॉर्स पावर बिजली देने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह सरकार ने किया है । निश्चित रूप से किसानों को वहां पर सहूलियतें और रियायतें दी जा रही हैं ।

सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने अद्‌भुत काम किया है । हमने सिंचाई की क्षमता बढ़ाई है । इतना ही नहीं **Inter-basin water transfer** के तहत रिवर्स को जोड़ने का हमने पहला सफल प्रयोग किया है । नर्मदा, जो अरब सागर में जाती है, वहां से पानी को प्रायः 1100 फीट उठा करके, हमने उसे क्षिप्रा में मिलाने का काम किया है । उसका पहला फेज़ सफल रूप में पूर्ण हो चुका है और नर्मदा और क्षिप्रा का पानी मिल गया है । मालवा में जो सूखा पड़ता है, परेशानी होती है, हमने उससे बचाव करने का एक रक्षात्मक उपाय कर लिया है। 'नर्मदा-क्षिप्रा जोड़ो' योजना को साकार करने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने किया है । मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है, वह और भी तेजी से होना चाहिए ।

जीडीपी के बारे में कहा गया है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये गलत आंकड़े हैं । अरे भाई, यह सरकार तो अभी-अभी आई है, इससे पहले तो आपकी सरकार ही थी । उस समय, आपकी सरकार के अधिकारियों ने वहां पर जो कुछ देखा होगा, परखा होगा, उसी आधार पर ही तो यह आंकड़ों का खेल हुआ होगा । इन सारी बातों पर आलोचना करने के बजाए अगर कहीं अच्छा काम हुआ है, तो उसके बारे निश्चित रूप से हमें अच्छा बोलने की आदत भी होनी चाहिए । ये सारे काम जो हो रहे हैं, इन कामों को करने के लिए जो-जो उपाय किए जाने चाहिए, हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा । कृषि के कामों से लोग हट रहे हैं । वे इसलिए हट रहे हैं कि खेती-किसानी का जो रकबा है, वह परिवारों में बँटवारे के बाद कम रह जाता है । आज से 50 साल पहले यदि किसी परिवार के पास कोई रकबा 50 एकड़ का रहा होगा, तो दो पीढ़ियां आने के बाद, यदि हम दो बच्चों का ही अनुमान लगा लें, तो वह रकबा गुजारे लायक नहीं रहता है । उससे किसानी-खेती पर निर्भर नहीं रहा जा सकता । गांव में रोजगार के आज और कोई अवसर नहीं हैं । एक समय था, जब छोटे-छोटे कौशल के आधार पर कारीगर अपना गुजारा कर लिया करते थे । बढ़ई को अपना काम मिल जाता था, लोहार को अपना काम मिल जाता था, कुम्भकार को अपना काम मिल जाता था और सुनार को अपना काम मिल जाता था । इस प्रकार से छोटे-छोटे कामों पर गुजारा करने वाले लोगों का गुजारा गांव की अपनी अंतरिम व्यवस्था से ही हो जाया करता था । जितना मिलता था, उसमें लोग संतुष्ट हो जाया करते थे । चूँकि आज परिवारों में खेती का रकबा कम होने के

[डा. सत्यनारायण जटिया]

**5.00 P.M.**

कारण उसके परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है, तो उसमें से कुछ सदस्य निकल कर शहरों में आ गये। जब वे शहरों में आ गये, तो शहरों में रहने की वैसी व्यवस्था नहीं है। वे ऐसी जगहों पर रहते हैं, जहां पर सफाई नहीं है, जहां पर रहने की गुंजाइश नहीं है और हाइजिनिक कंडिशंस नहीं हैं। वह आदमी गांव से चल कर शहर में आता है, तो एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। परन्तु उसके साथ होता क्या है? उसको बीमारी का शिकार होना पड़ता है, उसे परेशानी का शिकार होना पड़ता है और उसके रोजगार भी पक्के नहीं हुआ करते हैं। इसलिए, एक बहुत बड़ी आबादी किसानी से, खेती से शिफ्ट हो रही है और मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी खेती करने वाले लोग कम हो रहे हैं और मजदूरी करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इसके कारण भी निश्चित रूप से इन सारे कामों में गांव और शहरों में इम्बैलेंस हो गया है। अब फिर कहा गया है कि उसको खेती के सारे उत्पादों का मूल्य बराबर मिलना चाहिए, वह मिलना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि उसके उत्पादन की कीमत से, लागत की कीमत से उसको 50 परसेंट ज्यादा लाभ देना चाहिए। अब उसे लागत की कीमत से 50 परसेंट ज्यादा देना चाहिए, तो यह देगा कौन? सारे कमिशंस बैठ गए, सारी बातें हो गईं, परन्तु उसको वह नहीं मिल रहा है। इसके कारण...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Your party has got two more speakers.

**डा. सत्यनारायण जटिया** : ठीक है, सर। मैं अपनी बात कन्क्लूड कर लूँगा। मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस पर ज्यादा लोग बोलें, तो बहुत अच्छा होगा।

सर, मुझे यह कहना है कि इन सारी बातों का लब्बोलुआब एक ही है, सार एक ही है कि आदमी मरना नहीं चाहता, आदमी जीना चाहता है और उसके जीने के लिए जीने लायक परिस्थितियां बनाइए। जो लोग कृषि के उद्योग से—अभी इसे उद्योग का दर्जा नहीं मिला है। वैसे मेरे पास आस्ट्रेलिया के और अन्य देशों की रिपोटर्स हैं, जिनमें यह कहा गया है कि कृषि में जिस प्रकार से हमें इरिगेशन को महत्व देना चाहिए, उतना महत्व नहीं देने के कारण बहुत सी समस्याएँ पैदा हो रही हैं और रोजगार के अवसर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं चाहूँगा कि कृषि में जो लोग रोजगार से बेरोजगार हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। चूँकि पुनर्वास की व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती, वे निर्माण के कामों में, मजदूरी के कामों में लगते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं और जो शहरों में आ जाते हैं, उनके लिए इस प्रकार का एक नया आयाम खोला जाना चाहिए, जिसके कारण वे सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करके अपने देश के भविष्य को आगे सुधारने में अपना योगदान कर सकें।

महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम यहां पर एक अच्छा विचार-विमर्श कर रहे हैं। उनकी आत्महत्याएँ बंद होनी चाहिए। किसी भी रूप में इस बात का होना ठीक नहीं है। ये जो सारी कठिनाइयां हैं, वे अमानवीय परिस्थितियां हैं। उन अमानवीय परिस्थितियों को देखते हुए लोकतंत्र का तकाजा है कि हम उनके साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय करने के लिए तैयार रहें। हम उनके लिए ऐसी योजनाएँ बनाए, जिनसे हम उनके आत्महत्या करने के विचार को बदल सकें। हम उनको सुविधाजनक खाद, बीज, बिजली, पानी और कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु

अनेक प्रकार से उपाय करने के लिए मदद कर सकें । यदि हम यह कर सकें, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा काम होगा । मैं जानता हूँ कि खेती के कामों को करने के लिएः

खेत जोतता किसान जब, खेत में काम करता है,
और सूरज तपता है, तेरा पसीना मोती बन कर,
झर-झर करके झरता है ।
मेरे देश का किसान, है पसीना तेरा गान,
तेरी आँखों में हैं सबके सपने ।

सर, यदि उसकी आंखों में सबकी समृद्धि के सपने हैं, तो हमारे भी मन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम उसे सुखी और खुशहाल कर सकें और वह अपना जीवन सम्मानजनक रूप से जी सके । इतना ही मुझे कहना है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Dr. Chandrapal Singh Yadav. It is a maiden speech. So, you take 15 minutes.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (Madhya Pradesh): Sir, maiden speech has no time limit. He can speak as much as he wants to speak.

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आज कृषि के विकास पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मेरा इस सदन में बोलने का यह पहला अवसर है और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मैं एक किसान परिवार से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ । हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग सीधे-सीधे खेती से जुड़े हुए हैं । देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा, देश के किसान को स्वावलंबी बनाना होगा ।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

मान्यवर, हम अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं कि खेती के हिसाब से हमारे देश का मौसम बहुत ही अच्छा है । पूरी दुनिया में इतना अच्छा मौसम कहीं नहीं है । हमारे यहां सर्दी भी है, हमारे यहां गर्मी भी है, हमारे यहां बरसात भी है और हमारे यहां का किसान खुद में इतना योग्य है, कुशल है कि वह इस तरीके से खेती करता है कि पैर के अंगूठे से बता देता है कि खेत का टेम्परेचर क्या है ।

मान्यवर, फसल चक्र के माध्यम से किसान अपने खेत में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है और वह लाभकारी भी होता है, लेकिन मान्यवर, आज के इस मौके पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि 1970 के दशक के बाद, यह सही है कि देश में उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन हम इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसान की विपन्नता दिन-प्रति-दिन लगातार बढ़ी है । किसान आज देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है और आप जानते हैं कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है, वह 60 परसेंट से घटकर 10 परसेंट के आसपास आ गया है ।

श्रीमन्, यह बड़ी चिंता की बात है और इसलिए मुख्य रूप से आज़ादी के बाद से लेकर आज

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

तक लगातार सरकार ने बहुत सी नीतियां बनाईं, किसानों के हित के लिए, कृषि के विकास के लिए आयोग भी बनाए, कमेटियां भी बनाईं, उनकी रिपोर्ट्स आईं, लेकिन उनको कागज के ढेर में शामिल कर दिया गया, क्योंकि सरकार की इच्छा नीति बनाने की तो थी, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था, इस वजह से वे नीतियां लागू नहीं हो पाईं, वे सिफारिशें लागू नहीं हो पाईं, जिस कारण से आज किसान को इस तरीके से मोहताज होना पड़ रहा है ।

मान्यवर, खेती करने वालों की तादाद दिन-प्रति-दिन कम हो रही है, लोग खेती से पलायन कर रहे हैं । सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है । पिछले समय में चाहे इस तरफ बैठे लोगों की सरकार रही हो, चाहे आज जो लोग सरकार में हैं, वे कृषि के प्रति, खेती के प्रति गंभीर नहीं हैं, इसलिए दिन-प्रति-दिन खेती से लोग पलायन करते जा रहे हैं और इसके कारण आज गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की तादाद दिन-प्रति-दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है । आज अगर किसी किसान का लड़का चपरासी बनना चाहता है, तो किसान अपनी एक-एक खेती को बेचकर उसे चपरासी बनाना पसंद कर रहा है, लेकिन वह खेती करना पसंद नहीं कर रहा है ।

मान्यवर, आज "मनरेगा" के अंतर्गत जो मजदूरी मिलती है, उसके मुताबिक अगर एक घर में पांच मेम्बर्स हैं, तो उस परिवार को 200 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन 1000 रुपये की मजदूरी मिलती है, लेकिन एक किसान, जिसके पास दो एकड़ जमीन है, वह पांच लोगों के लिए 200 रुपये पैदा नहीं कर पाता । आज किसान मजबूर हो रहा है । जो बड़े-बड़े काश्तकार थे, वे परिवार बढ़ने के कारण आज छोटे काश्तकार हो गए हैं । श्रीमन्, हम जिस एरिया से आते हैं, वह बुंदेलखंड का एरिया है । उस एरिया के 20-20, 25-25 एकड़ के काश्तकार वहां से पलायन कर आज दिल्ली और मुम्बई में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं । वे वहां अपनी इज्जत को छिपाकर मजदूरी करने का काम कर रहे हैं । वे गांव में मजदूरी नहीं कर सकते, वे दिल्ली में आकर रिक्शा चलाने का काम करते हैं । मान्यवर, आज ये परिस्थितियां बनी हुई हैं । आज मैं इस मौके पर सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे किसी भी तरीके से हो, सरकार इन सब के प्रति गंभीर हो और वह गंभीर होकर निश्चित रूप से कृषि पर ध्यान दे । कृषि पर ध्यान देकर, उसे प्राथमिकता देकर उसके उत्पादन को बढ़ाने का काम किया जाए । कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान को कृषि-आदान की आवश्यकता है और उसे बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता है । मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि वह सस्ती दरों पर किसान को ऋण उपलब्ध कराए ।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लम्बे समय के लिए ऋण लिए थे, जिनकी जमीनें नीलाम हो रही थीं, जो ऋण नहीं दे पा रहे थे, उनके ऋण को उसने माफ करने का काम किया है । इसके अलावा, जो किसान आज कोऑपरेकटिव बैंक से ऋण लेते हैं, उनको 4 परसेंट या 3 परसेंट की सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का काम लगातार किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश के किसानों की तमाम प्रकार से मदद करने का काम किया जा रहा है । मैं केंद्र की सरकार से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह बहुत आवश्यक है कि अगर खेत का उत्पादन बढ़ाना है, किसान को सशक्त बनाना है, तो खेती पर लगने वाली जो लागत है, उसे आपको निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा । उसके लिए आपको किसान को मदद करनी पड़ेगी, किसान को पूरे तरीके से प्रशिक्षित करना पड़ेगा और किसान को पूरे तरीके से जागरुक करना पड़ेगा ।

मान्यवर, जब उत्पादन होगा और उसके बाद किसान को बाजार में सही कीमत नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से किसान की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी । कई लोगों ने यहां स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का जिक्र किया । मैं आपसे आज के इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन जी ने यह कहा कि आज खाद का दाम बढ़ गया, डीज़ल का दाम बढ़ गया, आप एमएसपी में 50 रुपये या 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दें, वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है । यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 50 रुपये और 100 रुपये बढ़ाकर किसान को खुशहाल बनाने का सपना देखना चाहते हैं, बल्कि आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि किसान की अगर पांच एकड़ जमीन है तो आज की तारीख में उसकी क्या कीमत है । आज किसान पर जो लागत आ रही है, उसके लिए चाहे उसने ट्रैक्टर खरीदा हो या पम्पिंग सेट खरीदा हो, उसकी खेती पर जितनी लागत आई है, उसको जोड़कर किसान को कम से कम 50 परसेंट लाभकारी मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए और सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए । सरकार ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में भी इस बात का वादा किया था कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करेंगे, लेकिन 200 दिन हो गए, सरकार ने उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया है । इसके साथ-साथ, मैं आज के इस मौके पर केंद्र सरकार से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि गांव को अगर उत्पादन एवं प्रसंस्करण केंद्र के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, तो उस खेत, उस गांव का जितना उत्पादन होगा उसके रखरखाव के लिए, वहां पर उसकी प्रोसेसिंग के लिए अगर गांव के लेविल पर यूनिट बनाने का काम करेंगे, तभी निश्चित रूप से वहां के किसानों को फायदा मिल पाएगा । इसके अलावा किसानों को फायदा मिलने वाला नहीं है । मान्यवर, दूसरी तरफ, सरकार एम.एस.पी. घोषित कर देती है लेकिन एम.एस.पी. पर खरीद नहीं हो पाती । सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितना उत्पादन किसान का होता है, हमारे देश में जितना उत्पादन होगा, हम एम.एस.पी. के रेट पर किसानों को दिलवाने का काम करेंगे । आज कहा जा रहा है कि धान की खरीद नहीं हो पा रही है । पूरे देश में आपने एम.एस.पी. घोषित कर दी, रेट घोषित करना अकेला आपका काम नहीं है, किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह जिम्मेदारी भी सरकार की है । आपको निश्चित रूप से इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि किसान का जितना उत्पादन है, सारा का सारा उत्पादन भले ही सरकार खरीदे, भले ही बाजार में खरीदा जाए, भले ही व्यापारी खरीदें लेकिन जो आपने एम.एस.पी. घोषित किया है, उससे कम रेट पर किसी भी सूरत पर नहीं बिकने दिया जाएगा । यह सरकार की जिम्मेदारी है । मान्यवर, आज के मौके पर मैं आप सब लोगों से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंचाई की सुविधा बहुत आवश्यक है । आज सिंचाई नहीं हो पा रही है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि भूजल की उपलब्धता का सर्वेक्षण और जलापूर्ति पूरी करने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए । एक-एक गांव के बारे में आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि नीचे भूजल कितना है, नीचे से हमें ग्राउंड वाटर कितना मिल सकता है । दूसरी तरफ जो सरफेस वाटर है, नदियां हैं, बरसात बहुत होती है । मान्यवर, नदियों से पानी बह करके निकल जाता है, सही तरीके से उसका प्रबंधन नहीं है । हम जिस क्षेत्र, बुंदेलखंड से आते हैं वहां बहुत नदियां हैं और बरसात के दिनों में बहुत बाढ़ आती है । बाढ़ से भी नुकसान हो जाता है और आज के समय में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता । आज तालाब खाली पड़े हैं, बरसात में पानी बह करके निकल रहा है लेकिन तालाब खाली पड़े हैं । जो डैम बने हुए हैं वे सब खाली पड़े हुए हैं । मान्यवर, सही तरीके पानी का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस धरातल के पानी का प्रबंधन सही तरीके से हो, जिससे कि पूरे तरीके से सिंचाई

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

की सुविधा मिल सके। आज सिंचाई के भी दाम बढ़ रहे हैं। पूरे देश में सिंचाई के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव की सरकार को कि उन्होंने किसानों का सिंचाई का शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। एक पैसा भी किसानों से सिंचाई के शुल्क के रूप में नहीं लिया जाता। ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, आज आवश्यकता है तमाम तालाबों के रखरखाव की। आप देख रहे हैं जितने तालाब बने हैं, हमारे एरिया में बड़े-बड़े तालाब हैं, सागर की तरह से सभी खाली पड़े हैं। ...**(व्यवधान)**... ...**(समय की घंटी)**...

**कुछ सम्मानित सदस्य :** सर, इनकी मेडन स्पीच है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति :** इसलिए दो मिनट और, 15 मिनट से ज्यादा न हो जाए।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव :** तालाबों में पानी पहुंचाने के लिए चैनल बनाए जाने चाहिए। अगर चैनल बनाए जाएंगे तभी इनमें पानी उपलब्ध हो पाएगा। मान्यवर, आज आवश्यकता है रासायनिक खादों की। आज किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिल पा रही है। और वे क्या कारण हैं, अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी नहीं हैं, वे पीठ थपथपा रहे थे कि 1960 से लेकर के आज तक बहुत प्रोडक्शन हो गया।

**श्री उपसभापति :** दो मिनट में समाप्त कीजिए।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव :** मान्यवर, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है, आज यूरिया के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा है? क्यों फिर रहा है? पिछली सरकार ने जो नीति बनाई है, उसने जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर के लिए डि-कंट्रोल कर दिया, नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने का एलान कर दिया। उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए। आज परिस्थितियां ये हैं कि उस फास्फेट को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग न करके यूरिया का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए यूरिया की बुरी तरह से मारा-मारी हो रही है। आज देश में जो उत्पादन है, देश का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा है, हम विदेशों से क्यों आयात कर रहे हैं, इस बात पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आज हमारे यहां 220 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होता है। इसके बाद भी हम दूसरे देशों से एक लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात करते हैं।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव :** मान्यवर, इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि रासायनिक खाद और यूरिया का पूरे तरीके से इंतजाम होना चाहिए।

**श्री उपसभापति :** धन्यवाद। माफ करना, There are ten more speakers. ...**(व्यवधान)**... बस, हो गया। पंद्रह मिनट हो चुके। अब आप खत्म करें।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव :** मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अनुसंधान पर सरकार बजट में पैसा नहीं देती है। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान पर बजट का केवल 0.56 परसेंट दिया और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 0.70 परसेंट दिया। मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालयों के पास आज संसाधन नहीं हैं। झांसी

में कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, लेकिन उसमें आज तक कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please, cooperate.

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : कृषि विज्ञान केंद्र काम नहीं कर पा रहे । मान्यवर, मिट्टी का परीक्षण बहुत आवश्यक है । मैं आज के मौके पर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए । एक-एक खेत का परीक्षण होना चाहिए, ताकि किसान को इस बात का पता हो कि वहां किन पोषक तत्वों की कमी है और उन पोषक तत्वों की कमी के आधार पर चाहे जैविक फर्टिलाइजर हो, चाहे कम्पोज्ड फर्टिलाइजर हो, उनका संतुलित मात्रा में उपयोग किया जा सके ।

**श्री उपसभापति** : चंद्रपाल जी, आप सवाल कीजिए ।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : मान्यवर, इस बात की बहुत आवश्यकता है कि अनुसंधान पर ध्यान दिया जाए और किसानों को अच्छे बीज मिलने चाहिए ।

**श्री उपसभापति** : चंद्रपाल जी, खत्म कीजिए ।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : मान्यवर, एक सबसे प्रमुख बात यह है कि जो किसान, छाती फाड़ करके, पूरा सीना चीर करके मेहनत करके पूरे हिन्दुस्तान को खिलाने का काम करता है, आज उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है । आज मैं इस मौके पर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए । कोई भी किसान हो, उसे 60 साल से ऊपर पेंशन देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । जब किसान का एक्सीडेंट हो जाता है, किसान मर जाता है, तो उसके परिवार के लोग पूरे तरीके से अनाथ हो जाते हैं, उनके आगे-पीछे देखने वाला कोई नहीं होता है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please, conclude. That is enough.

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : सरकार को इसके लिए उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए । मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान बीमा योजना लागू करके, कि यदि इनका एक्सीडेंट होता है तो पांच लाख रुपए तक देने का काम किया है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: आप बैठिए ।

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : मान्यवर, आदरणीय जटिया जी कह रहे थे, आप क्यों आरोप लगा रहे थे?

**श्री उपसभापति** : बैठिए, प्लीज । That is enough. बैठिए । ...**(व्यवधान)**... I will have to stop the mike.

**डा. चंद्रपाल सिंह यादव** : वे कह रहे थे 'तेरी रहबरी का सवाल है'। हम भी किसान होने के नाते किसानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि—

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ।

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।"

जयहिंद । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, first speaker will exhaust the entire time allotted to a party. And, then the maiden speech will come. What can the Chair do ? I don't know. I think, those who make their maiden speech should be put first, so that they can use the party's time. Now, Shri D. Raja.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, this is also a maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is making maiden speech every day.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, on agrarian crisis, it is his maiden speech.

SHRI D. RAJA : Sir, thank you for the opportunity given. The Indian agriculture continues to be in deep crisis. The farmers, particularly the agricultural workers, continue to live in distress, in abject poverty. The agricultural workers who are the real creators of wealth in our villages live in abject poverty, almost on the verge of pauperization. This is happening ever since our country has embarked upon the neo-liberal paradigm of economic development. What are the issues ?

(i) Farmers don't get remunerative prices to their agricultural produce. No remunerative prices.

(ii) High cost of inputs, particularly of seeds, fertilizers, diesel and electricity, having adverse impact on the productivity in agriculture.

(iii) No adequate credit facilities to our farmers. They are left in indebtedness.

(iv) Natural calamities such as flood and rains.

(v) Calamities in the global market, which have the impact on the commodity prices in our country.

(vi) Failure in resolving water disputes, particularly inter-State water disputes.

(vii) Lack of irrigation and failure in protecting our traditional water bodies.

(viii) We witness frequent failure of monsoons, drought and deficit rains.

The Government should have long-term and short-term perspective on the ways of addressing these issues. Sir, right now, we are witnessing extreme and acute distress of cotton farmers in different parts of the country, particularly in Telangana and Maharashtra. The number of suicides has gone up and every day there are reports. It is not the case of cotton growers alone. It is the case of cane growers; it is the case of paddy growers also. I draw the attention of the Government on two issues. One, as far as cotton growers are concerned, the yields are low this year. There are different reasons. I am not getting into them. Two, the prices are low. The farm-gate prices of cotton are as low as ₹3,000 per quintal. This is ₹1,000 less than the MSP announced.

Sir, the other immediate and urgent issue which requires attention is the crop insurance. Not only land-owning farmers but also tenant farmers and non-loanee farmers must be brought under the insurance cover. This requires Government's attention. Then, Sir, on this Minimum Support Price, I am asking the Government. This year, the procurement of paddy has been 2 MT lower than what was procured last year. The MSP given to paddy growers was so low. But, the previous Government set up a Committee some one-and-a-half years ago to look into the price fixation methodologies. What is the progress? Have we ever reviewed the work of this committee? Why is the progress so sluggish, so low? Because, the task before this Committee is to look at the methodologies. But, what is happening there? Nothing is happening. No progress. No review of this committee.

Sir, I now draw your attention to your own BJP manifesto. It said that 50 per cent more profitability over the cost incurred would be ensured to all farmers. It is not new. It is the formula given in the Swaminathan Commission Report; C2+50 per cent, it is the Swaminathan Commission's recommendation. You also promised. But, is it happening on the ground? Why is MSP not properly addressed? Because that Committee set up by the Government is not working and there is no progress in that Committee. Government will have to tell the Parliament, tell the House, what the purpose of having that Committee is, which is not doing anything, which is not making any progress. But, it is a crucial issue, a critical issue, as far as farmers are concerned.

Then, Sir, another issue is the need to look at the income security guarantee for all farm households, wherein every farm household will be guaranteed a minimum living income. Is the Government prepared to address this issue? Unless we address these issues on an urgent basis, on a priority basis, we cannot reduce the distress in the coming five to ten years, and agrarian distress will continue. This is a serious issue before us.

Now, the final point which I wanted to make is this. Yesterday, we had enough discussion on WTO. Whatever the Government claims to be a victory in the WTO negotiations, actually, I find it is succumbing to the American design, in the long run, which can impoverish our farmers and which will adversely affect our agriculture. In such a situation, the worst-affected are the agricultural workers. They do not have livelihood in villages; they do not have jobs in the villages; they migrate to cities for jobs. There also, they don't get jobs. This leads to a kind of vaporisation and social tension in the country. So, agrarian distress will have to be addressed with a sense of urgency.

Finally, Sir, I end with what Thiruvalluvar had said; you will like it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I will like it.

SHRI D. RAJA: He was a great philosopher and poet.*

What Thiruvalluvar says, "let us hail agriculture and industry." He gives priority to agriculture. And let us denounce those who just eat and enjoy without doing anything. Government should have that approach; you should give priority to agriculture, understand the dimension and depth of agrarian distress, the crises in the interest of small and marginal farmers, in the interest of agricultural workers. Government will have to act, no more rhetoric, no more demagogy. What we need is action from the Government. What you are going to do in the coming days, please, tell the Parliament, tell the nation. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you very much. Shrimati Rajani Patil.

**श्रीमती रजनी पाटिल** (महाराष्ट्र) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं यहां पर दो चीज़ें बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। एक तो मैं किसान परिवार से बिलांग करती हूं, I am a farmer. दूसरी चीज़ यह है कि यहां पर पचास प्रतिशत लोगों ने यह बात कही कि मराठवाड़ा क्षेत्र में आत्महत्याएं ज्यादा हुई हैं। जिस क्षेत्र का वे सब नाम ले रहे हैं, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही कम समय में मैं अपने शब्द और विचार आपके सामने रखूं।

सर, इस देश की 70 प्रतिशत जनता खेती और उससे जुड़े हुए व्यवसायों से संबंध रखती है, उनका जीवन-मरण उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उन किसानों और उन लोगों की कठिनाइयों के बारे में और खास तौर से आज की तारीख में वे जिन खतरों के साथ जूझ रहे हैं, उनके बारे में मैं अपने विचार यहां पर व्यक्त करूंगी। सर, पूरे देश में मुझे खेती के लिए तीन खतरे लगते हैं। एक है वर्षाकाल, मानसून, दूसरा है मार्केट, बाजार और तीसरा है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी व्यवस्था और इन तीन चीजों से किसान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज तो ये कठिनाइयां इतनी बढ़ गई हैं कि किसान इनके चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गया है। सर, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब क्षेत्रों में आज तक 40 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और केवल महाराष्ट्र में और विशेषकर मेरे क्षेत्र मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में गत महीने में 120 लोगों ने आत्महत्या की है। पूरे देश में जहां कपास और सोयाबीन का उत्पादन होता था, उस क्षेत्र में इस साल पानी का अकाल है, इसके कारण कपास और सोयाबीन की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई है और जो भी पैदावार हुई है, उसकी कीमत एकदम गिर गई है।

सर, मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूं। आज गेहूं, कपास, गन्ना, सोयाबीन, धान, मूंगफली और जो हार्टिकल्चर है, एक ज़माना ऐसा था कि हम अभिमान से कहते थे कि हम इन सब को महाराष्ट्र से लाते हैं। आज उसी महाराष्ट्र में, खासतौर से मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में सबसे ज्यादा अकाल इस बार पड़ा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सभी जगह पर चाहे धान हो, चारा हो, पानी हो, सभी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारे महाराष्ट्र में करीब 40 हजार गांवों में से 20 हजार गांव अकालग्रस्त हैं। रबी की फसल की बुवाई सिर्फ 55 प्रतिशत हुई है और 45 प्रतिशत खेत बिना बुवाई के पड़े हैं।

---

* The hon. member spoke in Tamil.

सर, यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, वह हर साल बढ़ाई गई थी, इससे किसानों को थोड़ी राहत मिल रही थी । यूपीए सरकार ने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया था और किसानों की मदद करने की कोशिश की थी । आज न मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि हुई है, न कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी है और प्याज की निर्यात पर रोक लगाकर प्याज के भाव गिराए गए हैं और प्याज उगाने वाला किसान भारी संकट में है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत है और आयात पर पाबूंदी लगाने की जरूरत है ।

सर, आपको मालूम है कि जापान में चावल के आयात पर एक हजार प्रतिशत इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है जिसकी वजह से वहां पर चावल पैदा करने वाले जो किसान हैं, वे सुरक्षित हो गए हैं । हमारे देश में long-term, दूरदर्शी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाना जरूरी है । कपास के भाव चार हजार रुपये क्विंटल दिखाए तो जाते हैं, लेकिन आज किसान दो हजार, ढ़ाई हजार, डेढ़ हजार रुपये क्विंटल में कपास बेचने को मजबूर है । कपास उत्पन्न करने वाला किसान मारा जा रहा है । सबसे ज्यादा कपास चीन में होता है । उन्होंने इम्पोर्ट बन्द किया हुआ है क्योंकि उनके पास कपास का बहुत स्टाक है । हमारे देश में हौजरी की, कपड़े की कोई दूरदर्शी योजना नहीं है । इसके कारण हमारे देश में जो कपास का उत्पादन है, उसकी कीमत में बहुत गिरावट आई है ।

सर, सोयाबीन जैसी वस्तु को प्रोसेस करके बड़ी तादाद में सोया मिल्क, सोया प्रोटीन, एडिबल ऑयल तैयार करने की आवश्यकता है । आज गन्ना उत्पादन करने वाला किसान त्रस्त है । सर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शूगर का प्रोडक्शन होता है, वहां पर सबसे ज्यादा चीनी तैयार की जाती है, लेकिन गन्ने का किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, न चीनी का अच्छा भाव मिल रहा है । जो चीनी मिलें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक और तमिलनाडु में हैं, उनके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए जिससे किसानों को अच्छा भाव मिले ।

सर, महाराष्ट्र में गत दस साल में गन्ने के आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है । सर, विधान सभा के चुनाव के पहले एक रचना थी जिसके माध्यम से गन्ने की राजनीति करके महाराष्ट्र में हमारी तब की सरकार को बदनाम किया गया और उसमें वे सफल भी हुए । अब भी गन्ने की स्थिति वैसी ही है । जो नई सरकार है वह बात करने के लिए तैयार नहीं है । ...(**समय की घंटी**)... सर, हमारे यहां किसानों को जो राहत दी जाती है, वह बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, प्यास लगी तो कुआं खोदा, ऐसा बोला जाता है । आज सभी लोग पैकेज की मांग कर रहे हैं । इलेक्ट्रिसिटी के बिल में माफी, कर्ज में माफी, जिस क्षेत्र में अकाल पड़ा है, उसके लिए मुआवजा देने की मांग लेकर हम केंद्र सरकार के पास आए हैं । इन सब चीजों पर केंद्र सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस पल में देश के किसानों का साथ दे । सर, मैं एक ही मुद्दा बताना चाहती हूं कि यह सब मदद, राहत कार्य तात्कालिक स्वरूप में होना चाहिए । हम चाहते हैं कि इस देश के किसानों के लिए एक दीर्घकालीन, लांग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें किसानों को ऋण दिया जाए और वह केवल 4 प्रतिशत ब्याज पर देते हैं । उसके साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कोल्ड स्टोरेज हो, उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है । सर, मैं अपने भाषण को कट करूंगी, क्योंकि हमारे दो सहयोगी और बोलने वाले हैं । मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं । यहां पर कृषि मंत्री जी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी जो भी आदमी काम करता है, चाहे वह कर्मचारी है, गैर-कर्मचारी है या MNC में काम करने वाला है, उसको काम करने के कुछ

[श्रीमती रजनी पाटिल]

साल बाद पेंशन मिलने की व्यवस्था है । हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग किसान हैं और उनको भी पेंशन देने की आवश्यकता है । किसानों की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए किसानों की मदद करने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a very genuine demand.

**श्री नंद कुमार साय** : उपसभापति जी, देश में किसानों की बड़ी दुर्दशा है, जिसके कारण आज खेती पिछड़ गई है । यह देश का सबसे बड़ा धन्धा और सबसे बड़ा काम है । हमारे सभी वक्ताओं ने इस पर बहुत सारे सुझाव दिए हैं । मैं कृषि मंत्री के ध्यान में दो-तीन बातें लाना चाहता हूं । पहले किसान गोबर की खाद से खेती करता था, खरपतवार की खाद से खेती करता था । जब से यह रासायनिक खाद आ गयी है, उर्वरक आ गए हैं, तो किसान उनका बंधक हो गया है और उसके बिना खेती नहीं होती है । कीटनाशक के बिना खेती नहीं होती है । ये दोनों ही जहर का काम कर रहे हैं । भूमि पूरी तरह से बंजर हो गई है । किसान की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बोर करके पानी निकालो और जल स्तर नीचे चला गया है, ड्राई हो गया है । एक समय कहा जाता था, मालवा के लिए—

"मालव धरती गहर गंभीर

और डग डग रोटी पग पग नीर ।"

वह सूखा हो गया है । पंजाब की तो दुर्दशा ही है । इससे देश के किसानों को और जमीन को कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है । मैं इस पर बहुत ज्यादा सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो उर्वरक और कीटनाशक है, इसका विकल्प गोमूत्र और नीम की पत्तियों से बनाया जा सकता है । इसके और भी कई विकल्प हैं, इसको शुरू किया जाए और कीटनाशक और उर्वरक को धीरे-धीरे बंद करने की कोशिश की जाए । यहां पर तालाब और सरोवर के बारे में सभी लोगों ने कहा है कि वे बंद हो गए हैं । केवल बोर पर ही सिंचाई होगी, तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है...

**श्री उपसभापति** : बोलिए, बोलिए ।

**श्री नंद कुमार साय** : किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि खेत में पैदा होने वाले माल, कारखानों और मिलों में तैयार होने वाले माल, दोनों के दाम में जमीन-आसमान का अन्तर है । किसान जब माल बेचता है और उसके पास सामान रहता है, वह पूरा सस्ता होता है तथा गोदाम में जाने के बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है । कपड़ों से लेकर दूसरा सामान जो किसान खरीदता है, उसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं । इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई तालमेल बिठाने का तरीका हो सकता है कि खेत में जो माल पैदा होगा, अगर वह सस्ता है, तो मिलों और कारखानों में बनने वाला सामान भी किसान को सस्ते में मिलना चाहिए । यह तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? इसीलिए किसान दुखी और परेशान है, अगर वह कर्जा ले लेता है, तो वह चुकाएगा कैसे? वह जो सामान खरीदेगा, वह सब सामान महंगा ही खरीदेगा और जो अपना उत्पादन बेचेगा, वह सब सस्ता । कृषि मंत्री जी कैसे इसमें तालमेल बिठाएंगे और उनके पास जो कर्जे हैं, वे कितने कम हो सकते हैं, कैसे उनको छूट दी जा सकती है । उनको

अपने ही उत्पादन की लाभकारी आमदनी कैसे दी जा सकती है, इस दिशा में अनुसंधान और खोज करने की जरूरत है । मैं समझता हूं कि अगर किसान दुखी है, तो देश सुखी नहीं हो सकता ।

**[उपसभाध्यक्ष (श्री पी. राजीव)** *पीठासीन हुए*]

खेती और अच्छी कैसे हो, उसके साथ पशुपालन को कैसे जोड़ा जाए? यहां पर गऊ नहीं है, किसी के घर में नहीं है । जितना घी और दूध है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के कारखानों में बन रही हैं । ये चीजें यूरिया से बन रही हैं । यूरिया खेतों को नहीं मिलेगा । इन सारी चीजों का निर्माण करने के लिए जगह-जगह कारखाने खुले हुए हैं । वे सारे कारखाने जहर का काम कर रहे हैं । उसी की सप्लाई हो रही है । एक भी गाय नहीं है, लेकिन आप टनों खोया ले लीजिए । इसलिए गऊ पालन का काम हो, ताकि दूध भी आए, गोबर भी हो और उससे खेती हो । हमारे पास समय सीमित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि इस दिशा में भी विचार करने की जरूरत है । मैं समझता हूं कि पहले अकाल जरूर पड़ता था, लेकिन किसान आत्महत्या नहीं करते थे, परन्तु जब से कर्ज़ा लेकर खेती करने का सिस्टम आया है, तब से यह हो रहा है । वे उधारी और कर्ज़ा तो ले लेते हैं, लेकिन चुका नहीं पाते, क्योंकि सारी खेती ही घाटे में है, खेती करने वाले घाटे में रहते हैं । कई लोगों ने बताया कि सौ एकड़ या पांच सौ एकड़ का जो किसान है, वह उसको बेचकर पान का ठेला लगाना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है । समाज में किसान की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इस समाज में खेती करने वाले की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए इन सारी परिस्थितियों को बदलकर किसान को, खेती को कैसे प्रतिष्ठित किया जाएगा, इसके बारे में सोचें । अगर किसान प्रतिष्ठित होगा, कृषि प्रतिष्ठित होगी, तभी यह देश भी प्रतिष्ठित होगा, उसके बिना नहीं हो सकता है । अगर अस्सी प्रतिशत किसान दुखी हैं, परेशानी में हैं, तो वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है । मैं चाहता हूं, मेरी यह राय है कि यह बहुत कठिन काम है, लेकिन आप इस बोर के काम को बंद करें, नदी जोड़ने के काम की शुरूआत करें, तालाबों के निर्माण को विस्तार दें । इसके साथ आपको इन सभी कामों को ठीक से करना पड़ेगा कि यह पानी, जिसका बहुत अपव्यय हो रहा है, उसके अपव्यय को कैसे रोका जाए और कृषि में अच्छा काम कैसे किया जाए? क्योंकि, किसी ने कहा था ...एक मिनट, आधा सैकिंड... हमारे वेदों में लिखा है, कोई कहता था कि यह देश देश नहीं है, यह तो उपमहाद्वीप है, यह अलग-अलग फैला हुआ है । ऋग्वेद में लिखा है, "इयं ते राष्ट्र ध्रुवअसि धरूणः, कृषैस्त्वा क्षेमायत्वा पोषायत्वा ।।" यह देश तुम्हारा है, जो कृषि के लिए है, सबकी भलाई के लिए है, सबके भरण-पोषण के लिए है, इस देश को मजबूती से धारण करो । कृषि मंत्री जी, इसी ब्रह्मवाक्य को, इसी वेदवाक्य को ध्यान में रखकर किसान, खेती और देश को कैसे ठीक किया जा सकता है, आप इसके लिए भागीरथ प्रयत्न करके संपन्न कीजिए । देश आपके साथ है, हम सभी लोग आपके साथ हैं । आप इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो बहुत आनन्द आएगा, देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में इसका नाम होगा । इन्हीं बातों के साथ, मैं समझता हूं कि कृषि मंत्री जी बहुत सारे कामों को ठीक करेंगे । मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

**श्री संजय राउत** (महाराष्ट्र) : सर, हमारे देश में किसानों की खेती की जो स्थिति पैदा हुई है, किसानों को जिंदा रखने के लिए, उनको प्रतिष्ठा देने के लिए, हमने इस सदन में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का प्रोविजन रखा है । लेकिन यह शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं है, यह लांग ड्यूरेशन डिस्कशन है । हम साठ साल से इस विषय पर लांग-लांग ड्यूरेशन डिस्कशन करते आए हैं, लेकिन

[श्री संजय राउत]

कुछ हल नहीं निकाल पाए हैं और आज भी इसको कर रहे हैं । हम गर्व से कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है, "जय जवान, जय किसान" हमारा राष्ट्रीय नारा है, लेकिन हमारे किसानों की, हमारी खेती की जो दुर्गति हमारे देश में हो रही है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं । यहां पर जो आंकड़े मेरे पूर्व वक्ताओं ने पेश किए, वे बहुत ही गंम्भीर आंकड़े हैं । लगभग 3 लाख फार्मर्स ने 1995 और 2014 के बीच आत्महत्याएं की हैं । 2004 से लेकर अब तक 2 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं । Every thirty minutes, in India, a farmer commits suicide. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, केरल में सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं । महाराष्ट्र में गत दो महीने में, अक्टूबर और नवंबर में मराठवाड़ा, विदर्भ रीज़न में 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं । सर, यह किसानों का आक्रोश है । देश को सबसे ज्यादा रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर देता है । लगभग 56 परसेंट लोगों को जीविका देने का काम किसान करता है, लेकिन देश भर में आज वही किसान बेरोजगार और भिखारी बन गया है । वह भूखा और कंगाल बन गया है । यहां हम सभी लोग उस पर बार-बार चर्चा करते हैं । मैं अभी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में था, मेरे हाथ एक किताब लगी, जो देश के मशहूर शायर फ़ैज अहमद फ़ैज की थी । मैंने उसमें किसानों के ऊपर एक कविता देखी और मुझे लगा कि आज के किसानों की भी यही हालत है । फ़ैज अहमद फ़ैज ने उर्दू में लिखा है –

सब काट दो,
बिस्मिल पौधों को,
बेआब, सिसकते मत छोड़ो ।
सब नोच लो,
बेकल फूलों को,
शाखों पे बिलखते मत छोड़ो ।
ये फसल उम्मीदों की हमदम,
इस बार भी गारत जाएगी ।
सब मेहनत, सुबह शामों की,
अब के भी अकारथ जाएगी ।
खेती के कोनों, खुदरों में,
फिर अपने लहू की खाद भरो ।
फिर मिट्टी सींचो अश्कों से,
फिर अगली रुत की फिक्र करो ।
फिर अगली रुत की फिक्र करो ।
जब फिर एक बार उजड़ना है,
इक फसल पकी तो भर पाया,
तब तक तो यही कुछ करना है ।

फिर-फिर हमको उजड़ना है, यह किसानों की हालत है । वह खेती करता है, उसको फिर उजड़ना है । इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को कितनी बार उजड़ने देंगे? यह हाल हमारे किसानों का है । किसानों का खेती से मोहभंग हो रहा है । हम किसानों के लिए जितनी भी योजनाएँ बना रहे हैं, क्या हम उन्हें किसानों तक पहुँचा रहे हैं? हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया । मैं बीच में सुन रहा था कि किसानों के लिए सरकार ने एक क्रेडिट कार्ड योजना बनाई, ताकि कम ब्याज देना पड़े । उसमें शून्य ब्याज बताया गया है, अगर आप 6 महीने में रकम अदा कर देते हैं । अगर आप 6 महीने में इसे नहीं भर पाते हैं, तो उस पर 14-15 परसेंट ब्याज चढ़ा कर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जबरन वसूली करते हैं । अगर 6 महीने बाद फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान कहां से कर्ज चुकाएगा? ऐसी स्थिति में किसान कर्ज में डूब जाता है और इतना कर्ज होता है कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर होता है । मैंने आपको सुसाइड के जो आँकड़े बताए, उनमें से लगभग 50 हजार किसान परिवार की महिलाएं हैं । उन महिलाओं ने आत्महत्याएँ की हैं । यह हमारे किसानों के परिवारों की स्थिति है । हम लोगों ने, सरकार ने, यहां की हो या वहां की हो, योजनाबद्ध तरीके से किसानों की खेती को घाटे का सौदा बना दिया है, क्योंकि जो उद्योगपति हैं, जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, हम उनको किसानों की जमीन देना चाहते हैं । हम लोग इस प्रकार की योजनाएँ बनाते हैं और हमारा किसान जिंदा नहीं रहना चाहता है, मरना चाहता है । आजादी के बाद किसानों के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा है । जब चुनाव आता है, तो हम किसानों के लिए बड़े-बड़े वादे करते हैं, हम प्रचारों में किसानों की बात करते हैं, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वादे करते हैं । ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री संजय राउत** : प्रचार में हमने भी वादे किए हैं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने वादे पूरे कर सके? हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में किसान रहेगा, तो देश रहेगा और हम सब लोग रहेंगे । मैं महाराष्ट से आता हूँ । मराठवाड़ा और विदर्भ, दोनों क्षेत्रों में इतना भारी अकाल पड़ा है, हजारों गांव उजड़ गए हैं, हजारों जानवर खत्म हो गए हैं । हम केंद्र की सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वह एक अच्छा पैकेज बनाए । ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री संजय राउत** : महाराष्ट्र में हमारे जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, वहां इतना ज्यादा दूध का उत्पादन हुआ है कि उनको मिनिमम प्राइस नहीं मिल रही है और वे पूरा दूध सड़कों पर फेंक रहे हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री संजय राउत** : हमारे यहां आलू, प्याज और टमाटर का इतनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है कि सरकार उनको अच्छा मूल्य नहीं दे पाती, तो किसान उसे रास्ते पर फेंकने को मजबूर होते हैं । ...(**समय की घंटी**)... मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप देश के किसानों के बारे में एक ऐसी नीति बनाएँ कि जो हमारा किसान है, जो हमारा भगवान है, वह जिंदा रहे । अगर वह जिंदा नहीं रहेगा, तो देश नहीं बचेगा और हम भी जिंदा नहीं रहेंगे । धन्यवाद ।

**डा. संजय सिंह** (असम) : महोदय, आपको बहुत धन्यवाद । अभी उस तरफ से, इस तरफ से और चारों तरफ से इस विषय पर चर्चा हुई । यह भी कहा गया कि हमारा विकास हो रहा है, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, हम सेल्फ-सफिशिएंट भी हैं, हम विदेशों को अपने अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, हम सारे लोग भोजन कर रहे हैं और बड़े सुखी हैं । उसी के साथ-साथ महाराष्ट्र में कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गन्ना किसान आत्महत्या कर रहे हैं और देश में चारों तरफ हर तरह से कृषि और किसान, दोनों के बारे में बड़े विस्तार से चिंता व्यक्त की गई । यह विरोधाभास क्यों है? अगर हम निर्यात कर रहे हैं, **self-sufficient** हैं, हर तरह से किसान दुरुस्त हैं, तो फिर वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसे में हमारे सामने दुःख का अन्य क्या कारण बनता है?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गम्भीर है । माननीय कृषि मंत्री जी, स्वयं किसान हैं और योग्य हैं । एनडीए की नई सरकार बनी है, वह विकास के मुद्दे पर आई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो सिर्फ विकास का ही विकास हो रहा है । अगर आप किसान और कृषि का विकास कर सकेंगे, मैं समझता हूं कि इस देश का असली विकास तब हो सकेगा । हालात ये हैं, आज लगभग 2,500 लोग हर रोज़ खेती का काम छोड़ रहे हैं और खेती के काम से विमुख होकर दूसरे कामों में जा रहे हैं । इस देश का जो सामान्य कृषक है, उसकी औसत आय आज 2,500 रुपये के आसपास है । यह आंकड़ा स्वयं में हर चीज़ को दर्शाता है कि हमारी स्थिति क्या है, इसमें किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक नये सांसद महोदय बोल रहे थे, उनका स्वागत है । उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी बातों की बहुत चर्चा की है । मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की एक बानगी देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में क्लास-1 कैटेगरी के ऑफिसर्स में 80.3% वेकेंसीज़ खाली हैं, क्लास-2 में करीब 55% रिक्तियां हैं, क्लास-3 में लगभग 70% पद अभी रिक्त हैं, वहां काम करने वाले लोग नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में चार कृषि विश्वविद्यालय हैं, जहां पढ़ाने वाले लोगों की 50% कमी है और फील्ड और लैब वर्कर्स में करीब 70% रिक्तियां हैं ।

महोदय, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और न ही किसी की प्रशंसा कर रहा हूं, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं । एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि कहीं पर डाटा की **jugglery** है । आज दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और है ।

अंग्रेज इस देश को छोड़ गए । हमारे देश में रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों का ही लागू किया गया है । आज भी हमारे यहां लेखपाल है, पटवारी है, जिसे स्वयं हर जगह खेतों में जाना चाहिए, और वहां पर देखना चाहिए कि क्या खेती हो रही है, कौन सी वेराइटी है, उसकी यील्ड क्या है, पैदावार क्या है । वही पटवारी जिले में जाता है, जिले से प्रदेश में जाता है और प्रदेश से केंद्र सरकार के पास आता है । वहीं यह तय होता है कि हमारे देश में लाखों मीट्रिक टन पैदावार होने वाली है ।

आज हमारे देश में खेती योग्य जमीन लगातार कम हो रही है, प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है और तमाम निर्माण कार्य भी हो रहे हैं । किसानों को बिजली समय पर नहीं मिलती, खाद समय पर नहीं मिलती, बीज मिलता ही नहीं है और टेक्निकल सपोर्ट उनको है नहीं । 20 साल पहले हमारे यहां यूकेलिप्टस की बहुत अच्छी पैदावार होती थी, पूरे देश में यूकेलिप्टस पैदा हो गया और नतीजा यह हुआ कि उसकी कीमत घट गई । यहां पर मेन्थॉल की खेती ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, दो-तीन मिनट बोलने का समय और दे दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): You take one more minute.

**डा. संजय सिंह** : अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ ही जाऊँगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Take one more minute. आपकी पार्टी से एक स्पीकर और भी है ।

**डा. संजय सिंह** : ठीक है, तो आप दूसरे स्पीकर को बुलवा लीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Take one more minute.

**डा. संजय सिंह** : नहीं, हमें नहीं बोलना है ।

**श्रीमती रेणुका चौधरी** (आंध्र प्रदेश): आप बोलिए, अभी आपका टाइम है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): You can take on one more minute.

**डा. संजय सिंह** : नहीं, हम नहीं बोलेंगे । मान्यवर, आप हमारे दूसरे साथी को समय दे दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay. Thank you. Then, Shri Basawaraj Patil.

**श्री बसावाराज पाटिल** (कर्णाटक) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कृषि के ऊपर चर्चा हो रही है । किसान, कृषक और कृषि सम्बन्धी कई आंकड़े दिए गए हैं । किसी ने कहा कि 80% किसान हैं, किसी ने कहा कि 65% किसान हैं । वास्तव में एक श्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक ने कहा है कि आज भारत में केवल 53% किसान ही बचे हैं और धीरे-धीरे यह संख्या घटकर 20% तक पहुंचने वाली है । ऐसी परिस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज़ादी से पहले गांव स्वतंत्र था, उसी तरह अगर आप मेरे गांव की आज़ादी को वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारा किसान अधिक खुश रहेगा । इस दिशा में यहां पर जितने भी सलाह-मशविरे मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि पांच साल या दस साल का एक लम्बा प्लान बनाकर आने वाले 10 साल के बाद एक ऐसी स्थिति देश में निर्मित हो, जो आज़ादी से पहले थी, आज़ादी के बाद भी कुछ दिनों तक थी । पहले जब सरकार को कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो वह बाजार से कम रेट में खरीदती थी, अब वह जो रेट बोलती है, किसान को रोना पड़ता है । किसान की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए । अगर धरती पर दूसरा कोई भगवान है, जो लोगों को अन्न देता है, पशु-पक्षी, जीवराशि को भी, तो भगवान के बाद वह किसान है । उसके सुख के बिना किसी देश का सुख नहीं होता है । इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि पहला, जो आत्महत्याएं आदि जिन-जिन राज्यों में हो रही हैं, उनको तुरन्त रोकने की दृष्टि से सरकार ने अभी कदम उठाया होगा, लेकिन अगर और भी जरूरत पड़े, तो कड़े कदम उठा कर हरेक किसान को जिन्दा बचाए रखने को सरकार पहली प्राथमिकता दे, मैं यह आपसे प्रार्थना करता हूँ ।

दूसरा, कृषि राज्य और केंद्र से जुड़ी हुई चीज़ है । राज्य के कृषि मंत्रियों से आने वाले एक-दो महीने के अन्दर दीर्घ चर्चा करके एक सुदीर्घ लम्बी नीति बनाकर किसान के लिए एक गौरव का स्वरूप इस देश को देने की दृष्टि से अलग-अलग मुद्दों पर आपको सोचना होगा । हमारे देश के अन्दर 127 इको जोन्स हैं । धरती के गुण हैं । अलग-अलग प्रकार के गुण हैं-वहां की मिट्टी की परीक्षा, वहां पर पानी की उपलब्धता और उसके आधार पर वहां की उपज ।

[श्री बसावाराज पाटिल]

**6.00 P.M.**

सर, मैं एक और बात की तरफ माननीय कृषि मंत्री जी का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । सामान्यतः जैसे पढ़ाई में सब लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, वैसे ही अगर किसी फसल का दाम किसी साल ज्यादा हो जाता है, तो तुरन्त सारे किसान उसी फसल की खेती की ओर जाकर आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं । इसे रोकने की दृष्टि से, जनजागृकति की दृष्टि से, हर बार आंकड़े को इकट्ठा करके पहले से जनता को अवगत कराया जाए, मल्टी क्रॉप की नीति रहे और कृषि के साथ-साथ पशुपालन, पक्षी पालन और अन्य प्रकार के पेड़-पौधे, फल आदि लगाने चाहिए । बहुत सारे छोटे उद्योग हैं । जो सामान छोटे उद्योगों में उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वह गांवों में उत्पन्न किया जा सकता है, वह बड़े कारखाने में उत्पन्न होता है । तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करके जो सामान गांव में तैयार हो सकता है, जिस वस्तु का उत्पादन गांव में हो सकता है, वैसे बड़े कारखानों की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है । इससे जहां करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं गांव के लोग सुखी रहेंगे और गांव के छोटे-छोटे उद्योगों के आधार पर वहीं पर बाई-प्रॉडक्ट्स तैयार होंगे । इससे किसान भी खुश रहेगा और वहां का कामगार भी खुश रहेगा । अगर इस दिशा में सरकार सोचेगी, तो यह मेरे लिए अत्यंत आनन्द की बात होगी । मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि उस दिशा में एक दीर्घकालीन योजना, दस साल लम्बी योजना बने । लोग थोड़ा समय तक कुछ कहेंगे, लेकिन आप चिन्तन करके सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात करके, विश्वविद्यालयों से बात करके एक नयी योजना अगले साल लाएँ, मैं यह आपसे प्रार्थना करता हूँ । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Thank you, Mr. Basawaraj Patil. There are four more speakers. Now, since it is 6 o'clock, I have to take the sense of the House. If the House agrees, we have to conclude it.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay. Now, Shri Balwinder Singh Bhunder.

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** (पंजाब)ः सर, हिन्दुस्तान के किसान की जो हालत है, आज हम सभी उस पर चर्चा कर रहे हैं । हमारे देश के किसानों की जो हालत है, यह हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी जो किसान हैं, किसी भी किस्म का प्रोड्यूस वह करता है, चाहे वह केला पैदा करता है, सेब पैदा करता है, टमाटर पैदा करता है, ऊन पैदा करता है, पैडी या व्हीट पैदा करता है अथवा मिल्क पैदा करता है, हरेक की हालत एक जैसी है ।

सर, आप भी देखिए, मैं हैरान हूँ कि उसी की पैदा की हुई हर चीज़ से हम लोग जी रहे हैं, हम सब जो यहां अभी बैठे हैं, हम कपड़ा भी उसका बनाया पहनते हैं, दूध भी उसका दिया हुआ पीते हैं और जो भी खाने वाली चीजें हैं, फ्रूट, वेजिटेबल आदि जो भी हैं, सब उसी की देन हैं । हम लोग कोट-पैंट तो पहने हुए हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है । अभी सर्दी कितनी है, जब वह खेतों में पानी लगाता है, तब देखने वाली बात होती है । मैं ज्यादा इन चीजों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है । मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगातार बार-बार

कमिशन बना, 2006 में Working Group on Distressed Farmers under Sardar Singh Johl बना, 2007 में Indebtedness पर राधाकृष्णन कमिशन बना, National Commission on Farmers under Dr. M. S. Swaminathan बना। सभी कमिशनों ने एक ही रिपोर्ट दी कि अगर किसान को बचाना है, तो उनको immediate रिलीफ पैकेज देना चाहिए और बाद में यह सेकेण्डरी है कि आगे उसको कैसे preventive measures करने हैं। यह 2006 की बात नहीं है, बल्कि यह सदियों से हो रहा है कि कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि किसान डिसयुनाइटेड है और छोटे-छोटे काम वाला भी युनाइटेड है। अगर कभी उनको याद आ गई और हिन्दुस्तान के किसान ने एक साल में एक दिन व्रत रख लिया और यह कह दिया कि इस साल हम फसल पैदा नहीं करेंगे, हमें तो भूखे मरना है, तो हम क्यों फसल पैदा करें? तब देश को पता लग जाएगा कि किसान की कीमत क्या है। हमारा किसान, हमारा जवान, हमारा साइंसदान दुनिया में महान है। मंगल मिशन ने साबित कर दिया कि हमारा साइंसदान कितना काबिल है। कारगिल वॉर ने साबित कर दिया कि हमारा जवान कितना काबिल है और दुनिया हमारे हिन्दुस्तान के किसान का लोहा मानती है, लेकिन दुनिया में सबसे गरीब, दुखी हमारा किसान है। इसका कारण क्या है? आज WTO एक नई प्रॉब्लम आ गई है। हम तो कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, सबसे एग्रीमेंट के बाद यह आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें बात क्या है? वह कहता है कि यह तो ग्रीन सब्सिडी है, यह ब्लू सब्सिडी है। हम तो ब्लू में आ जाते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे ग्रीन सब्सिडी में आ जाते हैं और इसके तहत वे इतनी सब्सिडी देते हैं और वहां का किसान खेती करता है। अगर जैसा हमारे साथ हो रहा है, वैसा ही वहां भी होगा, तो वहां के सारे किसान खेती छोड़ कर भाग जाएंगे। मैं कारणों में ज्यादा जाने के बजाए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सजेशन्स देना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है। मेरे पास प्वाइंट्स तो बहुत हैं।

महोदय, मैं पांच-छः प्वाइंट्स कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि खेती की जो भी वस्तु है, उसके लिए रिसर्च की व्यवस्था होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम फंड दिया जाए ताकि बेस्ट रिसर्च हो, सीड बेस्ट मिले, उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, yield बेस्ट हो ताकि किसान की पैदावार बढ़े। अच्छा सीड देंगे, तो वे अच्छी क्वालिटी पैदा करेंगे और इससे उसके हालात अच्छे होंगे।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में है। पूरे देश में हर क्रॉप का इंश्योरेंस मस्ट कर दिया जाए। आप मिनिमम इंश्योरेंस कर दीजिए, मैं यह नहीं कहता कि आप प्रति एकड़ 40 हजार या 50 हजार कर दीजिए, आप 20 हजार या 15 हजार प्रति एकड़ कर दीजिए। ...(**समय की घंटी**)...

मेरा तीसरा सुझाव एमएसपी के बारे में है। गुड एमएसपी निर्धारित की जाए, आज जो एमएसपी है, उसका मतलब क्या है? हम तो कहते हैं कि एमएसपी बड़ी अच्छी बात है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यह remunerative भी नहीं, या तो लाहे बंद हो। इसको दूसरे में बदलिए ताकि उसको गुड प्राइस मिले।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि अगर हम प्राइस निश्चित करते हैं, हमने जो 25 क्रॉप्स की प्राइस नियत की है, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट में 2 या 3 क्रॉप्स में एंटर करती है और किसी में नहीं करती है, इसलिए यह ensure करें कि गवर्नमेंट सारे में एंटर करेगी ताकि किसान को उसका फायदा मिले।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : सर, मैं सिर्फ सजेशन्स बता रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा यह है कि wheat और paddy का कंट्री में ग्लट आ गया। पानी की बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं, उनके लिए किसानों को हेल्प किया जाए और ऑल्टरनेटिव के रूप में किसान से जुड़ा हुआ जो काम है, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरीज़ है, उसमें हेल्प किया जाए। डेयरी इतना अच्छा है, फार्म के दोनों काम हैं - डेयरी और खेती। ये साथ-साथ चलते हैं, इसलिए डेयरी पर सब्सिडी दें, मिल्क पर सब्सिडी दें, एक रुपए प्रति लीटर दे दें, तो किसान डेयरी पर चला जाएगा, जो स्माल फार्मर्स हैं। इस समय हिन्दुस्तान में पंजाब जो सबसे अच्छा है, मैं उसके आंकड़े आपको बताता हूँ कि 70 परसेंट फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है और Johl Committee जो बनी थी ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा)** : कृपया आप समाप्त कीजिए।

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। Johl Committee में मैंने भी Sardar Johl के साथ काम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसान हैं? मैंने कहा कि हां, मैं किसान हूँ। मैंने Johl साहब से पूछा कि आप भी किसान हैं, तब वे कहते हैं कि मैं भी किसान हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बताइए कि किसान की पोजिशन क्या है? मैंने कहा कि आप यह सोच लीजिए कि अगर किसी एक किसान के पास सात एकड़ जमीन है, तो वह सोचता है कि हम तो बड़े किसान हैं, लेकिन वह चाहता है कि मेरा लड़का खेती न करे, वह peon बन जाए। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक किसान अपनी हालत से ज्यादा अच्छी एक peon की हालत को मानता है। ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्री पी. राजीव)** : धन्यवाद।

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : इसलिए मेरा यह सज़ेशन है कि आप उन क्रॉप्स पर भी ध्यान दीजिए, जैसे, ऑयलसीड्स, मेज़, बासमती आदि की एमएसपी आप नियत करें। आप प्रति वर्ष 55 हजार करोड़ की ऑयलसीड्स बाहर से मँगाते हैं। हमारी पैदावार बहुत ज्यादा है, हम कर सकते हैं, तो हम इसकी गुड प्राइस क्यों नहीं देते हैं? जैसे, कॉटन के एक किलो का रेट 38 रुपये है, लेकिन उसके एक मीटर कपड़े का मूल्य एक हजार रुपये है। इसलिए किसान को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। मैं किसी को नहीं कहता, क्योंकि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम मिनिस्टर साहब से यही विनती करेंगे कि सभी लोग यूनाइट होइए। मैं सबसे यह विनती करता हूँ कि हम सभी किसानों से यह वादा करके यहां आते हैं कि हम वहां जाकर आपकी बात करेंगे, देश की बात करेंगे, लेकिन हम यहां झगड़ने लग जाते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : इसलिए मैं सभी से यह विनती करता हूँ कि हम जिसका दिया खाते हैं, उसको बचाने में हम भी यूनाइट हों और उसके लिए कुछ करें ताकि उसकी हालत सुधरे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): You made very good points.

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : सर, आप बार-बार कह रहे हैं। मेरे दो-तीन प्वाइंट्स और हैं, लेकिन मुझे यहां अपनी बात खत्म करनी पड़ रही है। सर, देश की सबसे बड़ी बात यह है कि

फर्स्ट किसानी सेकंड इंडस्ट्री, इसलिए मेरा एक सजेशन यह है कि जब भी ऐसा सब्जेक्ट आए, तो इस पर दो दिन बहस होनी चाहिए । हमें इस पर बोलने के लिए 10 मिनट्स मिलने चाहिए । इतने कम समय में कोई क्या बोलेगा? इतने कम समय में तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हम किस प्वाइंट को बोलें, किस प्वाइंट को छोड़ें । इसलिए मेरी यह विनती है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए । आखिर हमारा काम क्या है? हम यहां बहस करने के लिए और अपने सजेशंस देने के लिए ही आते हैं । थैंक्यू सर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Now, Shrimati Renuka Chowdhury – five minutes.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, the greatest challenge today that lies in front of mankind is to be able to grow food. More than 800 million people worldwide do not have enough to eat or access to food. Concern about food and its supply, where it comes from, what kind of food we grow, how much we waste, how we waste, how much we grow and whether we will have enough in the years to come is something that all of us are seized of nationally. Rising world and national populations that want to eat high-quality food, whether it is meat, vegetables or dairy products, for nutrition because of growing awareness and education, becomes the challenge.

In the first quarter assessment that we have done, India has fallen behind in the Millennium Development Goals of halving hunger by 2015. Declining per capita incomes, foodgrain availability and unequal distribution have serious implications. आखिर हम किस बात पर बहस किए जा रहे हैं? हर मेम्बर खड़े होकर यह कहते जा रहे हैं कि किसान के हालात बहुत बुरे हैं । यह वास्तविकता है । क्या हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जिनसे हम कोई अंदाजा लगा सकें कि food crop से cash crop में कितना बदलाव आया है? क्या हम अपनी पॉलिसी में यह लागू करेंगे कि जहां अनाज और धान उग सकते हैं, उस जमीन को हम SEZs में या industrialization और industrial component में नहीं देंगे, because you have to conserve. अभी संजय सिंह जी बता रहे थे कि eucalyptus ने परेशानी बढ़ा दी है । This was the national policy. हमने कहा कि eucalyptus बहुत अच्छा प्लांट है, आप लगा दीजिए । बाद में हमें यह पता चला कि जहां अनाज उगता था, जहां सोना उगता था, वहां eucalyptus लगाकर हमने उस जमीन को बंजर बना दिया, क्योंकि eucalyptus उस जमीन के सारे पोटैशियम एवं उसकी पौष्टिकता को खा गया ।

सर, यह बात सभी कह रहे हैं कि वे सुसाइड करते हैं । मैं किसान हूँ । आप मानें या न मानें, मगर मैं खेती-बाड़ी करती हूँ । बदनौर जी बहुत अच्छी तरह से यह जानते हैं कि वास्तविकता में मैं हर सीज़न में अपनी जमीन जोतती हूँ । मेरे कष्ट क्या हैं? अगर मेरे क्रॉप्स फेल हो गए और मैं बैंक में गई, तो मुझे दूसरा ऋण नहीं मिलता है । हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं होती है । अगर एक बार हमारी फसल गई, चाहे उसका कारण बीज की कमजोरी हो, उसमें मिलावट हो या चाहे कई अन्य कारणों से हमारी फसल खत्म हो गई, तो हमें दूसरा ऋण नहीं मिलता है । आप waiver of loan करते हैं और बैंक पेमेंट्स को stagger करते हैं, मगर हम पर सिम्पल इंटरेस्ट के बदले कम्पाउंड इंटरेस्ट को लागू करते हैं । आज अगर लग्जरी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको

[Shrimati Renuka Chowdhury]

सॉफ्ट लोन इजी क्वार्टरली पेमेंट पर मिल जाते हैं, ई.एम.आई. और इंस्टॉलमेंट पर । मगर ट्रेक्टर खरीदने में हमें नहीं मिलता है, कोई छूट नहीं मिलती है । When your land is distributed so badly and you have small land holdings, you have to have an approach policy which will keep your land and give it for value addition crops and, therefore, we have to do National Crop Planning. आज के दिन वास्तविकता में अगर आप देख लीजिए एक जमाने में असम जैसे इलाके में, there was nothing happening in agriculture. They are water rich. When one lakh tubewells were set up in Assam, it altered the profile of that State, and, it altered the demand and supply of what is happening across the country. So, you have to have crop planning because of global heating today and because of changing weather and its vagaries. यह हालात थे कि we were importing moong dal from Myanmar. If you have crop planning, if you can grow cumin in arid areas, you can give them compensation or incentivize them. MSP was a fine thought when the time was right for it. Today, you are in open competitive market. You need to incentivize. You have to check your regions. You have to have soil health maps of all States and Districts, and, you should be able to grow crops which are conducive to your soil, water, weather and other conditions. ...(*Time-bell rings*)...

This will keep India in sustainable development and we will be able to give food and sustenance to the farmers as well as to the children when India is facing sub-Saharan African region malnutrition. Hunger does not create poverty; poverty creates hunger. The farmers who grow the crop have no access to food resource or land resources, and, because they are in that condition, they are unable to access the very food that they grow. What is your marketing strategy today? All agriculture markets are cesspools of intermediary men. हर मार्केट में आप देख लीजिए, किसान के मार्केट में एंटर करते ही इस कोने से उस कोने पर जमीन आसमान का रेट का फर्क पड़ता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: They are robbed in the very agricultural market that we have created for their facility and for their सहूलियत, which we do not look at. Sir, the crop insurance has to be given national priority. We can't sit and talk in Parliament. बार-बार हम यहां मातम करते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है । क्यों करते हैं आत्महत्या? हम अपने परिवार के लिए शहीद हो जाते हैं । एक बार हमने कहीं से मार्केट में चूंकि बैंक हमें दूसरा ऋण देता नहीं है तो हम चले जाते हैं उनके चंगुल में जो हमें बहुत बड़े ब्याज पर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, it is in public interest. उसके बाद उस पर सूद पर सूद चढ़ता चला जाता है । उसके बाद हमारे चार बम्पर क्रॉप्स होने से भी, we cannot

recover from this loan. This is why the small and tiny farmers with landholding from zero to 2 ½ acres and farmers with landholding from 2 ½ to 5 acres must be treated separately because necessarily the small landholdings are held by the backward farmers, by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe farmers and also the OBCs who do their farming and tilling. These people should be given crop planning. Otherwise, what they are doing is copycat farming of the big farmers. If there is a farmer with 100-acre land growing mirchi, and, there is a farmer with 2½ acre land also growing mirchi, obviously, the market dynamics will play and the rates will drop, and, it will not be a sustainable income for the small farmer.

Sir, coming to recharging of water aquifers, I would say that underground water resources इतने डिप्लीट हो गए हैं कि इसमें अलग-अलग नई-नई बीमारियां निकल रही हैं, and, we are over-utilizing synthetic fertilizer. At one time, synthetic fertilizer brought the Green Revolution but today it is going against. You have to stop this overuse of the synthetic fertilizer. Subsidy should be given also for liquid fertilizer because you have given subsidy on drip irrigation, and when you give it on drip irrigation, the farmer is denied subsidy on liquid fertilizer, which is mandatory for drip irrigation. Otherwise, you cannot fertilize your plants through hydroponics.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay; thank you.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: So, you have to be able to have a policy that is clearer, wider, more comprehensive and more integrated for us to prevent farmers' suicide, and it should become the national mission. Everyone mentioned the M.S. Swaminathan Report. There are some very valuable suggestions which are very doable and applicable to the Government, and we should be able to apply them. Industrial monocultures versus diversified agro ecologically managed small holding farming is the need of the hour today. With so much science and technology, awareness and knowledge, it is an easily doable thing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude. Now, Shri A.V. Swamy.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, this is such a complex subject. You can't really finish it in this time.

MR. VICE-CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I am concluding. There is also an acute shortage of transfer ...(*Interruptions*)...

**श्री अनिल माधव दवे** (मध्य प्रदेश): सर, संजय जी को आपने बैठा दिया । ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती रेणुका चौधरी** : आपको क्या एतराज है, जो अभी मैं बोल रही हूँ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude.

**श्री अनिल माधव दवे** : मैं आपसे नहीं कह रहा था, उपसभाध्यक्ष जी से कह रहा था ।

**श्रीमती रेणुका चौधरी** : तो आप मेरा समय क्यों ले रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Please conclude, Renukaji. Sanjayji is a very disciplined Member. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We do not have enough transfer of knowledge from the laboratories to the ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): He is only supporting Sanjayji. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I appreciate, but don't interrupt me. Thank you very much.

Sir, we need to bring technologies from institutes like ICAR and all into the ground and to be able to facilitate the farmer in this knowledge.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay. Thank you.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We also need to have young people involved in farming.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay. Now, Shri Ramdas Athawale. ...(*Interruptions*)... You have already taken ten minutes.

**श्रीमती रेणुका चौधरी** : आज किसान के बच्चे खेती-बाड़ी नहीं करना चाहते हैं । यह वास्तविकता है । So, not only must we grow more food, we must also grow more people interested in growing more food. Thank you very much.

**श्री रामदास अठावले** (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय,मैं कहना चाहता हूं -

"इस देश का किसान हमेशा रहता है परेशान,
राधा मोहन जी उनकी तरफ देना होगा आपको ज्यादा ध्यान,
वरना ध्वस्त हो जाएगा अपने देश का किसान।"

मुझे लगता है कि किसान अपने देश में कष्ट करके, अपनी जिंदगी बरबाद करके सभी लोगों को जिंदगी देने का काम करता है । वह फसल उगाने का काम करता है, अनाज देने का काम करता है, लेकिन किसान को जिस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस तरह की उसे नहीं मिलती है । हमारे यहां महाराष्ट्र में नवंबर महीने में विदर्भ, मराठवाड़ा, नासिक डिवीजन में कम से कम 120 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं । उसका कारण साहूकार लोगों से लिया गया कर्जा है और उस कर्जे के कारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में वे आत्महत्याएं कर रहे हैं । मंत्री महोदय से निवेदन यह

है कि कांग्रेस वालों ने तो कुछ नहीं किया है, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है । किसानों को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है । साहूकारों से लिया कर्जा किस तरह से माफ कर सकते हैं? साहूकारों के कर्जों के ऊपर भी कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वे 20 परसेंट इंटरेस्ट भी लेते हैं । इसलिए फाइनेन्स मिनिस्ट्री को साहूकारों से लिए जाने वाले कर्जे के लिए कोई सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है । इनसे किसानों को बचाने की आवश्यकता है । किसानों को अगर बचाना है, तो खेत-मजदूरों को भी बचाना चाहिए । खेतों में काम करने वाले जो खेत-मजदूर हैं, उनकी समस्याओं की तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है ।

महोदय, हमारे महाराष्ट्र में अकाल है, बारिश नहीं है । किसान तो फसल उगाने का काम करता है और अगर बारिश नहीं आती है तो पूरा ध्वस्त हो जाता है । कई बार बहुत बारिश आती है, तो जो फसल अच्छी हुई होती है वह भी बरबाद हो जाती है । उन किसानों को बचाने के लिए हम सभी को काम करना चाहिए । महाराष्ट्र के लिए इस समय कम से कम 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अकाल काफी है, कम से कम 60 परसेंट गांवों में अकाल है, इससे किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं । राज्य सरकार की तरफ से जो मांग की गई है, मैंने उसमें 500 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं, क्योंकि उतनी आवश्यकता है । इसलिए पांच हज़ार करोड़ रुपया महाराष्ट्र के लिए देना चाहिए । साथ ही, किसानों को बचाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उनका जो अनाज होता है, जो उत्पादन होता है, उसकी कीमतें डिसाइड करने के संबंध में भी सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ज़रूर किसानों को न्याय देने का काम करेगी । उधर बैठे हुए लोगों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । आज तो वे बड़े-बड़े भाषण कर रहे हैं, लेकिन जब इतने सालों तक सत्ता आपके हाथ में थी, तब आपने किसानों को बरबाद करने का काम किया, इसलिए हम उधर से इधर आ गए और आपको यहां से वहां जाना पड़ा है । अभी दस साल आप आराम कीजिए । हम किसानों को न्याय देने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ज़रूर किसानों को न्याय देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है । ...(**व्यवधान**)... आप तो वहीं रहेंगे । आप वहां रहिए, आप उधर आराम कीजिए । आप चाहे मोर्चा निकालें या रैली निकालें । रैलियां निकाल-निकाल कर हम थक चुके थे, इसलिए अब आप रैली निकालो, हल्ला बोलो, मोर्चा निकालो, हंगामा करो, हम आराम से बैठेंगे । ...(**समय की घंटी**)... इसलिए राधा मोहन जी, जो किसान के बच्चे हैं, वे यहां बैठे हैं और पूरी बात जानते हैं । ...(**व्यवधान**)...

**श्री मुख्तार अब्बास नक़वी** : ये खुद भी किसान हैं ।

**श्री रामदास अठावले** : हां, किसान के बेटे हैं, मतलब किसान हैं । ...(**व्यवधान**)... वे किसान हैं, इसलिए किसानों की समस्याओं के बारे में जरूर हल निकालेंगे और किसानों की आत्महत्याओं को रोकने का प्रयास करेंगे । उनकी फसल, उनके अनाज की मैक्सिमम कीमत कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में भी निर्णय लेंगे । ...(**समय की घंटी**)... लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, पांच साल तो रुकना ही पड़ेगा । आप तीन महीने में ही पूछ रहे हैं कि सौ दिनों में क्या किया? आपने पचास साल में क्या किया? आपने जो किया, वही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है । हम किसानों को न्याय देने का काम करेंगे और इसलिए राधा मोहन जी, आप अच्छे निर्णय लीजिए ...(**समय की घंटी**)... और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है । जय भीम, जय भारत !

**कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि संकट पर चर्चा के लिए जो लोग इस विषय को लाए हैं, मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्मरण है कि पिछली बार सूखे पर हम लोगों ने चर्चा की थी और उसका बहुत लाभ हुआ था। जब चर्चा होती है, तो सरकारी अधिकारियों के साथ बैठने पर आंकड़े मिलते रहते हैं, लेकिन जब सभी माननीय सांसद किसी चर्चा में भाग लेते हैं, तो कई बातें ऐसी हैं, जो मंत्रालय के अंदर बैठकर पता नहीं चलती हैं या फिर हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां जो जानकारी मिलती है, वही पर्याप्त नहीं होती है।

(**श्री उपसभापति** पीठासीन हुए)

जब यहां चर्चा होती है और चारों तरफ से जब जानकारियां आती हैं, तो वे भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों ने राजनीति से अलग हटकर किसान की चर्चा की। अब दिग्विजय बाबू हम लोगों के बीच अपवाद हैं क्योंकि राजनीति का करंट उनका ज्यादा चलता है, लेकिन हम सब लोगों ने किसान की चिंता की है और यह स्वाभाविक है, क्योंकि दुनिया का जो भूगोल है, उसका मात्र 2.4 प्रतिशत हमारे पास है और जो जल संसाधन है, उसका मात्र 4 प्रतिशत हमारे पास है। अब ढाई प्रतिशत भूगोल और चार प्रतिशत जल संसाधन पर यह जिम्मेदारी है कि वह सत्रह प्रतिशत आबादी और पंद्रह प्रतिशत पशुधन को आहार उपलब्ध कराए। स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ी चुनौती है। फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सूखा और कश्मीर, आंध्र, तमिलनाडु में बाढ़, हुदहुद आदि स्थितियों का भी सामना वहां के किसान कर रहे हैं। हमारी कई योजनाओं में विसंगतियां भी हैं और कई योजनाओं में यदि विसंगतियां नहीं हैं, तो उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जो हम सबकी चिंता के विषय हैं - कृषि बीमा योजना से लेकर कृषि आमदनी, कृषि आदानों का बढ़ता मूल्य तथा अन्य कई बातें हैं, जिनकी सबने अलग-अलग चर्चा की है - ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूमि अधिग्रहण, जीएम फूड, आत्महत्या, ये सब उन्हीं विसंगतियों में से उपजे हुए elements हैं, तत्व हैं। यकीनन हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इन विसंगतियों के बावजूद भी जब डाण् राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम कृषि मंत्री बने होंगे तो उन्होंने थोड़ी चिंता जरूर की होगी। फिर इस पद पर एक से एक व्यक्ति आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सभी लोग, जगजीवन बाबू भी थे, सब लोगों ने निश्चित रूप से चिंता की होगी, समाधान भी खोजा होगा, लेकिन हम जितना समाधान खोजते गए, उतनी विसंगतियां भी बढ़ती गयीं। फिर भी हमारा प्रयत्न लगातार रहा। यदि यह प्रयत्न न होता तो जो कृषि विकास दर 9वीं, 10वीं योजना में दो-ढाई प्रतिशत थी, वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर चार प्रतिशत तक नहीं पहुंचती। हमने प्रयत्न किया। वह प्रयत्न किसने किया, किसके कारण उपलब्ध हुई और किसके कारण नुकसान हुआ, यदि इस चर्चा में पड़ेंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी दिग्विजय बाबू ने कहा कि दस वर्षों के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में जो हम आज करते हैं, उसकी उपलब्धि आज या दूसरे दिन ही नहीं मिलती। इन दस वर्षों के अंदर जो उपलब्धि हुई होगी, उसके पहले पांच वर्ष कुछ जरूर किया होगा, जिसके कारण वह उपलब्धि प्राप्त हुई। उसका योगदान अवश्य रहा होगा क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि आज बीज बोकर आज ही फसल नहीं काटते, बीज बोने के कुछ समय बाद फसल कटती है। उसके पहले पांच वर्षों तक निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कुछ प्रयत्न हुए होंगे। उस पांच वर्ष में भी यदि कुछ परिणाम आए होंगे तो उससे पहले जो लोग रहे होंगे, उन्होंने प्रयत्न किए होंगे। आज जो कुछ भी है, निश्चित रूप से दस वर्ष तक आपने जो

प्रयत्न किए, उसका परिणाम है । अब ये परिणाम अच्छे हैं या बुरे हैं, इसमें हम नहीं फंसेंगे - अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं । आप आत्महत्या की चर्चा कर रहे थे । आपसे ज्यादा हमारे माननीय आनन्द शर्मा जी चर्चा कर रहे थे । आत्महत्या निश्चित रूप से बहुत अधिक चिंता का विषय है । कोई भी व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो इससे बड़ी घटना डेमोक्रेसी के अंदर नहीं हो सकती, वह किसी न किसी संकट के कारण ऐसा करता है । लेकिन बोलते समय हम ऐसे-ऐसे आंकड़े बोलते रहते हैं, जिससे लगता है कि पूरे देश में कृषि के कारण आत्महत्या हो रही है, खेती के कारण आत्महत्या हो रही है। यदि हम 2013 का आंकड़ा देखें तो 2013 के दरम्यान 1 लाख 34 हजार लोगों ने आत्महत्या की । यह आंकड़ा है - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का । 1985 से उसमें कॉलम रखा जाता है, कृषि और खेती से संबंधित परिवारों का । उसने बताया है कि इन 1 लाख 34 हजार में से खेती एवं कृषि के कारण 11,772 लोगों ने आत्महत्या की । इन 1 लाख 34 हजार लोगों में से 11,772 कृषि परिवार के लोगों ने आत्महत्या की । हमें नहीं पता, यह परसेंटेज कितना होगा?

**श्री दिग्विजय सिंह** : 9 प्रतिशत ।

**श्री राधा मोहन सिंह** : जी, 9 प्रतिशत । जितनी आत्महत्याएं देश में हुई, आत्महत्याएं किसी भी कारण से हुई हों, वह ठीक नहीं है, लेकिन 9 प्रतिशत कृषि परिवार के लोगों ने आत्महत्या की । आत्महत्या सिर्फ कृषि के कारण या ऋण के कारण नहीं होती । कई बार हम लोग लिखते हैं, "कृषि परिवार।" अगर पति-पत्नी में कुछ हुआ, उसके कारण आत्महत्या की गयी और उसके कॉलम में व्यवसाय "कृषि" लिखा है तो ऐसी आत्महत्याएं 11,772 हैं । राज्य रिपोर्ट करता है कि खेती के कारण, कर्जे के कारण कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं । आप 2013 के आंकड़े देखेंगे, तो उसमें 11,772 में से कुल 511 कृषि कारण से आत्महत्याएं हुई हैं । ये आंकड़े हैं, हम गलत-सही पर नहीं जाते हैं । इन 511 में महाराष्ट्र में 407 और शेष देश के बाकी हिस्सों में हुई हैं । वर्ष 2012 में 13,754 कृषि परिवारों में हुई आत्महत्याओं में 919 कृषि कारणों से हुई हैं, जिनमें 662 महाराष्ट्र में हुई हैं । अभी महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं, देश में कम भी हों, ज्यादा भी हों, सब चिंता का विषय है । पिछले साल 50 प्रतिशत से ज्यादा और इस बार तो हमको लगता है कि 80 प्रतिशत 2013 का । अब ये जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इसमें सरकार की नीतियों में भी गड़बड़ी हो सकती है । सरकार की जो भी नीतियां बनी हैं, स्वामीनाथन कमीशन की चर्चा हम सब कर रहे हैं, अच्छी नीति बनी है, नई नीति बनाने की कोई जरूरत नहीं है । उनकी रिपोर्ट के बाद जो किसान नीति बनी है, उसमें 200 से ज्यादा रिकमण्डेशन्स हैं और 175 से 180 रिकमण्डेशन्स देश में लागू हुई हैं । 12वीं योजना के पहले 51 स्कीम्स से ज्यादा चलती थीं, उनमें ओवरलैपिंग ज्यादा थी, तो फिर इसको पांच योजना, पांच मिशन और राज्यों के लिए "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" बनाया गया । इनका क्रियान्वयन ठीक से होना चाहिए ।

अब क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? मैं चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में गया था, वहां पर 20 दिन था । हमने 20 दिन के अंदर जानकारी ली कि पिछले 10 साल से जो भारत सरकार की सिंचाई की योजनाएं हैं, वे जमीन पर नहीं उतर रही हैं । मैं एक दिन शाहपुर चला गया, जो वहां से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है । वहां जो डैम बना है, वहां से पानी मुम्बई, नई मुम्बई सबको जाता है, लेकिन हम उसके आसपास के इलाके में लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में घूमे, वहां पर एक भी सिंचाई की योजना नहीं, वहां पर खेती पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है, मतलब यह कि सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो सका । जो 11 पंचवर्षीय योजनाएं बनीं और उनके तहत जो पैसे गए, जो 2013-14 में पैसा गया था, उसमें से 800 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए ।

[श्री राधा मोहन सिंह]

पशुपालन की बात हो रही है । पशुपालन की मद में जो पैसे गए थे, उनमें से भी 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ । अकेले महाराष्ट्र राज्य की हालत ऐसी नहीं है, अधिकतर राज्यों की हालत ऐसी है कि यहां से जो पैसे जाते हैं, वे खर्च नहीं हो पाते हैं । यदि खर्च भी हो जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ पाती है । अब महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार 2013-14 में लगभग 500 करोड़ रुपया एसडीआरएफ का गया। अब वहां सूखा पड़ा है, हमारी टीम गई है, वहां एनडीआरएफ का भी पैसा गया था । जब मैंने परसों देखा कि इस बार उसका 405 करोड़ एसडीआरएफ में जाना है, तो क्यों नहीं गया? तो पता चला कि पिछली रिपोर्ट नहीं आई है । हमने वहां के कमिश्नर से बात की, फिर मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, तो हो सकता है आज रिपोर्ट आई हो । जब सूखा पड़ा तो बहुत पहले लोक सभा के अंदर और यहां भी हमने बताया था कि पिछली बार जब हम लोगों ने सूखे पर चर्चा की थी, जो रिपोर्ट सब जगह से आ रही थी और डेढ़ महीने बाद मानसून आया था, लेकिन किसी राज्य सरकार ने अपने यहां सूखा घोषित नहीं किया । सूखा तो राज्य सरकार ने घोषित करना है, लेकिन किसी राज्य सरकार ने सूखा घोषित नहीं किया । जुलाई-अगस्त में सामान्यतः सूखे की घोषणा होती है । जब घोषणा नहीं हुई और जब सदन में चर्चा हुई, तब पता लगा कि राज्य के कई हिस्सों में सूखा है । राज्य सरकार नोटिफिकेशन करती, अधिसूचना भेजती, मेमोरेंडम भेजती, तभी तो पता चलता । हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा, हम राजनैतिक बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बशिष्ठ बाबू नहीं हैं, जहां का राजा व्यापारी होगा, वहां की प्रजा कंगाल होगी, आज वह युग नहीं है । आज व्यापारी सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं बैठा है, आज एक मजदूर का बेटा, जो गांव और गरीब का दुख जानता है, वह बैठा हुआ है, इसलिए यह स्थिति अब नहीं आने वाली है । मैंने प्रधान मंत्री जी के संज्ञान में यह लाया कि आज तक सूखे की रिपोर्ट कोई भेज नहीं रहा है, डिक्लेयर नहीं कर रहा है और कई हिस्सों में इस प्रकार की स्थिति है, तो उन्होंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाकर चार बातें तय की थी कि जहां 50 प्रतिशत से कम वर्षा 15 दिनों तक नहीं हुई, उस इलाके में, उस जिले में डीज़ल पर राज्य सहायता दी जाए । यदि बागवानी नष्ट हो रही है, तो 35,000 रुपए प्रति हैक्टेयर दी जाए । बीज पर राज सहायता बढ़ायी जाये, इसी प्रकार से चारा विकास कार्यक्रम के लिए पैसा दिया जाए और जो विदेशों से खली के रूप में चारा आयात करते हैं, उस पर आयात छूट समाप्त की जाए । इसका परिणाम हुआ है । बिहार में डीज़ल पर राज्य सहायता देनी शुरू की गई । उत्तर प्रदेश, कर्णाटक, महाराष्ट्र ने उस योजना के तहत चारा विकास कार्यक्रम के लिए पैसा मांगा । महाराष्ट्र ने बागवानी मिशन के तहत भी पैसा मांगा है और चारा विकास के क्रम में हमने उसको पैसा भी भेजा है । लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार, दोनों को संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा । बिना नई नीति बनाए, जो पुरानी नीतियां हैं, उनमें कहीं विसंगतियां हैं, उनको ठीक करके राज्य सरकार और भारत सरकार इसको करे । अब जैसे यहां हमारे अधिकारी बैठे हैं और राज्य के अधिकारियों की साल में एक या दो बार मीटिंग बुलाते हैं, बैठक करते हैं । यहां के अधिकारी नहीं जाते हैं, वहां के अधिकारियों के साथ नहीं बैठते हैं । कृषि सचिव हैं या अन्य ज्वाइंट सेक्रेटेरीज हैं, ये सचिवालय से निकलकर, राज्यों के अंदर जाएं और राज्यों के अंदर लोगों के साथ बैठें । कई राज्यों में प्रवृत्ति जगी है । हम अभी तक राजनीतिक विरोध पर भी यह काम करते थे और आज भी कहीं-कहीं यह लक्षण दिखाई दे रहा है । लेकिन मुझे खुशी है कि केरल के अंदर हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और जो घटना अभी कश्मीर की आई थी, उससे पहले हम वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे ।

हम आंध्र के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, तो हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ भी जाकर बैठे। हमारा यह प्रयास है कि हम जनवरी महीने तक सभी राज्यों में जाकर अपने अधिकारियों को लेकर उनके अधिकारियों के साथ बैठें, ताकि जो योजनाएं हैं, उनका ठीक से क्रियान्वयन कर सकें। कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि 51 से ज्यादा योजनाएं चल रही थीं, ओवरलैपिंग हो रही थी, तो 11 योजनाएं, 5 मिशन, 5 योजनाएं और राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हमारी ये 11 योजनाएं चल रही हैं और उसके कारण भी पिछले वर्षों में प्रगति हुई है। हम कह सकते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है, लेकिन उस कारण से प्रगति हुई है और कृषि ऋण प्रवाह में वृद्धि की भी लगातार पहल हो रही है। जो 7 प्रतिशत ऋण की चर्चा कर रहे थे, यह ऋण 4 प्रतिशत पर ही दिया जा रहा है। जो समय पर लौटा देते हैं, उनको 4 प्रतिशत ही देना पड़ता है और तीन प्रतिशत बैंकों को सरकार देती है। वह ऋण आज भी 4 प्रतिशत का है, बल्कि उसमें इस वर्ष राशि बढ़ाई गई है और कैबिनेट ने कल ही इसका निर्णय लिया है। लेकिन यह कृषि ऋण प्रवाह जब 2011-12 के दौरान देखेंगे, तो जो शॉर्ट टर्म लोन हैं, उस पर 4 प्रतिशत ब्याज है। 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह 5,11,000 करोड़ रुपए था। 2012-13 में 5,75, 000 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह की तुलना में सौ लाख करोड़ से ज्यादा दिया गया। फिर 2013-14 में जो 7,00,000 करोड़ का था, वह 7,11,000 करोड़ दिया गया और 2014-15 के लिए आठ लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी ऋण की अन्य पहलों में कृषि ऋण पर ब्याज की दर में समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर चार प्रतिशत रखी गई जो अभी भी जारी है। 1998-99 में किसान क्रेडिट की भी शुरूआत की गई थी। जो अल्पावधि के सहकारी ऋण हैं, पुनरुत्थान पैकेज, वैद्यनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर 25 राज्यों की सरकारों ने, भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 17 राज्यों में 53,202 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां थीं, तीन राज्यों में 30 केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित, 1510 अयोग्य प्राथमिक कृषि सहायता सहयोग समिति, उड़ीसा में 13 केंद्रीय सहकारी बैंक्स के पुनः पंजीकरण के लिए नाबार्ड ने भारत सरकार संस्थान के रूप में 9,000 करोड़ रुपये 2010 तक रिलीज़ किए थे। अब हाल ही में, जब से हम लोग आए हैं, तो चार राज्यों के तीस जिलों के कमजोर सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने का दायित्व, जो राज्य सरकारों का था, फिर भी इनकी अनिश्चित स्थिति पर विचार करते हुए भारत सरकार ने पुनर्जीवन संबंधित विशेष पैकेज के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और उनको उपलब्ध कराया। इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार बदलने से ...**(व्यवधान)**...

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** (उत्तर प्रदेश) : पाला पीड़ित और अतिवृष्टि पीड़ित किसानों को देवी आपदा की श्रेणी में नहीं मानते हैं ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ओला पीड़ित और अतिवृष्टि पीड़ित किसान जो हैं, जिनकी फसलें बरबाद होती हैं ...**(व्यवधान)**... प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाये जिससे मदद मिल सके।

**श्री राधा मोहन सिंह** : हम आपको बीच में बोलने का मौका देंगे, अभी बैठिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : मेरा सुझाव है कि पाला पीड़ित व अतिवृष्टि पीड़ित किसानों को देवी आपदा में शामिल करें, भारत सरकार गाइडलाइन्स तैयार करे।

**श्री राधा मोहन सिंह** : सरकार पिछले दिनों से क्या-क्या कर रही है, उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनकी चर्चा में बहुत समय लगेगा, लेकिन कई तरफ से जरूर सवाल आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सवाल कई बार उठे हैं, तो मैं इन पर थोड़ा टाइम जरूर लूंगा कि 492 नई स्वायत्त परीक्षण प्रयोगशालाओं और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमने योजना बनाई है । मंत्रालय के द्वारा अगले तीन वर्ष के अंदर 568.54 करोड़ रुपये के परिव्यय से सॉयल हेल्थ कार्ड की महत्वाकांक्षी स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है । देश में पता नहीं है, लेकिन जो जोतदार हैं, शायद साढ़े चौदह करोड़ जोतदार हैं, इनमें छोटे जोतदार ज्यादा हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी जमीन में कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा देनी है, कितनी खाद देनी है । हम अपने गांव में देखते हैं कि यदि हमारा एक पड़ोसी एक बोरी यूरिया छिड़कता है, तो दूसरा डेढ़ या दो बोरी यूरिया छिड़कता है कि हमारी ज्यादा फसल होगी । उसको पता नहीं है कि जमीन में भी जीवन है । हमने आज तक किसानों को बताया नहीं है और उसी का परिणाम हुआ - हिरत क्रांति हुई थी, यह अच्छी बात हुई थी, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग हो रहे हैं । हम समझते हैं कि आज भी पंजाब की हजारों एकड़ जमीन मर चुकी होगी । जमीन में भी जीवन है, इस बात से नीचे तक, किसानों तक ले जाने के लिए तीन साल के अंदर और प्रत्येक तीन वर्ष पर उसकी पॉकेट में उसकी जमीन का, उसकी जोत का सॉयल हेल्थ कार्ड देने के लिए यह व्यवस्था की गई है । 56 करोड़ रुपये के आवंटन से सौ मोबाइल सॉयल लेबोरेट्रीज़ का भी अनुमोदन किया गया है । कृषि उत्पाद में मूल्य के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोर्स और इस प्रकार के 500 करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों की अनिश्चितता तथा कठिनाइयों को दूर करने की भी हमारी योजना है । एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, उनकी आधारभूत संरचना के लिए सौ करोड़ रुपये की घोषणा की गई है । सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपये कम हैं, अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि बुलेट ट्रेन के लिए इतना और सिंचाई के लिए इतना! देखिए, इस वित्तीय वर्ष के चार महीने बीतने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की, आज भी 60 प्रतिशत जमीन असिंचित है । हम सभी लोग भाषण में यह बात कह रहे थे और मुझे याद है कि जब मैं 1989 में एमपी बना था, तो गांव से आठ किलोमीटर पैदल गया था, गांव में दस-दस किलोमीटर तक कोई सड़क दिखाई नहीं देती थी । एक "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" चली थी । यदि आज भी आप गांव में सड़क देखेंगे तो "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" से आपको सहसा अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ जाते हैं । उसके बाद यह पहला अवसर है, जब देश के प्रधान मंत्री ने "प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना" प्रारंभ की है । सवाल 1000 करोड़ रुपये का नहीं है, सवाल उस दिशा का है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं । हम सदन में यह घोषणा करना चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तान के हर जोतदार के खेत पर, जो असिंचित भूमि है, वहां पानी पहुंचा कर रहेंगे । सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं । 500 करोड़ रुपए से भी, लेकिन आप योजना तो शुरू किरए, आप संकल्प तो व्यक्त करिए । इस सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है । इतना ही नहीं, हमारा कंसेप्ट नोट भी तैयार हो गया है और शीघ्र हमारी एक योजना जमीन पर आएगी । इरिगेशन के जितने बड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उन सब पर तेजी से काम शुरू हुआ है ।

इसी तरह से जब राजनीति की बात आती है, तो हम एक उदाहरण देना चाहते हैं । यह ठीक है कि आंध्र प्रदेश की सरकार हमारे साथ है, लेकिन तेलंगाना की सरकार हमारे साथ नहीं है । हम

वहां गए थे । मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मुझे वहीं जाने का मौका मिला था । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहां मेरा भोजन था । उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अन्दर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वह तेलंगाना के अन्दर रह गई है, हमारे यहां एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए । फिर हमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने चाय पर बुलाया । जब हम वहां गए, तो सारे अधिकारी बैठे थे । उन्होंने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वह आंध्र प्रदेश के अन्दर चली गई । प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की कि दोनों जगह, जहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी और जहां हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी । उन्होंने न सिर्फ घोषणा की है, बल्कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने जमीन आइडेंटिफाई करके भेजी और हमने दोनों को पैसा भेज दिया । इसी प्रकार से अभी राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की गई । हरियाणा, जो बगल का राज्य है और जहां धान, गेहूँ और बाजरा, इन्हीं की फसल में सारे किसान लगे रहते हैं, अब उनकी रुचि बागवानी की ओर बढ़ी है । जिनके पास खेत नहीं है, वे भी लीज पर खेत लेकर बागवानी कर रहे हैं । वहां भी हमारी सरकार ने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की घोषणा की । हमारी सरकार इसमें राजनीति नहीं करती । मैं मानता हूँ कि कोई सरकार राजनीति करती होगी, लेकिन यहां तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि आज जो देश का प्रधान मंत्री बना है, उसने गांव की गरीबी को नजदीक से देखा है, गांव की दुर्दशा को नजदीक से देखा है और वह गांव के दर्द को समझता है । इसलिए गांव, गरीब और किसान को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है । जब तक गांव, गरीब और किसान मजबूत नहीं बनेगा, तब तक देश को मजबूत बनाने का सपना कोई नहीं देख सकता । इसीलिए ये सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ।

इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गांव के अन्दर जो गरीब हैं, उनके पास बड़ी संख्या में देसी गायें हैं । संकर नस्ल की जो 20 प्रतिशत गायें हैं, वे तो कुछ बड़ी-बड़ी फर्मों के पास हैं, लेकिन जो 80 प्रतिशत देसी नस्ल की गायें हैं, उनके संवर्द्धन के लिए अगले तीन वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है । मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि इस वर्ष हमें 127 करोड़ रुपए खर्च करने थे, तो 123 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आ गए और सैंक्शन भी हो गए । ग्रामीण भंडारण योजना के जो पैसे थे, जो साल-साल भर तक बिल्कुल पड़े रहते थे, 6 महीने के अन्दर सारे सैंक्शन हो गए । मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि खेती और किसान को मजबूत बनाने के लिए नई-नई नीतियां बनें, लेकिन जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं, यदि हम सब उनको भी ठीक से लागू करने लगें, तो हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्ध्‍ध हो सकती है ।

इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, शायद 650 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और सबकी हालत बहुत खराब है । ऐसे 37 जिले तो ग्यारहवीं योजना में तय हुए कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा । जब यह तय हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री थे । उस समय 275 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए थे । मैं यह नहीं कहता कि उसके बाद 10 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ । 80-85 कृषि विज्ञान केंद्र 10 वर्षों में खोले गए । अभी 37 पुराने जिलों में, 24 नए जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र रहेंगे और जो 650 केंद्र पहले से हैं, उनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है । हमने तय किया है कि सबको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा कर जो पद रिक्त हैं, उनको भर कर एक साल के अन्दर उनको पूरा मजबूत बनाया जाए । प्रयोगशालाओं के अन्दर किसानों के लिए जो नए-नए बीज, नए-नए पौधे निकलते हैं, जो लैब में निकलते हैं, वे लैंड तक नहीं पहुंच रहे हैं ।

[श्री राधा मोहन सिंह]

चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए इसमें राज्य सरकार की भूमिका भी होती है । लेकिन इस क्षेत्र में हमने एक पहल की है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी इस काम में और तेज़ी लाई जाए । अब हम डाकिया के माध्यम से उन्नत बीज किसानों के घर पर भिजवा रहे हैं । अभी यह योजना 20 जिलों में शुरू की गई है । हमारी कोशिश है कि डाक विभाग के साथ हम एक समझौता करें और उसके माध्यम से इस योजना को पूरे देश के लिए शुरू करें । मैं यह एक उदाहरण बता रहा हूं, हालांकि दिखने में यह बहुत छोटा काम लग रहा है ।

इसके अलावा हम एक चीज़ और भी सोच रहे हैं । हमारे पास 6,000 के लगभग कृषि वैज्ञानिक हैं, जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ICAR से अटैच्ड हैं। लेकिन इस देश के अन्दर 20,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक हैं । बहुत से कृषि वैज्ञानिक राज्यों के अन्दर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर हैं, कॉलेजों के अन्दर हैं । ये जो 20,000 कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे भी निवेदन किया जा रहा है कि वे एक-एक गांव को गोद लें और एक-एक गांव में जाकर वे इस काम को करें । इसके लिए हम हर राज्य को पत्र भी लिख रहे हैं कि हर ब्लॉक में कम से कम दो पंचायतों को वे 'आदर्श कृषि पंचायत' बनाएं ।

फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात आती है । मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने सांसद आदर्श ग्राम में गया था । वहां पर 50 एकड़ जमीन में हमने नये किस्म का गेहूं का बीज बोने का काम शुरू किया है । जब उस 50 एकड़ जमीन में वह नये किस्म का गेहूं का बीज पैदा होगा, तो वह 200-300 क्विंटल के करीब होगा, उससे आसपास के गांवों को भी वह मिल सकेगा ।

हम लोग इतने-इतने नियम और कानून बना रहे हैं । एक हमारे प्रधान मंत्री जी ने सभी सेक्रेटरीज़ से कहा कि जिस ब्लॉक में तुम्हारी पहली पोस्टिंग हुई थी, एक बार उस ब्लॉक में जा करके देखिए कि जितनी योजनाएं आप बना रहे हैं, वे उस ब्लॉक में लागू हुई हैं या नहीं हुई हैं? इसके लिए केवल एक बार हम सब मिलकर संकल्प कर लें कि हमें यह करना है । हमने सभी माननीय सांसदों को पत्र लिखा है ।

यहां पर हमने एक नयी व्यवस्था शुरू की है । कृषि मंत्रालय के अन्दर एक लघु कृषि व्यापार संगठन (एसएफएसी) है, जो एक गांव में बीस किसानों का समूह बनाता है, 1000 किसानों का Farmer Producer Organization (FPO) बनाता है । उसके अंतर्गत इस प्रकार की 300 के लगभग organizations हैं, जो उत्पादन कर रही हैं । दिल्ली में 'किसान उत्पादक संगठन' के माध्यम से हमने एक किसान मंडी शुरू की है, जहां पर कोई बिचौलिया नहीं है । किसान सीधे वहां पर अपना सामान लाता है और बेचता है । एक प्रयोग के तौर पर हमने यह काम शुरू किया है और इसके लिए हमने सभी माननीय सांसदों को पत्र भी लिखा है । हमने उसमें कॉन्टैक्ट नम्बर भी दिया है कि आप इस नम्बर पर कॉन्टैक्ट करिए और अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना के तहत काम कीजिए ।

पूरे देश में सम्पूर्ण क्रान्ति आए, यह अच्छी बात है, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं से तो की ही जाएगी । माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' की बात कही है, अगर किसी को यह नाम ठीक नहीं लगता है, तो आप अपनी तरफ से कोई नाम देकर एक गांव या एक पंचायत को गोद लीजिए और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उनको वहां पर लागू

कीजिए, यही हमारी आप सभी से विनती है । हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो नई पहल की है, जो नई योजनाएं लाई गई हैं, जो नई नीतियां लाई गई हैं, उनको अपने-अपने क्षेत्रों में आप लागू कीजिए । नीति तो आपकी भी खराब नहीं थी और हमारी भी खराब नहीं है, नीतियां भले ही खराब हो सकती हैं । आपकी नीतियां अच्छी थीं या खराब थीं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उसका परिणाम तो देश भोग ही रहा है । हमारी नीयत ठीक है और जो नीतियां हैं, उनको ठीक से जमीन पर लागू किया जाए, हम सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं ।

माननीय सदस्यों के द्वारा अलग-अलग सवाल उठाए गए थे । दिग्विजय बाबू ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे । कृषि बीमा योजना के सम्बन्ध में एक सवाल उठाया गया था । मैं आपको बताना चाहूंगा, 11वीं योजना से पहले जो गाइडलाइन थी, 12वीं योजना के बाद उस गाइडलाइन को बदल दिया गया । जब उस गाइडलाइन को बदला गया, तो उसमें कई विदेशी कम्पनियों को भी जोड़ दिया गया । मेरे कृषि मंत्री बनने से पहले वह सर्कुलेट हुआ । जब हम कृषि मंत्री बने, तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा की सरकारें आने लगीं । उन्होंने यह ऑब्जेक्शन उठाया कि सरकार ने यह जो कृषि बीमा योजना की गाइडलाइन भेजी है, जिसमें 12वीं योजना में परिवर्तन किया गया था, इसमें बहुत विसंगतियां हैं, हम किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं करेंगे । इसमें बहुत सी विसंगतियां हैं । हम किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं करेंगे । हम पुरानी को ही लागू करेंगे । हालांकि पुरानी में भी बहुत विसंगतियां हैं, इस बात को उन लोगों ने कहा है और यह कहा है कि हम पुरानी को लागू करेंगे, इसमें तो और ज्यादा विसंगतियां हैं । तब हमने एक आदेश दिया कि अब जिस सरकार को पुरानी गाइडलाइंस या नयी गाइडलाइंस, इनमें से जो भी ठीक लगता हो, उसको अभी चालू करे और अगले वित्तीय वर्ष के पहले, यानी 31 मार्च के पहले, एक नयी कृषि बीमा योजना हो । दिग्विजय बाबू ने कहा कि इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है । यह बात ठीक है कि इसका क्रियान्वयन ठीक नहीं है । लेकिन, विसंगतियां भी उसमें ऐसी हैं कि जैसे-जलगांव में जो मौसम आधारित बीमा है, वहां केले की फसल का नुकसान हुआ । वहां जो यंत्र लगाया, वह ऐसा था कि नुकसान 15 किलोमीटर में हुआ और उसने 2 किलोमीटर के एरिया का रिपोर्ट किया । अब वहां के किसान 2012 से आन्दोलन करते-करते तंग हैं । वे हमारे पास भी आए थे । मैं वहां गया था । वहां बीमा कम्पनीज़ को बुलवाया था । हमने नोटिस किया । उसने स्वीकार किया कि मेरा यंत्र खराब था। तो नयी कृषि बीमा योजना के लिए सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र दिया है । कई राज्य सरकारों ने इस पर सेमिनार भी आयोजित किया है तथा अपना प्रारूप और सुझाव भी भेजा है । हमारी तीन बैठकें हो चुकी हैं । एक बार हम सभी प्रमुख नेताओं के साथ भी बैठेंगे और इसी वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से नयी कृषि बीमा योजना लाएंगे । हम इतना ही सदन को और पूरे देश को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी विसंगतियां हैं, वे हमारी पुरानी नीतियों का परिणाम हैं, पुराने कृतित्व का परिणाम हैं । हम कार्य कर रहे हैं । हो सकता है कि हमारे कृतित्व में भी कुछ कमी रह जाए ...**(व्यवधान)**... हमारे कृतित्व में भी कुछ कमी रह जाए, लेकिन इसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देंगे । लेकिन, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब गद्दी पर व्यापारी नहीं बैठा है । अब देश के सर्वोच्च सिंहासन पर कोई व्यापारी नहीं बैठा है । देश के सर्वोच्च सिंहासन पर गांव के गरीब किसान का बेटा बैठा है । इसका उदाहरण आपने डब्ल्यूटीओ में देखा होगा ।

**7.00 P.M.**

महोदय, जब डब्ल्यूटीओ की बैठक हुई, तो वहां क्या बात आई कि इसके पहले आश्वासन दिया गया था कि इस साल से हम सब्सिडी हटाने का विचार करेंगे । देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे । यहां की सरकार के प्रतिनिधि अड़े, झुके नहीं । अंत में मजबूर होकर दुनिया के अन्य देशों को झुकना पड़ा । तो एक गांव, गरीब, किसान और मजदूर के दर्द को समझने वाला गरीब का बेटा देश का प्रधान मंत्री होगा, तो हम गांव, गरीब, किसान को मजबूत करेंगे और शहर की सुविधाओं को गांव तक बिना पहुँचाए यह सरकार सुख और चैन से बैठने वाली नहीं है । इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । ...(**व्यवधान**)...

**श्री दिग्विजय सिंह** : माननीय मंत्री महोदय, तीन बातों पर आपने कोई चर्चा नहीं की । नम्बर एक-सस्ता धान बिक रहा है, उसके बारे में आप क्या मार्केटिंग ऑपरेशन करेंगे या नहीं? नम्बर दो-क्या आपने राइस मिल्स पर से लेवी की प्रतिशत घटाई है या नहीं? नम्बर तीन-क्या आपने राज्य सरकारों को बोनस नहीं देने का निर्देश दिया है या नहीं? इन तीन बातों पर हमें जवाब दीजिए ।

**श्री राधा मोहन सिंह** : महोदय, मैं इनको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ । ये बातें हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं, लेकिन फिर भी, ...(**व्यवधान**)... फिर भी आप मेरी बात सुनिए । ये जो धान खरीद और उस पर बोनस की बात आपने की...

**श्री दिग्विजय सिंह** : पहले धान खरीद, तब बोनस और उसके बाद लेवी ।

**श्री राधा मोहन सिंह** : वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बैठक उस मंत्रालय के साथ हुई थी । किसी ने कहा कि यहां कृषि मंत्री जी को बैठना चाहिए था । कृषि मंत्री जी फूड मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ बैठे हैं । फूड मिनिस्टर के साथ बैठक हुई थी । उसमें बहुत साफ-साफ है कि कोई भी राज्य के अन्दर, जैसे मैं बिहार का उदाहरण देता हूँ । उसको 48 लाख टन अनाज राशन में देने के लिए चाहिए । सर, पिछली बार जो वह एकदम नहीं खरीद पाया था, लेकिन इस बार 10 लाख टन खरीदा और शोर कर रहा है कि बोनस देना बन्द कर दिया । आप 48 लाख टन अनाज खरीदिए और उस पर आप एक हजार बोनस दीजिए । यह तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था । आप दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आप तो खरीदते नहीं हैं । यदि पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकार कहती है, तो फिर हम बातचीत करके रास्ता निकालेंगे, लेकिन पहले उस राज्य को उसकी जितनी आवश्यकता है, उतना तो खरीदा जाए । अगर साल भर राशन देना है, तो वह बिहार में पंजाब से क्यों जाएगा? वहां की सरकार क्यों नहीं खरीदेगी? और कहते हैं कि बोनस बंद कर दिया । आप 48 लाख टन अनाज खरीदिए, एक हजार बोनस दीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, फिर उसके बाद सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, बल्कि राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि आपके यहां जितनी जरूरत है, आप उतना खरीदिए ।

सर, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों को बुला कर हमने बैठक की थी और मैं यह बात आपको तथा पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि जो समर्थन मूल्य है, उस पर हम देश के अंदर जितना कपास है, सब खरीदेंगे । यदि किसी को क्रय केंद्र कम लगते हैं, इस बार पिछले साल से दोगुने

क्रय केंद्र हम खोल चुके हैं, इसके बाद भी अगर किसी सांसद को लगता है कि उसके क्षेत्र में क्रय केंद्र नहीं खुला है, वे लिखें और हम वहां 48 घंटे के अंदर क्रय केंद्र खुलवाएंगे। ऐसा मंत्रालय ने हमको कहा है और गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ऐसा शुरू भी किया है। आप आज का अख़बार देखिए, 60 चल रहे थे, 120 शुरू हो गये। जहां भी ऐसा किसी माननीय सदस्य को लगता है, तो कपड़ा मंत्रालय से बात करके तुरंत उनके अनुरोध पर खोला जाएगा। देखिए, सवाल यह है कि किसान की चिंता करना, एक अलग बात है, लेकिन किसान को राहत मिल जाए, इसके लिए मिल कर प्रयास करना पड़ेगा। हम सबको मिल कर प्रयास करना पड़ेगा। सरकार की ओर से इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं बरती जाएगी।

**श्रीमती रेणुका चौधरी** : आप लिक्विड फर्टीलाइजर पर सब्सिडी एक्सटेंड कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA: Mr. Minister, I asked about the Committee set up by the Government to look into the price fixation methodology. What is the status of that Committee? I would like to know whether there is any progress in the work of that Committee. How is the Government going to carry forward? Is there any review of the work of that Committee?

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, I have two clarifications. In the Budget announcement, there was a Kisan TV announcement and Rupees eight lakh crore credit support and another ₹ 100 crores for agri-technology infrastructure fund. What happened to all these things? The second clarification is about Saansad Adarsh Gram Yojana. That is a very appreciative scheme which was announced. In that scheme, is there any specific provision by the Agricultural Department? What are the provisions, what are the concessions, what are the announcements you are making in that?

**श्री बलविंदर सिंह भुंडर** : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कृषि में रिसर्च का बहुत महत्व है, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना है, वह सबसे पुरानी है, लेकिन वहां पर रिसर्च के लिए फंड की बहुत शॉर्टेज है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

दूसरी बात यह है कि लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वह चार परसेंट है, उस पर कुछ और स्टेट का खर्चा पड़ जाता है, वह 7 परसेंट के करीब पड़ जाता है। उसको कम करके दो या तीन परसेंट कीजिए। जो समय पर लोन वापस कर देता है, उसके लिए यह होना चाहिए। किसी कारण से किसान के ऊपर जो लोन है, उसका जो इंटरेस्ट है, वह सारा माफ होना चाहिए।

**प्रो0 राम गोपाल यादव** : श्रीमन्, जो लेवी का चावल 67 परसेंट खरीदा जाता था, वह घटा कर 25 परसेंट कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, असली समस्या यह है, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को धान सस्ता बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जब वहां चावल राइस मिल ओनर्स वगैरह खरीदेंगे ही नहीं, तो उनका चावल उठाया नहीं जाएगा। इस तरह से चावल कोई नहीं खरीदेगा। आपने

[प्रो0 राम गोपाल यादव]

जो यह कमी की है, इसके संबंध में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी पूछा था, लेकिन उस बात पर आप साइलेंट हैं । आप यह तो बता दीजिए कि ऐसा आपने क्यों किया?

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I will be very specific. Sir, the subject was about the agrarian crisis in the country. You must have heard the hon. Minister. It is a Short Duration Discussion. It is like an Adjournment Motion. ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want you put a question.

SHRI BHUPINDER SINGH: No, Sir.

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, don't adjourn the House. Let the Minister reply.

**श्री भूपिंदर सिंह** : सर, मेरे बोलने का मतलब यह है कि हमने आपसे निवेदन किया था । आपने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं । हमने आज हाउस में इस बात पर चर्चा की है कि आज किसान दुःखी है, वह हमारी बात सुनकर ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this ? You are speaking again on the subject!

**श्री भूपिंदर सिंह** : सर, जो "हुदहुद" आया है । ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to seek any clarification, you seek. I don't want to hear any lecture here, now.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I am seeking only clarification. The hon. Minister has not responded to our questions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Which question he has not answered? Don't waste the time of the House.

**श्री भूपिंदर सिंह** : मंत्री जी, आप कॉटन के बारे में जो बता रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आज कॉटन को 4,050 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है । ...(**व्यवधान**)... उसको आप थोड़ा बढ़ाइए । ...(**व्यवधान**)... यहां वेंकैया नायडु जी बैठे हैं । आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जहां-जहां "हुदहुद" आया है, वहां के कॉटन के लिए आप कोई सपोर्ट प्राइस दीजिए । ...(**व्यवधान**)... वहां के लिए आप कुछ पैकेज दीजिए, it has not been announced. No package has been announced today.

SHRI K. N. BALAGOPAL: Sir, I have to ask two questions.

The first one is: To resolve the agrarian crisis, the basic thing is the MSP. It should be increased. There is a formula recommended by Dr. M.S. Swaminathan

Commission. It has recommended for giving production cost plus 50 per cent. I want to know whether that is going to be implemented. Some assurance was given. So, it has to be implemented.

Secondly, due to Foot-and-Mouth disease, a lot of cattle died. There is no insurance scheme and compensation. Then, there is Bird Flu. In Kerala, around 1 million...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said that he is coming out with new insurance scheme. He said that.

SHRI K. N. BALAGOPAL: ...ducks and chicken died. I want to know whether there is any insurance. Mr. Minister, I am asking about insurance or compensation for death of cattle due to diseases. I want to know whether there is any scheme or will you come out with any scheme.

**चौधरी मुनव्वर सलीम** (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी, गांधी जी ने कहा था कि शहर बसाए हैं इंसान ने और गांव बसाए हैं भगवान ने । मध्य प्रदेश के बेतुल जिले में मुल्ताई नामक एक जगह है । वहां किसानों की जमीन बिलजब्र छीनी जा रही है । वहां आन्दोलन चल रहा है, एक हजार किसान धरने पर बैठे हैं । वहां डा. सुनीलम के नेतृत्व में आन्दोलन हो रहा है, महिलाएं जेल में हैं । मैं चाहता हूँ कि आप वहां हस्तक्षेप करके, वहां के शासन-प्रशासन से बात करके उस मसले को सुलझवाएँ, क्योंकि उससे गांव वीरान हो रहा है । ...**(समय की घंटी)**... वहां की जमीन उपजाऊ है और वहां के लोगों की यह शिकायत है कि अधिग्रहण की जो नई नीति है, उसके तहत उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है ।

† **چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش)** : سر، میں مانّئے منتری جی سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مانّئے منتری جی، گاندھی جی نے کہا تھا کہ شہر بسائے ہیں انسان نے اور گاؤں بسائے ہیں بھگوان نے۔ مدّھیہ پردیش کے بیتل ضلع میں ملتائی نامی ایک جگہ ہے۔ وہاں کسانوں کی زمین بالجبر چھینی جا رہی ہے۔ وہاں آندولن چل رہا ہے، ایک ہزار کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر سنیلم کی قیادت میں آندولن ہو رہا ہے، عورتیں جیل میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں مداخلت کرکے، وہاں کے شاسن-پرشاسن سے بات کرکے مسئلے کو سلجھوائیں، کیوں کہ اس سے گاؤں ویران ہو رہا ہے ...(وقت کی گھنٹی)... وہاں کی زمین اپجاؤ ہے اور وہاں کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ادھی-گرہن کی جو نئی نیتی ہے، اس کے تحت ان کو معاوضہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔

† Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever you can reply now, you reply. On rest of the questions, you can write to the Members concerned.

**श्री राधा मोहन सिंह :** सर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आपने बजट में जो घोषणा की, उसका क्या-क्या किया? हमने उसकी तीन-चार बातें बताई हैं, यदि वे चाहें तो मैं अभी उनको पूरा विवरण बता सकता हूँ । ...**(व्यवधान)**...

**कई माननीय सदस्य :** आप लिखकर भेज दीजिए । ...**(व्यवधान)**...

**श्री राधा मोहन सिंह :** सर, अभी किसान टीवी के विषय में पूछा गया था । मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी शीघ्र लांचिंग होगी । ...**(व्यवधान)**... जहां तक लेवी की बात है, उसके बारे में हम फूड मिनिस्ट्री से जानकारी लेकर आपको बताएंगे । ...**(व्यवधान)**... चूंकि वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने इतना बताया कि यदि किसी राज्य को एक साल में 30 लाख टन चावल राशन के लिए देना है ...**(व्यवधान)**...

**श्री दिग्विजय सिंह :** यह पॉलिसी की बात है क्या? ...**(व्यवधान)**...

**श्री राधा मोहन सिंह :** देखिए, यह भी पॉलिसी है कि आपको 30 लाख टन चावल राशन में देना है, आप उतना समर्थन मूल्य पर खरीदिए । आपको जितना बोनस देना हो, आप 300 के बदले 500 दीजिए, उस पर सरकार या मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह बताना चाह रहा था ।

दूसरा, इन्होंने एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की बात की है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम विश्वविद्यालय को फाइनेंशियल और टेक्निकल सहायता देते हैं । हम हर कृषि विश्वविद्यालय को यह देते हैं और उसमें कमी ...**(व्यवधान)**...

**चौधरी मुनव्वर सलीम :** झांसी के विश्वविद्यालय को ...**(व्यवधान)**...

† **چودھری منوّر سلیم :** جھانسی کے وشوودھیالہ کو ...(مداخلت)...

**श्री राधा मोहन सिंह :** हमारी जो नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक हम सबको देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी । इसी प्रकार से आदर्श ग्राम में कृषि के लिए क्या है? सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे कृषि की हो, जैसे मैंने देखा कि हर विधवा को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन जब आप आदर्श गांव, पंचायत गांव में जाइएगा तो आधे से ज्यादा विधवाएं पहुंचेंगी कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है । मतलब, वह जो तंत्र है, रेस्पांस नहीं करता है । तो एक सांसद और डी.एम. महीने में दो बार जाएंगे, वहां सारा प्रशासन उपस्थित रहेगा, सारी सुविधा उसको मिलेगी तो आसपास के गांवों पर भी इसका असर पड़ेगा । तो कृषि विकास की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे ब्लॉक के अंदर जिले में ATMA है, तो ATMA किसान पाठशाला करता है या सांसद आदर्श ग्राम में भी करेगा और बाकी ब्लॉक के दो-चार गांवों में करता है । ...**(व्यवधान)**...

**प्रो0 राम गोपाल यादव :** आसपास के सारे गांव नाराज हो गए, सिर्फ एक गांव ले लिया । इससे काफी एम.पीज. चुनाव हार जाएंगे, यह नोट कर लीजिए ।

---

Transliteration in Urdu Script.

**श्री राधा मोहन सिंह** : नहीं, सर । मेरी बात आप सुनिए । एक गांव के अंदर यदि कोई एम. पी. अपना सारा पैसा देगा तो निश्चित रूप से लोग नाराज होंगे । सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जो किसी गांव में ठीक से नहीं आ रही है, तो कम से कम एक गांव में तो करके दिखाइए ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE: Is there no additional cost for this? ...(*Interruptions*)...

DR. K.P. RAMALINGAM: What is the specific allocation for this? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him reply. Don't interrupt, let him reply. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, please don't interrupt. Let him reply.

**श्री राधा मोहन सिंह** : इनका विषय था कि कृषि विकास की कौन सी योजना उस आदर्श गांव में चलेगी, तो मेरी जितनी योजनाएं हैं, जो उस ब्लॉक के अंदर हैं या कृषि विज्ञान के अंदर है वे सारी योजनाएं हर सांसद आदर्श ग्राम में जाएंगी । हर सांसद को हमने अलग से एक पत्र लिखा है कि फॉर्मर्स प्रॉड्यूसर्स आर्गनाइजेशन का गठन करिए अपने उस आदर्श ग्राम और आसपास के इलाके में, और हमने उस पर नम्बर दिया है, अपने ऑफिस का नम्बर दिया है, नोडल ऑफिसर का नम्बर दिया है । तो यह हमने उसमें कहा है ।

हुदहुद और सूखा, मैंने उस समय चर्चा सिर्फ सूखे के बारे में की थी, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूंगा और दिग्विजय बाबू तो सबसे बड़े प्रशंसक रहे हैं इस मामले में कि पहली बार देश के कोई प्रधान मंत्री कश्मीर के अंदर उस घटना के बाद गए और आर्मी में जिला मुख्यालय तक गए । ऐसा आज तक नहीं हुआ । ...(**व्यवधान**)... आंध्र के अंदर देश के प्रधान मंत्री और हमारी कमेटी गई है, सब जगह से रिपोर्ट आ गई है । उसको एन.डी.आर.एफ. में रखा जाएगा और सबकी पर्याप्त सहायता की जाएगी, हुदहुद और सूखा तथा बाढ़ से जो भी ग्रस्त होगा । ...(**व्यवधान**)...

SHRI D. RAJA: Sir, I had asked a pointed question: What is the Government committee on MSP doing? ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: It is an important issue. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Raja, he is replying.

**श्री राधा मोहन सिंह** : माननीय सदस्य के दो विषय हैं, जो हम भाषण सुन रहे थे । एक तो यह है कि इस देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब है, यानी वह लैंडलैस है, उसकी हालत बहुत खराब है । मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार एक मजदूर का बेटा जब देश का प्रधान मंत्री बना है, तो उसने तय किया है, क्या तय किया है कि पांच लाख भूमिहीन किसानों का समूह बनाकर उनको रुपया देकर खेती कराई जाएगी । यह काम देश में बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है । ...(**व्यवधान**)... लैंडलैस किसान पहली बार ...(**व्यवधान**)... आपको बधाई देनी चाहिए प्रधान मंत्री जी को इस मामले में ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that is all. ...(*Interruptions*)...

Hon. Members, it is already 7.15 p.m. With the consent of the House, I am deferring the Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2014 to be taken up later. Now, can we take up Special Mentions ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't you want Special Mentions ? ...(*Interruptions*)... Okay, all right. The Special Mentions will be taken up tomorrow.

The House stands adjourned to meet on Friday, the 12th December, 2014 at 11.00 a.m.

*The House then adjourned at fifteen minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Friday, the 12th December, 2014.*